रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

Missing No. 87, 11 Missing Issues No. 87, 11

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8 1983/पौष 18, 1904
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 1983/PAUSA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1982

स्टाम्प

का० आ०. 238—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14 अगस्त 1982 के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) के पृष्ठ 2911-12 पर प्रकाशित भारत सरकार राजस्व विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 1982 के आदेश सं० 26/82 स्टाम्प फा० सं० 33/23/82-बि०क० (का०आ० 2868) का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि० को मात्र एक लाख चालीस हजार आठ सौ रुपये पच्चीस पैसे के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा ऋण पत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले एक करोड़ सत्तासी लाख सत्तर हजार दो सौ रुपये के अंकित मूल्य के बंध पत्र पर प्रभार्य है।

[सं. 37/82-स्टाम्प/फा०सं० 33/23/82-बि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 15th December, 1982

STAMPS

S.O. 238.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), and in supersession of the Order of the Government of India in the Department of Revenue No. 26/82-Stamps F. No. 33/23/82-ST (S.O. 2868), dated the 31st July, 1982, published at page 2911-12 of the Gazette of India, Part-II Section 3 Sub-section (ii), dated the 14th August, 1982, the Central Government hereby permits the Ahmedabad Manufacturing and Calico Printing Company Limited to pay consolidated stamp duty of one lakh forty thousand eight hundred thirty-one rupees and twenty-five paise only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of one crore eighty seven lakhs seventy seven thousand two hundred rupees to be issued by the said Company.

[No. 37/82-Stamps F. No. 33/23/82-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1982

आय-कर

का०आ० 239.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० 4501/फा०सं० 187/41/81-आई टी (ए० आई०) तारीख 3-3-82 में निम्नलिखित संशोधन करता है। अनुसूची की क्रम सं० 23-ञ के सामने स्तंभ 1, 2, 3 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
23-ञ पश्चिम बंगाल-XI	कलकत्ता	(1) जिला I(1), कलकत्ता। (2) जिला I(2), कलकत्ता। (3) जिला I(3), कलकत्ता। (4) जिला I(4), कलकत्ता।

यह अधिसूचना 1-9-1982 से प्रभावी होगी।

[सं० 4926/फा०सं० 187/36/82-आईटी० (ए०आई०)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 29th September, 1982

INCOME-TAX

S.O. 239.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Notification No. 4501 F. No. 187|41|81-IT (AI) dated 3-3-82 as amended from time to time. The entries under Column 1, 2, 3, against Sl. No. 23-J of the schedule shall be substituted by the following entries.

Commissioner of Income Tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
23-J West Bengal-XI	Calcutta	(1) Dist. I(1), Calcutta. (2) Dist. I(2), Calcutta. (3) Dist. I(3), Calcutta. (4) Dist. I(4), Calcutta.

This notifications shall take effect from 1-9-1982.

[NO. 4926 F. No. 187|36|82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

आय-कर

का०आ० 240.—केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "श्री वेदनारायण पेरूमल मन्दिर मुसीरी तालुक (जिला तिरुची) तमिलनाडु" को तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र वि... लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 4974 (फा०सं० 176/74/82—आ०क० (ए०आ

New Delhi, the 17th November, 1982

INCOME-TAX

S.O. 240.—In exercise of the powers conferred section (2)(b) of Section 80-G of the Income tax Act (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Vedanarayana Perumal Temple, Musiri Taluk (Tiruchi... Tamil Nadu" to be a place of public worship of, throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 4974|F. No 176|74|82-

आय-कर

का०आ० 241.—केन्द्रीय सरकार आयकर अधि... 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उ... (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मन्दिर, गोरावनहल्ली, हिन्दूपुर तालुक जिला अनंतपुर (आन्ध्र प्रदेश)" को, आन्ध्र प्रदेश राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 4971/फा० सं० 176/20क/82-आ०क० (ए०आई)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 241.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Lakshmi Narasimhaswamy Temple, Gorvanhalli, Handupur Taluk, Anantpur Distt. (Andhra Pradesh)" to be a place of public worship of renown throughout the State of Andhra Pradesh.

[No. 4971|F. No. 176|20A|82-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1982

का०आ० 242—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 11 अक्तूबर, 1982 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 725(अ) तारीख 7 अक्तूबर, 1982 में, उपपैरा (ख) के नीचे दी गई सारणी में, "दस पैसे" मद के सामने स्तम्भ "आकार और बाहरी व्यास" के नीचे "25 मिलीमीटर" के स्थान पर "26 मिलीमीटर" पढ़ें।

[फा०सं० 1/28/II/79-सिक्का]

सी०जी० पथरोज, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th December, 1982

S.O. 242.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), No. S.O. 725(E), dated the 7th October, 1982 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 11th October, 1982, in the table given below sub-paragraph (b), against item "Ten Paise", under column "Shape and outside diameter", for "25 millimetre" read "26 millimetre".

[No. F. 1/28/(II)/79-Coin]

C. G. PATHROSE, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1982

का०आ० 243.—केन्द्रीय सरकार, राज भाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय (वित्तीय कार्य विभाग) के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय को जिसके कर्मचारीवृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

भारत सरकार टकसाल, बम्बई।

[सं० ई० 11011/40/82-हि०का०क०]

पी०एल० सकरवाल, उप सचिव

New Delhi, the 16th December, 1982

S.O. 243.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following subordinate office of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

India Government Mint, Bombay

[No. E 11011/40/82-HIC]

P. L. SAKARWAL, Dy Secy

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

का० आ० 244.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम काकतिया ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से काकतिया ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन —अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान —बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची .—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन .—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार को इनमें से जो अधिक हो, होगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन .—यदि बोर्ड का अधिवेशन गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन,

उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिससे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो उस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 12-5/81-आर० आर० बी० (II)]

New Delhi, the 22nd November, 1982
(Banking Division)

S.O. 244.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kakathiya Grameena Bank (Meetings of Board) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Kakathiya Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) : The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place.

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned, or want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation :

(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary, to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.

(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and the last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein

[No. F. 12-5/81-RRB(II)]

का० आ० 245.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन.—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख का अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें; तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों का अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ क्रमांकित, अध्यक्ष अथवा अधिवेशक जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो द्वारा प्राधिकृत हो हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[फा० सं० 12-5-81 आर आर बी (III)]

S.O. 245—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hadoti Kashetriya Gramin Bank (Meeting of Board) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Hadoti Kashetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) : The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or our whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place.—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned, for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.

(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitutes quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.

(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initiated or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(2) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F.12-5/81-RRB(III)]

का० आ० 246.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम मांडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक" से मांडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या : एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन : अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची.—(1)

(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन : यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जायेगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत में बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अंतर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन को अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जाएंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 12-5/81-आर०आर०बी० (iv)]

दिनेश चन्द्र, निदेशक

S.O. 246.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mandla-Balaghat Kashtiya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976)

(b) "bank" means the Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be hold at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total number of directors or four whichever is higher

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place.—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned, for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation :

(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitutes quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business:

(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initiated or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/81-RRB(IV)]

DINESH CHANDRA, Director

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1982

का०आ० 247.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि (क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) और (ii) के उपबन्ध 25 अगस्त 1983 तक आन्ध्र बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक ये उपबन्ध इसके अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक आन्ध्र प्रदेश इन्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड तथा उड़ीसा इन्डस्ट्रियल एं टेक्नीकल कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड के नि होने पर इसलिए पाबंदी लगाते हैं कि वह, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है; और (ख) उक्त अधिनियम की धारा 1 उपधारा (3) के उपबन्ध 25 अगस्त, 1983 तक बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक ये उक्त बैंक के आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड तथा उड़ीसा इंडस्ट्रियल टेक्नीकल कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड की शेयर पर पाबंदी लगाते हैं।

[संख्या 15/34/82-बी०ओ

New Delhi, the 15th December, 1982

S.O. 247.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that (a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Andhra Bank upto 25th August, 1983 insofar as the said provisions prohibit its Chairman and Managing director from being the Director of the Andhra Pradesh Industrial Consultancy Organisation Ltd., and Orissa Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd., being companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and (b) the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply to Andhra Bank upto the 25th August, 1983 insofar as the said provisions prohibit from holding shares in the Andhra Pradesh Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd., and Orissa Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.

[No. 15/34/82-B.O. III]

का०आ० 248.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के उपखण्ड (i) और (ii) के उपबन्ध 20 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए बैंक आफ अमरीका पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक ये उपबन्ध भारत में इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी के भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड के निदेशक होने पर इसलिए पाबंदी लगाते हैं कि वह, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत एक कम्पनी है, और (ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्ध 20 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए बैंक आफ अमरीका पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक ये उपबन्ध उक्त बैंक के भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड की शेयर धारिता पर पाबंदी लगाते हैं।

[संख्या 15/30/82-बी०ओ० III]

S.O. 248.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that (a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of the said Act shall not apply to Bank of America for a period upto the 20th December, 1983 insofar as the said provisions prohibit its Chief Executive Officer in India to function as a Director on the Board of the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. being a company registered under the Companies Act 1956 (1 of 1956) and that (b) the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply to Bank of America for a period upto 20th December, 1983 insofar as the said provisions prohibit from holding shares in the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.

[No. 15/30/82-B.O.III]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

का० आ० 249.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध, पंजाब को-आपरेटिव बैंक लि०, अमृतसर पर 1 जनवरी, 1983 से 31 मार्च, 1983 तक के 3 महीनों के वास्ते अथवा उक्त बैंक में अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो पहले हो, लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/18/82-बी०ओ० III]
एन०डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 249.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) and (2) of Section 10B of the said Act, shall not apply to Punjab Co-operative Bank Ltd. Amritsar for 3 months from 1st January, 1983 to 31st March, 1983 or till the appointment of the next whole-time Chairman of that bank whichever is earlier.

[No. 15/18/82-B.O.III]
N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1982

का०आ० 250.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड की सिफारिश पर, जनवरी, 1983 में उक्त निगम द्वारा निर्गमित किए जाने वाले और पहली जनवरी, 1984 को परिपक्व होने वाले बांड पर देय ब्याज की दर को एतद्द्वारा 10% वार्षिक (दस प्रतिशत) निर्धारित करती है।

[सं० 2(22) आई० एफ० 1/82]
के०पी० पाण्डियन, अवर सचिव

New Delhi, the 17th December, 1982

S.O. 250.—In pursuance of Sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948) the Central Government, on the recommendations of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby, fixes 10 per cent (Ten per cent) per annum as the rate of interest payable on the bond to be issued by the said Corporation in January, 1983 and maturing on 1st January, 1984.

[No. 2(22)IFI/82]

K. P. PANDIAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1983

का०आ० 251.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स एस० जी० एस० इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, 26-26-24, हरबर एप्रोच रोड, विशाखापत्तनम् 530001, को निम्नलिखित मदों के धूम्रीकरण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है :—

1. तेल रहित चावल की भूसी और
2. हड्डी का चूरा खुर और सींग ।

[सं० 5(7)/82-ई० आई० एण्ड ई०पी०]

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 8th January, 1983

S.O. 251.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of one year M/s. S.G.S. India Private Limited 26-26-24, Harbour Approach Road, Visakhapatnam-530001, as an agency for the fumigation of following items :—

1. De-oiled Rice Bran; and
2. Crushed Bones, Hooves and Horns.

[No. 5(7)/82-EI&EP]

(वाणिज्य विभाग)

का०आ० 252.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पी० बी० सी० चर्म कपड़े का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1981* का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पी० बी० सी० चर्म कपड़े का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पी० बी० सी० चर्म कपड़े का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1981 में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. निरीक्षण फीस :—निर्यात कर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस का संदाय यथा निम्नलिखित किया जाएगा :—

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्कीम के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त नि. शुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से ,

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से,

(ii) उन निर्यातकर्ताओं के लिए जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के साथ लघु उद्योग विनिर्माण एककों के लिए रजिस्ट्रीकृत है, प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) के खंड (क) तथा (ख) के लिए क्रमशः 0.18 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत (पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के) की दर से।"

[6(7)/82-ई० आई० एण्ड ई० पी०]

पाद टिप्पण :—
* का. आ. 49
तारीख 3-1-1981

S.O. 252.—In exercise of powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of P.V.C. Leather Cloth (Quality Control and Inspection) Rules, 1981,* namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of P.V.C. Leather Cloth (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of P.V.C. Leather Cloth (Quality Control and Inspection) Rules, 1981, for rule 7, the following rule shall be substituted namely :—

"7. Inspection Fees.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :—

(i) (a) for exports under in process quality control scheme at the rate of 0.2 per cent of the FOB value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment;

(b) for exports under consignment Inspection at the rate of 0.4 per cent of the FOB value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment;

(ii) subject to the minimum of Rs. 20/- per consignment the rate payable under clauses (a) and (b) of sub-rule (i) shall be 0.18 per cent and 0.36 per cent (of the FOB value) respectively, for exporters who are registered as Small Scale Manufacturing Units with the concerned Governments of States/Union Territories."

[6(7)/82-EI&EP]

Footnotes :—
*S.O. 49
Dated : 3-1-1981.

का०आ० 253.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनयल फिल्म तथा चद्दरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण नियम, 1969 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनियल फिल्म तथा चद्दरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनयल फिल्म तथा चद्दरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1969* में नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. निरीक्षण फीस:—निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस का संदाय यथा निम्नलिखित किया जाएगा :—

(1) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्कीम के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से ;

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से ;

(2) उन निर्यातकर्ताओं के लिए जो राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के साथ लघु उद्योग विनिर्माण एककों के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) के खंड (क) तथा (ख) के लिए क्रमशः 0.18 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत (पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के) की दर से।"

[सं० 6 (7)/82-ई० आई० एण्ड ई० पी०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

पाद टिप्पण :—

का. आ. 457

तारीख 1-2-1969

S.O. 253.—In exercise of powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963). The Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Vinyl Film and Sheetings (Quality Control and Inspection) Rules, 1969.* namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Vinyl Film and Sheetings (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Export of Vinyl Film and Sheetings (Quality Control and Inspection) Rules, 1969 for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Inspection Fee.—Inspection Fee shall be paid by the exporter to the Agency as under:—

(i) (a) for exports under inprocess quality control scheme at the rate of 0.2 per cent of the FOB value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment;

(b) for exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4 percent of the FOB value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment,

(ii) subject to the minimum of Rs. 20/- per consignment the rate payable under clauses (a) and (b) of sub-rule (i) shall be 0.18 percent and 0.36 percent (of the FOB value) respectively for exporters who are registered as Small Scale Manufacturing Units with the concerned Governments of States/Union Territories."

[No. 6(7)/82-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

Footnotes :—
*S.O. 457
Dated : 1-2-1969.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय

मद्रास

आदेश

मद्रास, 2 सितम्बर, 1982

का०आ० 254 :—सर्वश्री सन ट्रेडिंग कम्पनी, 14, आरीयन लेन, मद्रास–600007 को रुपये, 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड/1935922/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 26-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सन ट्रेडिंग कम्पनी, 14, आरीयन लेन, मद्रास-600007 को, अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये आयात लाइसेंस संख्या पी/जेड/1935922-सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 26-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ/969/एएम/82/एयू 3]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Export)

ORDER

Madras, the 2nd September, 1982

S.O. 254.—M/s. Sun Trading Co 14-Ariyan Lane Madras-600007 were granted a Licence No. P/Z/1935922/C/XX/82/M/81 dated 26-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal

hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935922/C/XX/82/M/81 dated 26-2-82 issued to M/s. Sun Trading Co., 14-Ariyan Lane Madras-600007 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No DF/969/AM 82/AU.III]

आदेश

मद्रास, 15 अक्तूबर, 1982

का०आ० 255.—सर्वश्री चन्द्रीका स्टोर्स, 143, पुलियानतोप हाई रोड़, मद्रास-600012 को रुपये 10,000तक सूखे फलों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी-जेट-1936104/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस गलती लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये । अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी के न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री चन्द्रीका स्टोर्स, 143, पुलियांतोप हाई रोड, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-जेड-1936104/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं ।

[संख्या डी एफ/1257/ए एम० 82/एयु-III]

ORDER

Madras, the 15th October, 1982

S.O. 255.—M/s. Chandrika Stores, 143 Pulianthope High Road, Madras-600012 were granted a licence No. P/Z/1936104/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 23-9-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1936104/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Chandalika Stores, 143, Pulianthope High Road, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No DF/1257/AM 82/AU. III]

आदेश

मद्रास, 16 नवम्बर, 1982

का०आ० 256.—सर्वश्री भारती स्टोर्स, संख्या-6, मुनियप्पन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी/जेड/1936093/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये । अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी को न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री भारती स्टोर्स, संख्या-6, मुनियप्पन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च, 1682 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये जारी किये गये लाइसस संख्या पी/जैड-1936093/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी एफ/1273/ए एम० 82-एयु-III]

ORDER

Madras, the 16th November, 1982

S.O. 256.—M/s. Bharathi Stores, No. 6 Muniappan St. Madras-600001 were granted a Licence No P/Z/1936093/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936093/C/XX|82|M|81 dated 6-3-82 issued to M/s. Bharathi Stores, No. 6 Munniappan St. Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1273/AM 82/AU III]

का०आ० 257—सर्वश्री धीरज कुमार एण्ड कम्पनी, संख्या-7, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1635849/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 18-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये। अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री धीरज कुमार एण्ड कम्पनी, संख्या-7, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-600 001 को, अप्रैल-मार्च 1682 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के के लिये जारी किये लाइसेंस संख्या पी/जैड/1635849/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 18-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी एफ/869/ए एम० 82/ए यु-III]

S.O. 257.—M/s. Dhiraj Kumar & Co, No 7 Kasi Chetty Lane Madras-600001 were granted a Licence No. P|Z|1935849|C|XX|82|M|81 dt. 18-2-1982 for import of dry fruits for Rs. 10000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show case notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Import (Control) Order. 1955 hereby cancel the import licence No P/Z/1935849/C|XX|82|M|81 dt. 18-2 1982 issued to M/s. Dhiraj Kumar & Co. No 7 Kasi Chetty Lane Madras-600001 for import of dry fruits for Rs 10000 for April-March 1982 period.

[No. DF/869/AM. 82/AU. III.]

का०आ० 258.—सर्वश्री चन्दन ट्रेडर्स, संख्या-32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1635819/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 8-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये। अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री चंदन ट्रेडर्स, संख्या-32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी/जैड/1635819/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 8-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी एफ/812/ए एम० 82-ए यु-III]

S.O. 258.—M/s Chandan Traders No. 32 Kasi Chetty street Madras 600001 were granted a licence No. P/Z/1935819/C|XX|82|M 81 dt. 8-2-1982 for import of dry fruits for Rs 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1) (a) of the imports (Control) Order, 1955 here by cancel the import licence No. P/Z/1935819/C/XX|82|M|81 dt. 8-2-82 issued to M/s. Chandan Traders No. 32, Kasi Chetty Street Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10000 for April—March 1982 period

[No DF|812|AM. 82|AU. III.]

का० आ० 259.—सर्वश्री कुमारी एंटरप्राइजस, संख्या-4, नंबू नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1935818/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 8-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का

कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री करुमारी एंटरप्राइजेस, संख्या-4 तम्बु नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935818-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 8-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ-815-एएम 82-एयू 3]

S.O. 259.—M/s. Karumari Enterprises No 4 Thambu Naiken Street Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1935818/C/XX/82/M/81 dt. 8-2-1982 for import of dry fruits for Rs. 10000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the import (control) order 1955 hereby cancel the import licence no. P/Z/1935818/C/XX/82/M/81 dt. 8-2-1982 issued to M/s. Karumari Enterprises No. 4 Thambu Naicken Street Madras-1 for import of dry fruits for Rs 10000 for April—March 1982 period.

[No. DF/815/AM. 82/AU. III.]

का० आ० 260.—सर्वश्री कुशल एन्टरप्राइजेस, 90, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935780-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कुशल एंटरप्राइजेस, 90, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935780-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ-791-एएम 82-एयू 3]

S.O. 260.—M/s. Kusal Enterprises, 90, Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/1935780/C/XX/82/M/81 dt. 1-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import Licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935780/C/XX/82/M/81 dt. 1-2-82 issued to M/s, Kusal Enterprises, No. 90, Narayana Mudali Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No DG/791/AM. 82/AU III.]

का० आ० 261.—सर्वश्री शिवाजी एण्ड कंपनी, संख्या-15, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935829-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 12-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री शिवाजी एण्ड कंपनी, संख्या-15, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट,

मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935829-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 12-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता है।

[सं० डीएफ-837-ए एम 820 एयू 3]

S.O. 261.—M/s. Shivaji & Co. No 15 Krishna Iyer Street, Madras-1 were granted a licence no. P/Z/1935829/C/XX/82/M/81 dt. 12-2-1982 for import of dry fruits for Rs. 10000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-10-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955 hereby cancel the import licence no P/Z/1935829/C/XX/82/M/81 dt. 12-2-1982 issued to M/s. Shivaji & Co. No. 15 Krishna Iyer Street, Madras for import of dry fruits for Rs. 10000 for April—March 1982 period.

[No. DF/837/AM. 82/AU. III.]

का० आ० 262.—सर्वश्री सुपर सेल्स कार्पोरेशन, संख्या-11, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935846-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री सुपर सेल्स कार्पोरेशन, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935846-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ/873-एएम 82-एयू 3]

S.O. 262.—M/s. Super Sales Corporation, No. 11, Krishna Iyer St., Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935846/C/XX/82/M/81 dated 18-2-1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935846/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 issued to M/s. Super Sales Corporation, Madras-600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/873/AM. 82/AU. III]

का० आ० 263.—सर्वश्री जे एंटरप्राइजेस, 62, नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-600001 को रुपये 10000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट 1935874-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री जे एंटरप्राइजेस, 62, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये लाइसेंस संख्या पी-इजट-19 35874-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता है।

[संख्या : डीएफ-908-एएम 82-एयू 3]

S O. 263.—M/s. Jay Enterprises 62, Narayana Mudali Street, Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935874/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935874/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Joy Enterprises, 62, Narayana Mudali St. Madras 600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/908/AM. 82/AU. III]

का०आ० 264.—सर्वश्री जेनरल ट्रेडिंग कम्पनी, 26, आदियप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जैड-1935919-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 26-2-82 दिनांक जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस धारी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस का रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जेनरल ट्रेडिंग कम्पनी, 26, आदियप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जैड-1935919-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 26-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[सं० डीएफ-968-एएम-82-एयू 3]

S.O. 264.—M/s. General Trading Co., 26, Audiappa Naicken St. Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1935919/C/XX/82/M/81 dated 26-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by Fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935919/C/XX/82/M/81 dated 26-2-82 issued to M/s General Trading Co., 26, Audiappa Naicken St Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/968/AM '82/AU. III]

1116 GI/83—3

का०आ० 265.—सर्वश्री प्रभू ट्रेडर्स, संख्या-24, आदियप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जैड-1936113-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस धारी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री प्रभू ट्रेडर्स, संख्या-24, आदियप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस सं० पी-जैड-1936113-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[सं० डीएफ-1271-एएम 22-एयू 3]

S.O. 265.—M/s. Prabhu Traders No. 24, Audiappa Naicken Street, Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1936113/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936113/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Prabhu Traders No. 24 Audiappa Naicken Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1271/AM. 82/AU. III

का०आ० 266.—सर्वश्री वैसाली एण्ड कम्पनी, संख्या 62 ए, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे-फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सं० पी-जैड-1935778-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के यथास्थिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बैसाली एण्ड कम्पनी संख्या-62 ए, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जैड-193 778-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 को एतद् रद्द करता हूं।

[सं० डीएफ-790-एएम 82 एयू 3]

S.O. 266.—M/s. Vaisali and Company, No. 62/A Narayana Mudali street, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1935778/C/XX|82|M|81 dt. 1-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935778/C/XX|82|M|81 dated 1-2-82 issued to M/s. Vaisali and Company, No. 62/A-Narayana Mudali street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F. No. DF/790/AM. 82/AU. III.]

का०आ० 267.—सर्वश्री मोती सेल्स कार्पोरेशन, सं०-25, चेल्लप्प मुदली स्ट्रीट, कोसप्पेट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी-जैड-1935845-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक-18-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के यथास्थिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोती सेल्स कार्पोरेशन, संख्या-25, चेल्लप्प मुदली स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जैड-1935845-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 18-2-1982 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं।

[सं० डीएफ-872-एएम 82-एयू 3]

S.O. 267.—M/s. Moti Salts Corporation No. 25 Chellappa Mudali Sreet Kosapet Madras-12 were granted a licence no. P/Z/1935845/C/XX|82|M|81 dt. 18-2-82 for import of dry fruits for Rs. 10000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, A show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an oppoortunity for a personal hearing on 29-10-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant mean and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exrcise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955 hereby cancel the import licence no P/Z/1935845/C/XX|82|M|81 dt. 18-2-1982 issued to M/s. Moti Sales Corporation 25 Chellappa Mudali Street Madras-12 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No DF/872/AM '82/AU. III.]

का०आ० 268 —सर्वश्री मंगल ट्रेडर्स, 31, स्ट्राट्टन मुथया मुदली, स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सं० पी० जैड-1935848-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के यथास्थिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री

मंगल ट्रेडर्स, 31, स्ट्राट्टन मुथिया मुदली स्ट्रीट मद्रास-600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935848-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 18-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[सं० डी एफ-870-ए एम 82-एयू 3]

S.O. 268.—M/s. Mangal Traders 31, Strotten Muthia Mudali Street Madras-600001 were granted a licence no. P/Z/1935848/C/XX/82/M/81 dt. 18.2.1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the import (control) order 1955 hereby cancel the import licence no. P/Z/1935848/C/XX/82/M/81 dt. 18-2-1982 issued to M/s. Mangal Traders 31 Strotten Muthia Mudali Street Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1270/AM.82/AU. III]

का० आ० 269.—सर्वश्री रामदेव एन्टरप्राइजस, संख्या-59, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जैड-1935806-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर लिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी के न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रामदेव एन्टरप्राइजस, संख्या-59, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-जैड-1935806-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डी० एफ० -803-ए एम 82-एयू 3]

S.O. 269.—M/s. Ramdev Enterprises, No. 59, Narayana Mudali street, Madras-1, were granted a licence No. P/Z/1935806/C/XX/82/M/81 dt 5-2-82 for import of dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935806/C/XX/82/M/81 dt. 5-2-82 issued to M/s. Ramdev Enterprises, 59, Narayana Mudali street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/803/AM. 82/AU. III.]

का० आ० 270.—सर्वश्री रामनलाल एण्ड कम्पनी, 29, चेल्लप्प मुदली स्ट्रीट, ओट्टेरी, कोसप्पेट, मद्रास-600-012 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जैड- 1935831-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी के न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रामनलाल एण्ड कम्पनी, 29, चैल्लप्प मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-जैड 1935831-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डी एफ-847 ए एम-82-ए यू 3]

S.O. 270.—M/s. Ramanlal and Company, 29, Chellappa Mudalia Street, Madras Ottery, Kosapet, Madras-600012, were granted a licence No. P/Z/1935831/C/XX/824/M/81 dt. 16-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence had been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate Certifying their past imports which was not genuine, Show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken

to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935831/C/XX/82/M/81 dt. 16-2-82 issued to M/s. Ramanlal and Company, 29, Chellappa Mudali Street for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F. No. DF/847/AM. 82/AU. III.]

का० आ० 271.—सर्वश्री कोहीनूर सेल्स डिपो, संख्या-7, कासी चट्टी लेन, मद्रास-600 001 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-ऊँड-1935847-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी के न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कोहीनूर सेल्स डिपो, संख्या-7, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-ऊँड-1935847-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं ।

[संख्या-डी एफ 871-एएम-82-एयु 3]

S.O. 271.—M/s. Kohinoor Sales Depot, No. 7 Kasi Chetty Lane, Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935847/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past Imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Imports Licence No. P/Z/1935847/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 issued to M/s. Kohinoor Sales Depot, No. 7 Kasi Chetty Lane, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/871/AM. 82/AU. III.]

का० आ० 272.—सर्वश्री वेंकटेश्वरा ट्रेडर्स, संख्या-18, वेस्ट कलमण्डबम रोड़, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-ऊँड-1935834-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी के न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वेंकटेश्वरन ट्रेडर्स, संख्या-18, वेस्ट कलमण्डबम रोड़, रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-ऊँड-1935834-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं ।

[संख्या : डी एफ - 851-ए एम 82- ए यु 3]

S.O. 272.—M/s. Venkateswara Traders No. 18 West Kalmandapam Road Royapuram Madras-13 were granted a licence no. P/Z/1935834/C/XX/82/M/81 dt. 16-2-82 for import of dry fruits for Rs. 10000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order 1955 hereby cancel the import licence no. P/Z/1935834/C/XX/82/M/81 dt. 16-2-1982 issued to M/s. Venkateswara Traders No. 18 West Kalmandapam Road Royapuram Madras-13 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April 1981—March 1982 period.

[No. DF/851/AM. 82/AU. III.]

का० आ० 273.—सर्वश्री चम्पक एन्टरप्राइजस, संख्या-3, तम्बू नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात

लाइसेंस संख्या पी/जैड-1936103/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देता से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29·10·82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी के न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री चम्पक एन्टरप्राइजस, सं० 3, थम्बू नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-जैड/1936103/सी/एक्स-एक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डी एफ/1270/एएम. 82/ एयू. III]

S.O. 273.—M/s. Champak Enterprises No. 3, Thambu Naiken St., Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/1936103/C|XX|82|M|81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not geniune A show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936103/C|XX|82|M|81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Champak Enterprises, 3 Thambu Naicken St., Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1270/AM. 82/AU. III]

का० आ० 274.—सर्वश्री सुन्दर ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या 32 कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जैड/1935816/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 8-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं 9(1) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री सुन्दर ट्रेडिंग कम्पनी संख्या-32 कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जैड/1935816/सी/एक्स-एक्स/82/एम/81 दिनांक 8-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या. डी एफ/814/एएम-82/एयू.III]

S.O. 274.—M/s Sundar Trading Co No. 32, Kasi Chetty Street, Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/1935816/C|XX|82|M|81 dated 8th February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935816/C|XX|82|M|81 dated 8th February, 1982 issued to M/s Sundar Trading Co., No. 32 Kasi Chetty Street, Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/814/AM. 82/AU. III]

मद्रास, 22 नवम्बर, 1982

का० आ० 275.—सर्वश्री राड्रीक एम्पोरियम संख्या-4 मलयप्पन स्ट्रीट मण्णडी मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जैड/1935165/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। इस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था गया कि 30-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस

गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री सनट्राक एम्पोरियम, संख्या-4 मलयप्पा स्ट्रीट मण्णडी मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी/जैड/1935965/सी/एक्सएक्स/82/एम-81 दिनांक 1-3-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ/1020/एएम 82/एयू III]

Madras, 22nd November, 1982

ORDER

S.O. 275.—M/s Suntrak Emporium, No. 4, Malayappan St., Mannady, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935965/C|XX|82|M|81 dated 1st March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935965/C|XX|82|M|81 dated 1st March, 1982 issued to M/s. Suntrak Emporium, No. 4, Malayappan St, Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1020/AM. 82/AU. III]

का० आ० 276.—सर्वश्री भवानी सेल्स कार्पोरेशन, संख्या-59, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1936095/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री भवानी सेल्स कार्पोरेशन, संख्या 59, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 का अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी/जैड/1936095/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ/1272/एएम 82/एयू III]

S.O. 276.—M/s Bhavani Sales Corporation, No. 59, Narayana Mudali St., Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1936095/C|XX|82|M 81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1936095/C|XX|82|M|81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Bhavani Sales Corporation, No. 59, Narayana Mudali St., Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10 000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1272/AM. 82/AU. III]

का० आ० 277.—सर्वश्री राजेश्वरी स्टोर्स, 9 वेलू नाइक्कन स्ट्रीट, वेस्ट माम्बलम, मद्रास-600033 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1636075/सी/एक्सएक्स/एम/82/81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजेश्वरी स्टोर्स, 9, वेलू नाइक्कन स्ट्रीट, वेस्ट माम्बलम-मद्रास-33 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी

किये गये लाइसेंस संख्या पी/जैड 1936075/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या: डीएफ/1197/एएम. 82-एयू III]

S.O. 277.—M/s. Rajeswari Stores, 9, Velu Naicken St, West Mambalam, Madras-600033, were granted Licence No. P/Z/1936075/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936075/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s Rajeswari Stores, 9, Velu Naicken St, Madras-33, for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1197/AM. 82/AU. III]

का० आ० 278.—सर्वश्री यूनियन ट्रेडर्स, 25, आदिअप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1936094/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 6-6-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के असलीपन के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री यूनियन ट्रेडर्स, 25, आदिअप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 का, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी/जैड-1936094/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या: डीएफ/1268/एएम 82-एयू III]

S.O. 278.—M/s. Union Traders, 25, Audiappa Naicken St., Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1936094/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936094/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Union Traders, 25, Audiappa Naicken St, Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1268/AM. 82/AU. III]

का०आ० 279.—सर्वश्री जैन इम्पैक्स 5/28-सी, मलयप्पन स्ट्रीट, मण्णडी, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1935963/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के असलीपन के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्दर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जैन इम्पेक्स, 5/28-सी, मलयप्पनल स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी/जैड/1935963/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 1-3-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी०एफ०/1018/एएम. 82/एयू० 3]

S.O. 279.—M/s. Jain Impex, 5/28 C, Malayappan St, Mannady, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935963/C/XX/82/M/81 dated 1st March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby

cancel the Import Licence No. P/Z/1935963/C|XX|82|M|81 dated 1st March, 1982 issued to M/s. Jain Impex, 5/28C, Malayappan St, Madras-1, for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1018/AM. 82/AU. III]

का० आ० 280.—सर्वश्री नैनेक्स एम्पोरियम, 64, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1936122/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के असलीविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नैनेक्स एम्पोरियम, 64, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी/जैड/1936122/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं ।

[संख्या : डीएफ/1016/एएम. 82-एयु-III]

S.O. 280.—M/s. Ninex Emporium, 64, Narayana Mudali St., Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1936122/C|XX|82|M|81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936122/C|XX|82|M|81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Ninex Emporium, 64, Narayana Mudali St., Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1016/AM. 82/AU III]

का० आ० 281.—सर्वश्री भारत कुमार एण्ड कम्पनी, 34, चेल्लप्प मुदली स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1935828/सी/एक्सएक्स/82/एम/81 दिनांक 12-2-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के असलीविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री भारत कुमार एण्ड कम्पनी, 34, चेल्लप्प मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जैड/1935828/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 12-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ०/836/एएम/82/एयु-III]

S.O. 281.—M/s. Bharat Kumar & Company, 34, Chellappa Mudali Street, Madras-600012, were granted a Licence No. P/Z/1935828/C|XX|82|M|81 dated 12th February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935828/C|XX|82|M|81 dated 12-2-82 issued to M/s. Bharat Kumar & Company, 34, Chellappa Mudali Street, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/836/AM. 82/AU. III]

का० आ० 282.—सर्वश्री शिवा एम्पोरियम, संख्या-59, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/जैड/1935920/सी/एक्स एक्स/82/एम/81 दिनांक 26-2-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है ।

उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री शिवा एम्पोरियम, संख्या-59, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935920-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 26-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डी० एफ०-967-ए० एम०-82-ए० यु०-3]

S.O. 282.—M/s. Siva Emporium, No. 59, Narayana Mudali St., Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935920/C/XX/82/M/81 dated 26th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935920/C/XX/82/M/81 dated 26th February, 1982 issued to M/s. Siva Emporium, 59, Narayana Mudali Street, Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/967/AM. 82/AU. III]

का० आ० 283.—सर्वश्री डीलक्स सेल्स, कारपोरेशन, संख्या-9, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखों फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935923-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 26-2-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री डीलक्स सेल्स कारपोरेशन, संख्या-9, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935923-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 26-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं ।

[संख्या : डी० एफ०-866-ए० एम०-82-ए० यु-3]

S.O. 283.—M/s. Delux Sales Corporation, No. 9, Krishna Iyer Street, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935923/C/XX/82/M/81 dated 26th February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935923/C/XX/82/M/81 dated 26th February, 1982 issued to M/s. Delux Sales Corporation, No. 9, Krishna Iyer Street, Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/866/AM. 82/AU. III]

का० आ० 284—सर्वश्री कृष्णा स्टोर्स, 11, जुबिली रोड, वेस्ट माम्बलम, मद्रास-33 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936038-सी० एक्स० एक्स०-82 एम०-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कृष्णा स्टोर्स, 11, जुबिली रोड, मद्रास-33 को

अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इज़ट 1936038 सी० एक्स० एक्स०-82 एम०-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी० एफ०-1164-ए० एम० 82-एयू० 3]

S.O. 284.—M/s. Krishna Stores, 11, Jubilee Road, West Mambalam, Madras-33, were granted a Licence No. P/Z/1936038/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936038/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 issued to M/s. Krishna Stores, 11, Jubilee, Road, Madras-33 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1164/AM. 82/AU. III]

का० आ० 285.—सर्वश्री पार्वती स्टोर्स, 13, महादेव ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600033 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इज़ट 1936014 सी० एक्स० एक्स-82 एम०-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री पार्वती स्टोर्स, 13, महादेव ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600033 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इज़ट 1936014 सी० एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी० एफ०-1111 ए० एम०-82-एयू० 3]

S.O. 285.—M/s. Parvathi Stores, 13, Mahadeva Iyer St., Madras-600033, were granted a Licence No. P/Z/1936014/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936014/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Parvathi Stores, 13, Mahadeva Iyer St., Madras-600033 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1111/AM. 82/AU. III]

का० आ० 286.—सर्वश्री मूर्ति स्टोर्स, 11, जुबिली रोड, वेस्ट माम्बलम, मद्रास-600033 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इज़ट 1935975-सी० एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस का रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मूर्ति स्टोर्स, 11, जुबिली रोड, मद्रास-600033 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इज़ट 1935975-सी० एक्स० एक्स० 82-एम०-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी० एफ०-1073-ए० एम०-82-एयू० 3]

S.O. 286.—M/s. Murthy Stores, 11, Jubilee Road, West Mambalam, Madras-600033, were granted a Licence No. P/Z/1935975/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken

to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935975/C|XX|82|M|81 dated 2nd March, 1982 issued to M/s. Muthy Stores, 11, Jubilee Road, Madras-600033 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1073/AM. 82/AU. III]

का० आ० 287—सर्वश्री श्री राम ट्रेडर्स, 84, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इज़ट-1935964-सी०-एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 1-3-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री राम ट्रेडर्स, 84, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इज़ट 1935964-सी०-एक्स० एक्स० -82 एम०-81-दिनांक 1-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या सी० एफ०-1019 ए० एम०-82-एयु० 3]

सी०जी० फेरनान्डीज,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात

S.O. 287.—M/s. Sree Ram Traders 84, Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/1935964|C|XX|82|M|81 dated 1st March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th October, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935964/C|XX|82|M|81 dated 1st March, 1982 issued to M/s. Sree Ram Traders, 84, Narayana Mudali Street, Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1019/AM. 82/AU. III]

C. G. FERNANDEZ, Dy. Chief Controller Imports and Exports

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

का०आ० 288—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और आगे निदेश करती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	क्रम सं०	सरकारी स्थानों के प्रदेश और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं		
		खाता सं०	प्लाट सं०	क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4	5
		ग्राम दामनजोड़ी, पुलिस थाना सेमलीगुडा, जिला कोरापुट		
उपप्रबन्धक (प्रशासन)	1.	1	82	0.88
नेशनल ऐलुमिनियम	2.	1	218	1.54
कंपनी लि० नोटी-	3.	1	222	1.09
फाइड एरिया कमेटी	4.	1	451	1.09
भवन सूनाबेड़ा-	5.	2	76	0.69
763003 जिला	6.	2	213	1.11
कोरापुट, उड़ीसा	7.	2	212	0.61
	8.	3	2	1.82
	9.	3	8	1.10
	10.	3	10	0-30
	11.	3	417	2.42
	12.	3	419	1.13
	13.	4	41	8.80
	14.	4	44	0.44
	15.	4	93	1.83
	16	4	94	1.62
	17.	4	110	0.91
	18.	4	112	1.41
	19.	4	32	3.88
	20.	4	34/1	1.70
	21.	4	21	1.76
	22.	4	39	2.08
	23.	4	107	3.05
	24.	5	5	0.98
	25.	6	111	0.53
	26.	7	319	1.18

1	2	3	4	5
	27.	7	114	4.06
	28.	7	151	1.68
	29.	7	175	0.25
	30.	7	239	1.41
	31.	7	255	0.58
	32.	8	81	1.71
	33.	8	369	0.88
	34.	8	374*	1.12
	35.	8	65	3.21
	36.	8	440	1.11
	37.	9	125	1.32
	38.	72/1	441/476	0.11
	39.	9	231	2.62
	40.	9	235	1.13
	41.	10	85	1.72
	42.	10	90	0.85
	43.	10	368	0.61
	44.	10	441	1.99
	45.	11	102	0.13
	46.	11	116	1.21
	47.	11	217	1.96
	48.	11	261	2.31
	49.	12	333	0.35
	50.	12	446	0.11
	51.	12	402	0.61
	52.	12	408	1.11
	53.	13	17	7.50
	54.	13	22	2.31
	55.	13	28	0.79
	56.	13	29	0.29
	57.	13	35	3.98
	58.	13	25	1.72
	59.	13	40	4.18
	60.	13	42	3.39
	61.	13	46	0.71
	62.	13	48	1.01
	63.	13	56	2.79
	64.	13	31	1.85
	65.	13	92	2.66
	66.	13	108	4.45
	67.	13	51/471	4.82
	68.	13	47	0.68
	69.	13	22/479	1.86
	70.	14	57	1.41
	71.	15	119	2.00
	72.	15	137	1.57
	73.	15	312	2.82
	74.	16	331	0.67
	75.	17	64	2.13
	76.	17	437	1.74
	77.	17	455	3.49
	78.	17	180	1.81
	79.	17	324	3.25
	80.	18	207	0.40
	81.	18	66	1.52
	82.	18	389	1.33
	83.	18	393	0.34
	84	19	12	1.71
	85.	20	13	0.86
	86.	20	103	0.07
	87.	20	256	1.31
	88.	20	263	2.23
	89.	20	263	3.04
	90.	20	264	3.42
	91.	20	266	2.22
	92.	20	130	2.57
	93.	20	134	4.72
	94.	20	450	0.24
	95.	21	172	0.64
	96.	21	282	0.81
	97.	21	283	1.12
	98.	22	284	0.16
	99.	22	286	0.58
	100.	22	292	0.81
	101.	22	156	1.09
	102.	22	161	1.91
	103.	22	166	0.63
	104.	22	307	0.22
	105.	22	311	0 56
	106.	22	347	0.41
	107.	22	348	0.50
	108.	23	285	0.18
	109.	23	293	0.59
	110.	23	294	1.25
	111.	23	295	0.39
	112.	23	207	0.17
	113.	22	306	0.35
	114.	23	77	0.69
	115	23	79	0.70
	116	23	168	0.68
	117.	23	169	0.20
	118.	23	370	0.71
	119.	23	375	1.09
	120.	23	380	1.23
	121.	24	153	1.07
	122	24	187	2.60
	123.	24	204	1.00
	124.	24	230	2.05
	125.	24	272	2.03
	126.	24	317	0.58
	127.	24	360	1.68
	128.	24	456	3.47
	129.	25	87	0.41
	130.	25	205	0.95
	131.	25	171	0.72
	132.	25	384	1.07
	133.	25	388	1.39
	134.	26	138	1.06
	135.	26	196	0.91
	136.	26	203	0.36

1	2	3	4	5
	137.	26	229	2.76
	138.	26	233	1.41
	139.	26	248	2.33
	140.	26	277	1.60
	141.	26	159	0.42
	142.	26	325	1.56
	143.	26	337	1.39
	144.	26	338	1.40
	145.	26	349	0.76
	146.	26	351	0.64
	147.	26	355	1.89
	148.	26	60	1.40
	149.	26	124	2.20
	150.	26	126	7.88
	151.	26	132	1.41
	152.	26	154	0.73
	153.	26	194	0.28
	154.	26	258	0.69
	155.	26	322	1.00
	156.	26	250	0.84
	157.	26	352	0.80
	158.	26	123	1.48
	159.	26	329	0.46
	160.	26	242	1.31
	161.	27	364	0.89
	162.	27	372	1 12
	163.	27	385	1.42
	164.	27	386	2.81
	165.	27	394	0.28
	166.	27	396	0.77
	167.	27	398	1.03
	168.	27	405	0.98
	169.	27	404	2.28
	170.	27	406	0.75
	171.	27	299	0.39
	172.	27	361	1.07
	173.	28	143	3.20
	174.	28	246	1.42
	175.	28	449	0.51
	176.	29	301	0.23
	177.	29	330	0.16
	178.	29	426	3.72
	179.	29	427	0.42
	180.	29	439	0.55
	181.	29	447	0.81
	182.	29	448	1.14
	183.	30	19	2.16
	184.	30	26	0.59
	185.	30	27	1.05
	186.	30	49	1.72
	187.	30	52	4.23
	188.	30	98	1.88
	189.	30	14	1.91
	190.	30	20	1.21
	191.	30	45	1.78
	192.	30	95	1.44
	193.	30	104	0.98
	194.	30	105	1.82
	195.	31	23	1.80
	196.	32	113	1.13
	197.	32	117	1.82
	198.	32	121	0.66
	199.	32	150	1.17
	200.	32	162	0.20
	201.	32	201	1.52
	202.	32	232	2.41
	203.	32	254	0.64
	204.	32	304	0.21
	205.	32	309	3.14
	206.	32	310	3.09
	207.	32	100	1.96
	208.	32	335	1.07
	209.	32	397	3.40
	210.	32	59	0.86
	211.	33	302	0.35
	212.	33	332	0.79
	213.	33	334	0.42
	214.	33	399	1.70
	215.	33	400	0.94
	216.	33	62	0.82
	217.	33	401	0.51
	218.	33	442	1.31
	219.	33	444	0.22
	220.	34	226	1.42
	221.	34	234	1.06
	222.	34	249	0.88
	223.	34	268	1.53
	224.	35	208	0.55
	225.	35	225	0.41
	226.	36	24	13.00
	227.	36	30	0.41
	228.	36	33	2.37
	229.	36	50	3.38
	230.	36	53	1.23
	231.	36	83	3.99
	232.	36	106	2.60
	233.	36	36/472	1.21
	234.	36	6	1.41
	235.	36	15	2.65
	236.	36	37	0.69
	237.	36	54	1.58
	238.	36	55	1.79
	239.	36	34/2	1.92
	240.	37	4	2.47
	241.	38	7	0.36
	242.	39	181	1.70
	243.	39	188	1.44
	244.	39	195	1.08
	245.	39	228	2.37
	246.	39	326	0.81
	247.	39	328	0.78

1	2	3	4	5
	248.	39	167	0.54
	249.	40	170	0.38
	250.	40	300	0.30
	251.	40	366	0.88
	252.	40	395	0.97
	253.	40	403	0.73
	254.	40	410	1.40
	255.	41	99	2.09
	256.	41	197	0.59
	257.	41	202	1.39
	258.	41	216	9.10
	259.	41	223	1.48
	260.	41	227	2.65
	261.	41	81/475	2.65
	262.	41	250	1.76
	263.	41	321	1.89
	264.	41	391	2.06
	265.	41	425	2.79
	266.	41	458	3.48
	267.	41	136/474	0.59
	268.	42	86	1.31
	269.	42	198	1.02
	270.	42	199	2.78
	271.	43	160	0.69
	272.	43	316	3.22
	273.	43	453	7.21
	274.	34	135	2.18
	275.	43	148	1.20
	276.	43	215	5.22
	277.	43	257	2.66
	278.	43	123	2.97
	279.	43	139	1.42
	280.	43	122	1.27
	281.	44	173	0.71
	282.	54	383	0.49
	283.	44	411	2.26
	284.	44	428	0.80
	285.	44	429	1.71
	286.	44	430	0.81
	287.	44	470	6.61
	288.	44	432	1.01
	289.	44	433	0.41
	290.	44	434	0.56
	291.	44	465	0.42
	292.	44	468	7.08
	293.	44	209	0.19
	294.	44	224	0.18
	295.	44	431	1.11
	296.	44	211/477	0.69
	297.	44	63	1.18
	298.	45	9	0.52
	299.	45	61	2.70
	300.	45	69	1.35
	301.	45	72	1.60
	302.	45	147	1.55
	303.	45	152	1.51
	304.	45	259	3.20
	305.	45	291	0.15
	306.	45	342	0.46
	307.	45	353	0.71
	308.	45	354	0.88
	309.	46	11	3.50
	310.	46	74	1.00
	311.	46	275	0.64
	312.	46	279	0.46
	313.	46	280	0.74
	314.	46	363	1.18
	315.	47	1	0.17
	316.	48	267	3.40
	317.	48	327	1.08
	318.	49	273	0.43
	319.	49	274	0.93
	320.	49	381	0.66
	321.	49	421	4.25
	322.	49	422	0.21
	323.	50	183	5.23
	324.	50	186	1.96
	325.	50	245	1.01
	326.	50	270	1.09
	327.	50	278	2.35
	328.	50	305	0.32
	329.	50	435	1.55
	330.	50	436	0.93
	331.	51	303	0.10
	332.	51	438	0.72
	333.	51	443	1.48
	334.	51	461	2.02
	335.	52	67	4.48
	336.	52	127	3.00
	337.	52	131	4.31
	338.	52	174	1.01
	339.	52	243	1.08
	340.	52	289	2.02
	341.	52	358	1.78
	342.	52	71	1.90
	343.	53	365	3.05
	344.	53	367	2.09
	345.	54	415	0.66
	346.	55	251	1.65
	347.	55	265	1.88
	348.	55	454	2.52
	349.	56	276	0.23
	350.	56	462	1.98
	351.	57	101	0.11
	352.	57	118	1.41
	353.	57	220	1.40
	354.	57	260	0.81
	355.	57	313	2.88
	356.	57	314	0.96
	357.	57	318	0.51

1	2	3	4	5
	358.	58	58	0.71
	359.	58	211	1.70
	360.	59	3	0.41
	361.	59	206	0.92
	362.	60	16	10.00
	363.	61	133	3.03
	364.	61	144	1.83
	365.	61	184	0.81
	366.	61	240	1.30
	367.	61	296	0.39
	368.	61	336	1.79
	369	61	339	4.63
	370	61	341	2.67
	371.	61	164	1.79
	372.	62	80	1.71
	373.	62	371	0.66
	374.	62	378	0.62
	375.	63	219	1.86
	376.	63	238	1.93
	377.	63	459	4.13
	378.	63	460	5.37
	379.	64	356	1.88
	380.	64	362	2.75
	381.	65	129	4.11
	382.	65	145	2.72
	383.	66	73	0.69
	384.	66	176	1.77
	385.	66	177	0.98
	386.	66	179	2.69
	387.	66	290	6.38
	388.	66	344	0.44
	389.	66	346	0.34
	390.	66	452	0.91
	391.	66	241	22.50
	392.	66	288	0.33
	393.	66	343	0.44
	394.	66	345	0.63
	395.	67	75	0.80
	396.	67	373	0.80
	397.	67	78	0.68
	398.	67	379	0.82
	399.	68	96	1.88
	400.	68	97	1.21
	401.	62	115	1.62
	402.	62	155	0.59
	403.	68	163/1	1.29
	404.	68	178	1.74
	405.	68	182	0.43
	406	68	193	0.97
	407.	68	221	1.03
	408.	68	247	0.82
	409.	68	252	0.50
	410.	68	269	1.54
	411.	72/4	323	0.80
	412.	72/6	340	2.09
	413.	68	392	1.92
	414.	68	413	1.14
	415	68	423	2.63
	416.	68	457	2.38
	417.	68	464	0.40
	418.	68	70	0 89
	419.	69	214	1.71
	420	69	287	0.19
	421.	69	296	0.92
	422.	69	376	1.71
	423.	72/5	387	0.64
	424.	69	463	0.60
	425.	69	465	0.58
	426.	69	467	0.93
	427.	69	469	2.58
	428.	69	108/473	0.39
	429.	70	68	1.58
	430.	70	84	0.93
	431.	70	120	1.41
	432.	70	146	0.60
	433.	70	157	1.63
	434.	70	244	1.25
	435.	70	315	2.38
	436.	70	357	2.68
	437.	70	381	0.06
	438.	71	89	0.69
	439.	71	377	1.35
	440.	71	382	1.82
	441.	71	390	1.36
	442.	71	407	0.48
	443.	71	416	2.42
	444.	71	445	0.31
	445.	72	414	3.32
	446.	72	418	0.48
	447.	72/3	200	0.84
	448.	73	253	0.28
	449.	73	140	0.72
	450.	73	142	1.11
	451.	73	82/481	0.09
	452.	74	359	35.90
	453.	74	149	0.11
	454.	74	158	60.90
	455.	74	185	10.00
	456.	74	237	14.85
	457.	74	424	25.24
	458.	74	308	0 47
	459.	74	420	1.41
	460.	74	18	0.82
	461.	74	38	2.45
	462.	74	43	3.97
	463.	74	51	1.21
	464.	74	165	0.31
	465.	75	210	1.38

1	2	3	4	5
	466.	75	192	1.08
	467.	76	91	0.73
	468.	76	141	0.66
	469.	77	271	1.28
	470.	77	83	50.00
	471.	77	109	14.50
	472.	77	189	2.77
	473.	77	190	0.89
	474.	77	236	10.00
	475.	77	409	11.60
	476.	77	412	4.72
	477.	77	209/480	0.36
ग्राम बा रंगापुट पुलिस थाना सेमलीगुडा जिला कोरापुट				
	1.	1	4	2.51
	2.	1	6	1.90
	3.	1	35	0.37
	4.	1	31	0.20
	5.	1	75	1.65
	6.	1	124	0.21
	7.	1	150	0.30
	8.	1	152	0.16
	9.	2	121	0.27
	10.	2	170	0.43
	11.	3	16	2.49
	12.	3	40	0.60
	13.	3	72	2.00
	14.	3	140	0.21
	15.	3	153	0.20
	16.	4	130	0.11
	17.	5	5	1.07
	18.	5	30	0.29
	19.	5	36	2.35
	20.	5	47	0.77
	21.	5	65	1.20
	22.	5	68	1.32
	23.	5	74	0.68
	24.	5	100	0.09
	25.	5	113	0.29
	26.	5	115	0.08
	27.	5	137	0.29
	28.	5	143	0.19
	29.	5	139	0.29
	30.	6	112	0.36
	31.	7	7	3.39
	32.	7	8	1.30
	33.	7	13	0.82
	34.	7	25	1.66
	35.	7	116	0.20
	36.	7	139	0.29
	37.	7	142	0.17
	38.	7	158	0.18
	39.	8	173	0.14
	40.	9	208	0.98
	41.	9	180	0.28
	42.	10	93	0.41
	43.	11	86	0.25
	44.	12	10	1.44
	45.	12	39	2.94
	46.	12	61	0.08
	47.	12	63	1.37
	48.	12	123	0.32
	49.	12	149	0.30
	50.	12	155	0.20
	51.	13	111	0.31
	52.	13	136	0.17
	53.	14	9	0.77
	54.	14	15	0.98
	55.	14	18	1.58
	56.	14	24	2.47
	57.	14	52	0.40
	58.	14	58	0.70
	59.	14	62	0.99
	60.	14	77	0.79
	61.	14	125	0.32
	62.	14	133	0.11
	63.	14	145	0.19
	64.	14	156	0.20
	65.	14	164	0.41
	66.	15	53	0.33
	67.	15	119	0.12
	68.	15	174	0.43
	69.	15	131	0.37
	70.	16	85	0.26
	71.	17	19	2.09
	72.	17	20	0.42
	73.	17	26	0.18
	74.	17	46	2.69
	75.	17	79	1.18
	76.	17	92	0.33
	77.	17	122	0.31
	78.	17	134	0.07
	79.	17	151	0.32
	80.	17	157	0.19
	81.	17	44	1.90
	82.	18	99	0.19
	83.	18	107	0.30
	84.	18	117	0.17
	85.	18	118	0.26
	86.	19	83	0.12
	87.	20	88	0.96
	88.	21	11	1.10
	89.	21	17	1.89
	90.	21	33	0.26
	91.	21	34	0.27
	92.	21	38	2.02
	93.	21	45	1.33
	94.	21	54	0.89
	95.	21	70	1.27
	96.	21	71	1.19
	97.	21	73	1.77

1	2	3	4	5
	98	21	96	2.80
	99	21	101	0.15
	100	21	104	0.19
	101	21	132	0.35
	102	21	136	0.34
	103	21	138	0.32
	104	21	141	0.17
	105	21	146	0.30
	106	21	147	0.24
	107	21	177	1.70
	108	22	55	0.45
	109	22	57	0.70
	110	22	128	0.21
	111	22	129	0.33
	112	22	163	0.68
	113	22	176	0.94
	114	23	91	0.90
	115	24	90	1.11
	116	25	3	2.26
	117	25	14	0.68
	118	25	21	1.40
	119	25	22	0.80
	120	25	23	1.37
	121	25	27	1.92
	122	25	28	2.56
	123	25	29	0.28
	124	25	49	0.78
	125	25	50	0.37
	126	25	59	0.71
	127	25	64	1.11
	128	25	66	1.63
	129	25	67	1.57
	130	25	69	1.07
	131	25	76	3.52
	132	25	105	0.06
	133	25	114	0.25
	134	25	136	0.46
	135	25	144	0.19
	136	25	148	0.24
	137	25	154	0.34
	138	25	30/181	0.24
	139	25	160	0.20
	140	25	166	0.58
	141	26	56	0.72
	142	26	102	0.08
	143	26	103	0.46
	144	26	109	0.20
	145	26	110	0.44
	146	26	127	0.20
	147	26	167	0.31
	148	26	168	0.11
	149	26	169	0.22
	150	26	171	0.37
	151	26	175	0.78
	152	27	42	2.01
	153	28	97	1.50
	154	29	94	3.21
	155	30	120	0.38
	156	30	162	0.61
	157	30	179	1.43
	158	31	87	1.60
	159	31/1	37	0.04
	160	31/1	95	0.42
	161	31/1	89	0.24
	162	31/1	161	0.44
	163	31/1	165	0.19

ग्राम धम्बागन पुलिस थाना सैमलीगुडा जिला कोरापुट

क्र०सं०	खाता सं०	प्लाट सं०	क्षेत्र (एकड़)	सीमा
1	2	3	4	5
1	1	785	2.34	उ० बैंगाइस गोडा द० मनू गोडा
2	1	789	1.04	उ० पहाडा द० धामूगोडा
3	1	802	1.28	उ० मुलीजानी द० गुरमूकेटा
4	1	796/967	2.84	उ० धानूगोडा द० वामन जोडी गांव
5	2	866	2.00	उ० पहाडा द० बैंगा गुपमी
6	5	901	0.90	उ० स्वयं द० मुलियाजानी
7	5	902	0.45	उ० मगतिया भोई द० स्वयं
8	10	962	1.07	उ० कुटूभोई द० पाडिया
9	10	852	1.21	उ० गोटिया भोई द० बांकुलू
10	10	887	0.74	उ० सिगुबुडिया द० धारा चालन
11	15	884	3.25	उ० पहाडा द० नाला
12	15	480	0.86	उ० डोराचालन द० डोराचालन
13	16	837	1.00	उ० कुकूबेडिया द० डोरा चालन
14	13	851	0.87	उ० मंगीतीभोई द० कैसाका भोई
15	16	896	0.30	उ० डींगरूभोई द० वामनजोडी गांव
16	16	830	0.14	उ० पटीटा द० पटीटा
17	17	867	1.29	उ० बैंगामुक्ली द० बोंकूह चालन
18	19	871	3.44	उ० बाडूभोई द० पैतुभोई
19	20	922	0.63	उ० मुलियाभोई द० बुरजा भोई
20	25	872	2.03	उ० गोंडाभोई द० मुलिया-भोई
21	26	957	0.72	उ० मगतियाभोई द० गोंडा-भोई
22	26	910	0.24	उ० पटीटा द० पाटिया
23	26	965	0.33	उ० स्वयं द० स्वयं
24	27	775	0.99	उ० स्वयं द० वामनजोडी
25	30	791	1.58	उ० मगनिया गोडा द० स्वयं
26	30	792	0.91	उ० स्वयं द० नाला
27	30	793	1.75	उ० बनगाती गोडा द० स्वयं

1	2	3	4	5
28	30	797	1.48	उ० मुकूभोई द० बानूभोई
29	30	803	0.63	उ० अलकागोडा द० बानू-गोडा
30	32	895	2.42	उ० बामूगोडा द० गंगा-धरभोई
31	32	912	0.30	उ० पटीटा द० पटीटा
32	32	915	0.82	उ० स्वयं द० दामनजोडी
33	34	913	0.22	उ० पाडिया द० पटीटा
34	34	919	1.26	उ० दारामुकुली द० दामन-जोडी
35	40	860	1.15	उ० बंडाका चालन द० गंगाधर माझी
36	40	869	1.86	उ० बांदकूचालन द० मुरूआभोई
37	40	888	1.38	उ० केसबाभाई द० बानू-भोई
38	40	823	0.90	उ० गुरजूडामी द० पडिया
39	40	546	0.85	उ० स्वयं द० पहाडा
40	41	897	0.11	
41	41	829	0.15	उ० पटीटा द० पटिया
42	42	854	1.69	उ० बांदकूचालन द० दामन जोडी गांव
43	42	891	1.14	उ० जामूभोई द० स्वयं
44	42	892	2.19	उ० स्वयं द० स्वयं
45	42	893	2.25	उ० स्वयं द० स्वयं
46	42	894	1.31	उ० स्वयं द० दामनजोडी गांव
47	42	929	4.15	उ० पहाडा द० नाला
48	42	935	0.84	उ० मुलियाजानी द० गोंडाभोई
49	42	940	0.41	
50	42	548	0.85	उ० नाला द० जयरामभोई
51	42	918	1.60	उ० स्वयं द० टोम्बूभोई
52	44	890	3.31	उ० डोंगाचालन द० डोंगा मुकुली
53	46	834	0.05	उ० बाराजु डामी द० गंगाधर माझी
54	48	783	1.65	उ० अलकागोडा द० दामनजोडी गांव
55	48	788	0.66	उ० अलका गोडा द० लधियाजानी
56	48	796	1.74	उ० बानू गोडा द० अलका गोडा
57	48	799	3.67	उ० मुकुरू भोई द० मलियाजानी
58	48	805	0.63	उ० बंगोटी गोडा द० लोदिया जानी
59	48	807	2.01	उ० स्वयं द० दामनजोडी
60	50	758	1.76	उ० रेली भोई द० रैली भो
61	50	760	1.26	उ० रेली भोई द० रेलीभोई
62	50	761	0.97	उ० रेली भोई द० रेली भोई
63	50	816	1.28	उ० मुलिया जानी द० नाला
64	50	939	0.48	उ० डोंगामुकुली द० मुकुभोई
65	52	817	1.26	उ० स्वयं द० नाला
66	52	818	1.48	उ० पहाडा द० स्वयं
67	52	846	0.38	उ० नाला द० पहाडा
68	52	858	1.11	उ० पहाडा द० माधु चालन
69	52	853	0.80	उ० केसबाभोई द० डोंगामुकुली
70	52	868	1.59	उ० नाला द० डोंगाचालन
71	52	900	2.25	उ० नाला द० मलिया जानी
72	52	839	1.73	उ० रमजू जानी द० नाला
73	52	957	1.92	उ० पहाडा द० पाडिया
74	54	876	2.02	उ० मगनियाभोई द० मुकुरूभोई
75	54	880	2.26	उ० नाला द० मुकुराभोई
76	54	934	1.82	उ० डोंगा मुकुली द० रेली भोई
77	54	958	1.48	उ० नैगनभोई द० लाडाभोई
78	56	786	2.19	उ० लोडिया जानी द० अलका गोडा
79	56	790	1.64	उ० पहाडा द० जामूगोडा
80	56	801	0.20	उ० अलका गोडा द० हानू गोडा
81	56	828	0.98	उ० बाराजुडामी द० मुकरू भोई
82	58	849	1.30	उ० नाला द० मगोनिया भोई
83	58	886	0.54	उ० पहाडा द० केसबाभाई
84	60	768	4.21	उ० पहाडा द० स्वयं
85	60	769	2.30	उ० स्वयं द० स्वयं
86	60	770	2.13	उ० स्वयं द० स्वयं
87	60	771	1.99	उ० स्वयं द० गोचर
88	60	772/1	4.70	उ० स्वयं द० पडिया जानी
89	60	776	0.74	उ० गोचर द० स्वयं
90	60	781	2.04	उ० स्वयं द० गांव दामनजोडी
91	60	782	1.79	उ० गोचर द० स्वयं
92	61	777	0.89	उ० गोचर द० दामनजोडी
93	61	778	0.81	उ० गोचर द० दामनजोडी
94	66	822	0.50	उ० डोंगा चालन द० पडिया
95	66	827	1.59	उ० बस्ता जानी द० गंगाधर माझी
96	66	832	2.04	उ० पडिया द० पडिया
97	66	833	2.81	उ० मुरूशू जानी द० स्वयं
98	66	845	1.30	उ० नाला द० पहाडा
99	66	693	1.51	उ० माधमा द० स्वयं
100	66	692	1.24	उ० स्वयं द० अनाबादी
101	66	691	1.00	उ० स्वयं द० पडिया
102	66	838	0.72	उ० बालडुकू चालन द० बालडुकू भोई
103	66	820	2.10	उ० हेमोगुडिया द० नाला
104	66	690	0.05	उ० लोदिया जानी द० स्वयं
105	70	870	1.35	उ० डोंगा चालन द० गोडाभोई
106	70	874	2.14	उ० मुनियाभोई द० मगोतिया भोई
107	71	923	0.87	उ० गोंडा भोई द० दामनजोडी
108	72	866	1.03	उ० बीडाभोई द० गंगाधर बुडिया
109	72	905	2.58	उ० लाडाभोई द० मगनाभोई
110	72	907	1.54	उ० मगनाभोई द० पडिया

1	2	3	4	5
111	78	956	1 13	उ० मोंगाभाई द० चैतनभाई द०
112	74	955	2 24	उ० मागलाभाई द० मगुलिया भाई
113	82	780	2 21	उ० पडिया द० दामनजाडा भूमि
114	82	800	2 81	श्याम गाडा द० अनका गाडा
115	82	813	1 88	उ० पहाडा द० हमागुडिया
116	82	867	1 29	
117	90	936	1 26	उ० पाडया द० डाग मडरी
118	90	703	0 60	उ० मुलिया जानी द० बुरुजु डामी
119	84	811	3 40	उ० पहाडा द० नाम्या
120	84	873	1 71	उ० चैतनभाई द० बुरुजी भाई
121	85	909	0 37	उ० पाडया द० पाडया
122	87	914	0 20	उ० पटोटा द० पटाटा
123	87	920	0 19	उ० मुलिया जानी द० डामनजाडा
124	80	960	0 74	उ० डुंड भाई द० डुड भाई
125	80	906	2 60	उ० नाडाभाई द० डैगा मडुमा
126	88	757	1 37	उ० बाना भाई द० बाना भाई
127	83	759	1 14	
128	85	742	1 76	उ० बाना भाई द० पहाडा
129	88	884	3 47	उ० पगाड द० नाम्या
130	89	547	3 10	उ० बाना भाई द० पहाडा
131	90	842	0 06	उ० नाम्या द० नाम्या
132	90	787	9 10	उ० मुलिया जानी द० पाडिया
133	90	794	1 20	उ० बागमिया गाडा द० नाला
134	90	806	1 25	उ० धानू गाडा द० दामनजाडा गाव
135	90	809	0 93	उ० पहाडा द० पहाडा
136	90	844	1 05	उ० नाला द० पहाडा
137	90	545	3 14	उ० बाला भाई द० पहाडा
138	90	863	2 06	उ० पहाडा द० माडाभाई
139	92	903	2 67	उ० मुकुन्द भाई द० मागुडू भाई
140	92	904	5 78	उ० मुकुन्द भाई द० बेगा मुडुली
141	92	969	1 23	उ० बेडा भाई द० मागुडू भाई
142	97	705	2 66	उ० पहाडा द० पाडिया
143	97	877	1 50	उ० बोडा भाई द० लडा भाई
144	97	978	1 52	उ० गाडा भाई द० माडाभाई
145	97	964	0 96	उ० कुरुतुना द० कमनभाई
146	97	938	0 81	उ० बाना भाई द० पाडिया
147	79	924	0 57	उ० मुलिया जानी द० बुरुजु भाई
148	99	812		उ० मुलिया भाई द० नाला
149	93	826	1 50	उ० पाडया द० बुरुज जानी
150	101/1	772/2	5 30	उ० बिनजू द० बिनजू
151	101/1	773	0 21	उ० सुनाधर चालन द० स्वयं
152		814	1 50	उ० गगाधर मजही द० गागया जानी
153		847	3 48	उ० नाम्या द० नाम्या
154	101/1	927	2 68	उ० पहाडा द० पगुलिया
155	101/1	928	3 84	
156	101/1	779	1 15	उ० मुलिया जानी द० मुलिया जानी
157	101/2	774	0 74	उ० स्वयं द० पाडुकू जाना
158	101/2	815	0 97	उ० मुलिया जानी द० नाला
159	101/2	864	2 39	
160	101/6	831	0 39	उ० बुरुजु जानी द० बुरुजी जानी
161	101/12	704	0 20	उ० पहाडा द० निडिया जाना और अन्य
162	101/13	908	1 36	उ० मात्री भानरा और अन्य द० डम्बरी भाई और अन्य
163	101/12	911	0 73	उ० दामनजाडी गाव द० डांगुम भाई
164	101/33	926	0 10	उ० प्रताप चालन द० सुकुरा भाई और अन्य
165	101/33	930	0 94	उ० गुनामुडुली और अन्य द० प्रताप चालन
166	101/44	989	1 56	उ० मुलिया जाना द० दामनजाडी गाव
167	101/44	899	0 88	उ० योडुकू चालन द० मुलियाजानी और अन्य
168	101/44	916	0 61	उ० डागुल्या भाई द० मोमतीपाडा
169	101/44	917	0 47	उ० दीरा मुडुली द० डागुरिया भाई
170	101/44	921	0 54	उ० मुलिया जानी द० दामनजाडा
171	101/44	925	0 92	उ० मुलिया जानी द० दामनजाडी
172	37	932	0 79	उ० बाया भाई द० बागाभाई
173	35	961	1 20	उ० मगालू भाई द० केशवा भाई
174	6	841	0 81	उ० पहाडा द० पहाडा
175	15	819	0 71	उ० पाडिया द० बडुकू चालन
176	78	850	1 96	उ० नाला द० गोटिया भाई
177	78	875	3 72	उ० मुरुजू भाई द० बोडा भाई
178	78	879	1 32	उ० नाम्या द० बडुकू चालन

गांव—जपापाडर पुलिस थाना कोरापुट जिला कोरापुट

क्रम सं०	खाता सं०	प्लाट सं०	अर्जित क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4
1	1		0 97
2.	1	51	2 35

1	2	3	4
3	1	53	3.30
4	1	54	1.04
5	1	82	0.98
6	1	95	1.48
7	1	111	0.91
8	1	180	0.32
9	1	181	3.14
10	2	85	0.37
11	2	96	1.05
12	3	9	3.21
13	3	19	2.68
14	3	25	1.63
15	3	58	1.18
16	3	122	2.73
17	3	169	8.00
18	3	178	0.94
19	3	183	2.93
20	4	153	0.64
21	5	156	0.31
22	6	24	0.76
23	6	48	2.99
24	6	87	0.93
25	6	104	0.23
26	6	112	2.30
27	6	118	2.60
28	6	138	0.31
29	6	151	3.52
30	6	166	2.29
31	6	173	0.96
32	6	177	0.93
33	6	197	1.32
34	6	201	1.75
35	6	235	3.72
36	7	94	0.21
37	7	239	0.88
38	8	234	0.62
39	9	29	1.83
40	9	38	1.16
41	9	60	3.56
42	9	115	0.58
43	9	193	1.86
44	9	194	3.46
45	9	208	5.13
46	9	213	2.20
47	9	121/249	1.41
48	10	207	0.08
49	11	11	0.77
50	11	30	2.09
51	11	80	1.75
52	11	83	0.98
53	11	120	3.77
54	11	171	2.03
55	11	186	3.04
56	11	187	3.04
57	11	190	1.30
58	11	192	1.89
59	11	202	1.57
60	11	238	4.98
61	11	241	1.67
62	12	135	0.31
63	13	204	2.54
64	14	5	0.60
65	14	6	3.38
66	14	15	1.07
67	14	20	3.45
68	14	22	3.21
69	14	45	4.72
70	14	64	4.28
71	14	65	3.55
72	14	67	2.28
73	14	68	3.63
74	14	73	0.79
75	14	81	1.35
76	14	114	0.81
77	14	117	5.19
78	14	126	1.58
79	14	128	1.80
80	14	142	0.67
81	14	149	5.05
82	15	88	1.21
83	15	84	0.35
84	15	90	0.25
85	15	147	0.56
86	15	150	0.74
87	15	152	0.42
88	15	179	0.23
89	15	205	0.41
90	16	44	2.43
91	16	171	1.64
92	17	49	4.18
93	17	188	3.52
94	17	200	3.56
95	17	214	3.40
96	17	218	1.63
97	18	7	6.31
98	18	8	2.34
99	18	12	2.05
100	18	13	3.07
101	18	28	5.12
102	18	40	3.38
103	18	59	4.01
104	18	62	4.99
105	18	74	0.75
106	18	76	0.45
107	18	92	0.78
108	18	106	0.61
109	18	116	2.08
110	18	125	3.94
111	18	146	3.92
112	18	196	4.92

1	2	3	4	5
	113	19	79	0.35
	114	19	154	0.23
	115	19	155	0.50
	116	19	77	1.34
	117	20	17	0.21
	118	20	21	5.71
	119	20	27	1.47
	120	20	31	1.48
	121	20	33	0.84
	122	20	35	5.70
	123	20	37	2.23
	124	20	41	3.65
	125	20	43	2.49
	126	20	63	1.58
	127	20	72	2.97
	128	20	88	1.21
	129	20	99	0.65
	130	20	100	0.47
	131	20	101	0.46
	132	20	102	1.59
	133	20	105	0.33
	134	20	107	0.40
	135	20	109	0.50
	136	20	110	1.20
	137	20	121	1.34
	138	20	123	3.78
	139	20	124	2.40
	140	20	129	1.96
	141	20	132	2.15
	142	20	136	4.32
	143	20	140	5.84
	144	20	141	1.10
	145	20	144	7.15
	146	20	148	2.61
	147	20	160	2.50
	148	20	162	2.56
	149	20	163	4.12
	150	20	165	11.55
	151	20	168	6.30
	152	20	172	2.55
	153	20	181	2.92
	154	20	191	1.[illegible]7
	155	20	199	1.03
	156	20	203	2.49
	157	20	210	0.58
	158	20	215	3.50
	159	20	220	3.11
	160	20	221	2.58
	161	20	222	4.01
	162	20	225	[illegible].51
	163	20	227	7.06
	164	20	228	6.19
	165	20	229	2.38
	166	20	230	[illegible]
	167	20	24[illegible]	[illegible]
	168	20	1[illegible]1/248	0.[illegible]9
	169	20	[illegible]6	0.19
	170	20	97	0.27
	171	20	157	1.09
	172	20	232	0.80
	173	20	233	0.52
	174	20	236	2.06
	175	20	237	0.56
	176	20	240	0.40
	177	20	244	1.06
	178	20	245	0.21
	179	20	246	2.40

गांव डुमुरगुडा पुलिस थाना सेमलीगुडा जिला कोरापुट

	क्रम सं०	खाता सं०	प्लाट सं०	क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4	5
	1	1	4	0.08
	2	2	87	0.70
	3	2	37/3	1.03
	4	2	10	3.76
	5	2	54	1.84
	6	2	22	1.19
	7	2	24	3.68
	8	2	47	1.45
	9	2	41	0.93
	10	2	23	3.84
	11	3	79	0.36
	12	3	34	1.58
	13	3	78	3.91
	14	3	84	0.28
	15	3	5/2	1.53
	16	3	27/1	6.96
	17	3	80/2	0.51
	18	3	80/3	0.53
	19	4	27/4	6.09
	20	4	3	3.72
	21	4	5/1	4.19
	22	4	17	17.05
	23	4	[illegible]	1.09
	24	4	1	1.63
	25	5	48	0.91
	26	5	72	0.30
	27	5	9	4.41
	28	5	[illegible]	2.75
	29	5	28	2.04
	30	5	33	3.35
	31	5	55	3.55
	32	5	71	3.82
	33	5	77	0.30
	34	6	49	0.84
	35	6	31	4.98
	36	6	69	1.30

1	2	3	4	5
	37	7	80/1	1.06
	38	7	83	2.36
	39	7	83	2.45
	40	7	13	7.65
	41	8	55	0.92
	42	8	6	1.81
	43	8	15	6.60
	44	8	16	3.00
	45	9	40	0.31
	46	9	2	3.70
	47	9	30	4.39
	48	9	35	1.66
	49	9	45	0.51
	50	9	56	1.81
	51	9	63	2.53
	52	9	27/5	2.65
	53	10	76	0.76
	54	10	42	0.65
	55	10	9	1.16
	56	10	29	1.73
	57	10	38	2.25
	58	10	70	1.49
	59	15/1	61	4.06
	60	11	39	1.40
	61	11	50	0.38
	62	11	14	4.08
	63	11	20	2.82
	64	11	36	0.67
	65	11	37	1.18
	66	11	62	2.14
	67	12	68	0.29
	68	12	73	2.28
	69	12	74	0.91
	70	13	46	0.27
	71	13	8	3.83
	72	13	12	0.86
	73	13	51	1.16
	74	13	52	1.58
	75	13	60	2.87
	76	13	53	2.27
	77	14	44	0.32
	78	14	86	0.77
	79	14	27/2	10.02
	80	14	25	2.98
	81	14	26	2.62
	82	14	54/2	1.26
	83	15	69	1.30

गांव सुगरीगुडा पुलिस थाना कोरापुट जिला कोरपुट

क्रम सं०	खाता सं०	प्लाट सं०	क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4	5
	1	1	38	1.55
	2	1	118	1.49
	3	1	50	0.18
	4	1	71	3.01
	5	1	100	0.24
	6	1	110	2.39
	7	1	35	2.23
	8	1	39	3.37
	9	1	183	0.62
	10	2	96	2.21
	11	2	104	0.11
	12	2	171	0.21
	13	2	175	0.41
	14	3	25	1.51
	15	3	26	0.08
	16	3	27	2.96
	17	3	29	1.19
	18	3	33	5.11
	19	3	34	3.84
	20	3	54	0.42
	21	3	63	6.25
	22	3	94	0.79
	23	3	121	2.14
	24	3	144	0.23
	25	3	145	5.59
	26	3	187	1.22
	27	3	158	0.96
	28	4	45	0.39
	29	4	178	0.89
	30.	4	182	0.42
	31.	4	188	1.00
	32.	4	189	0.39
	33	4	184	1.88
	34.	5	2	0.79
	35.	5	8	1.57
	36.	5	12	4.47
	37.	5	88	0.15
	38.	5	89	1.33
	39.	5	90	5.02
	40.	5	114	0.83
	41.	5	125	6.92
	42.	5	126	1.69
	43.	5	127	0.89
	44.	5	131	0.24
	45.	5	134	1.90
	46.	5	152	1.39
	47.	5	156	0.08
	48.	5	161	0.15
	49.	5	166	0.60
	50.	5	135/195	0.64
	51.	5	138	2.18
	52.	5	112/200	2.89
	53	5	139	6.03
	54.	5	159	0.12
	55.	5	168	0.60
	56.	5	4	1.56
	57.	5	73	2.31

1	2	3	4	5
	58	5	75	4 11
	59	5	149	1 13
	60	5	157	0 11
	61	5	162	0 14
	62	5	6	1 03
	63	5	20	2 47
	64	5	22	2 13
	65	5	30	1 46
	66	5	31	2 41
	67	5	68	2 22
	68	5	76	1 32
	69	5	140	1 70
	70	5	141	1 44
	73	5	150	0 19
	72	5	154	0 20
	73	5	164	0 32
	74	5	164	0 19
	75	5	169	0 42
	76	6	43	0 86
	77	6	44	0 35
	78	6	130	1 79
	79	6	174	1 20
	80	6	92	0 78
	81	6	129	0 62
	82	6	91	1 09
	83	6	353	0 32
	84	7	21	4 67
	85	7	59	1 69
	86	7	77	1 12
	87	7	97	0 13
	88	7	99	0 15
	89	7	101	0 12
	90	7	113	0 88
	91	7	119	0 47
	92	7	123	1 72
	93	7	142	1 49
	94	7	40	2 01
	95	7	83	2 37
	96	7	60	1 25
	97	8	102	0 59
	98	9	132	0 61
	99	10	5	0 97
	100	10	13	2 39
	101	10	16	0 84
	102	10	32	0 80
	103	10	52	0 41
	104	10	56	0 19
	105	10	65	0 94
	106	10	93	0 29
	107	11	179	0 51
	108	11	191	0 29
	109	12	19	1 72
	110	12	47	0 20
	111	12	51	0 18
	112	12	177	0 31
	113	13	180	0 27
	114	14	7	4 60
	115	11	24	3 54
	116	14	41	5 13
	117	14	49	0 33
	118	14	57	0 29
	119	14	80	2 19
	120	14	82	1 11
	121	14	111	2 14
	122	14	155	0 46
	123	14	186	1 90
	124	15	193	0 56
	125	16	18	0 63
	126	16	23	0 87
	127	16	58	0 13
	128	16	67	1 51
	129	16	72	1 22
	130	16	98	0 13
	131	17	194	0 23
	132	18	48	0 37
	133	18	66	2 71
	134	18	81	2 97
	135	18	91	1 79
	136	18	86	2 35
	137	18	62	2 96
	138	18	85/195	0 48
	139	19	172	0 42
	140	20	1	1 65
	141	20	15	1 32
	142	20	28	0 92
	143	20	37	0 87
	144	20	55	0 26
	145	20	93	0 37
	146	20	108	2 42
	147	20	103	1 97
	148	20	170	0 48
	149	21	181	0 57
	150	21	192	0 35
	151	22	10	1 52
	152	22	146	1 60
	153	23	3	0 82
	154	23	11	1 21
	155	23	160	0 08
	156	23	135	1 81
	157	23	151	0 10
	158	23	116	0 93
	159	23	176	0 21
	160	23	197/198	0 49

ग्राम पोटियासिल पुलिस थाना कोरापुट जिला कोरापुट

	क्रम सं०	खाता सं०	प्लाट सं०	क्षेत्र (एकड़)
1	2	3	4	5
	1	1	142	9 37
	2	1	145	3 25

1	2	3	4	5
3.	1	119	3 44
4	1	150/2	1 52
5	2	148	1 81
6	3	3	0 74
7	3	11	1 44
8	3	15	3 10
9.	3	22	3 24
10	3	27	1 80
11	3	37	0 45
12	3	61	0 11
13	3	87	2 06
14	4	81	0.33
15	5	10	2.28
16.	5	39	0 08
17.	5	63	0 17
18	5	66	4 40
19.	5	86	0.33
20.	6	85	0 27
21	7	1	1.92
22	7	6	4 27
23	7	9	5 26
24	7	16	4.30
25	7	35	0 76
26	7	37	4 88
27.	7	41	0 51
28	7	71	0 48
29	7	93	1 79
30.	7	144	4.62
31.	7	36/153	0.97
32.	8	16 156	1 39
33	8	14	2 25
34	8	51	1.51
35	9	146	1.12
36.	10	12	0.93
37.	10	23	0.58
38	10	33	0.99
39	10	34	0.48
40	10	56	0 17
41.	10	59	0 05
42.	10	74	0 27
43.	10	150/1	2.96
44	10	108	1.72
45.	10	89	0 26
46.	10	112	7.57
47	12	2	2 79
48	12	17	3 07
49.	12	19	5 25
50	12	38	0 19
51	12	40	0 35
52	12	44	1.30
53	12	50	0.44
54.	13	49	0 33
55.	13	77	0.23
56.	14	111	2.07
57.	14	113	1.51
58	14	114	1 76
59	14	124	6 65
60	14	125	1.27
61	14	132	4.40
62	14	134	1 87
63	15	120	0 60
64	15	126	0.28
65	15	126	1 27
66	15	30	3 41
67	15	60	0 09
68.	15	65	2 98
69	15	68	0 33
70	17	52	0 22
71	17	78	0 21
72.	18	151/1	1.11
73.	19	4	0 60
74.	19	21	0 11
75	19	25	0.77
76	19	64	0 21
77	19	72	1 23
78	19	75	0 91
79.	19	91	1.81
80.	19	119	0 13
81.	19	137	1 86
82	19	116	0.34
83	20	98	1 19
84.	20	92	1.83
85	20	97	1 65
86.	20	99	1 84
87.	20	101	2.17
88	20	102	1 30
89.	20	106	6 17
90	20	138	2 75
91.	20	139/2	2.53
92.	21	129	0.48
93.	21	151/2	1 37
94	21	152	1.96
95	22	103	8.98
96	22	104	5 83
97.	22	133	1.92
98.	22	130	3.39
99	22	131	5.98
100	23	32	1 36
101	23	58	0.18
102	23	110	2.71
103	23	115	0.35
104	24	16	0.66
105	24	83	0.12
106	25	62	0.08
107.	25	69	5.50
108	26	88	0.17
109.	26	82	0.34
110	26	28	2 65
111.	27	29	3.33
112.	27	43	0.43

1	2	3	4	5
	113	27	51	1 57
	114	27	70	2 05
	115	27	95	7 10
	116	27	31	1 56
	117	27	55	1 18
	118	27	67	0 50
	119	27	76	1 64
	120	27	94	1 39
	121	27	109	5 72
	122	27	7	4 81
	123	27	42	0 20
	124	28	48	0 33
	125	28	117	0 19
	126	28	47	0 31
	127	28	80	0 13

गांव छागन तहसील नवापुर (पौटिा) जिला कोरापुट

	क्रम सं०	खाता सं०	प्लाट सं०	क्षेत्र (एकड़)	सीमा
1	2	3	4	5	6
	1	7	198	1-32	उ० सुगोखोरा द० सिवाखोरा
	2		167	0 16	उ० मिवा मुडुली द० खालपाडी
	3	12	206	1-15	उ० सिवाखारा द० कुपुली
	4		138	0-29	उ० कुपुली द० सिवौडाम्बा
	5	14	131	7-73	उ० पौटोटा द० कुपुली
	6		145	0 77	उ० नाती द० स्वय
	7		144	1-79	उ० मुलिया मुडुली द० सदसिवा खोरा
	8	14	135	9 37	उ० स्वय द० कुपुली
	9	15	166	2 88	उ० कुपुली द० खालपाडी
	10	20	178	8 21	उ० पानी नाला द० भनिया नायक
	11		200	1-66	उ० स्वय द० स्वय
	12		201	3-16	उ० स्वयं द० सदसिवा खोरा
	13		137	0 40	उ० धासीपांगी द० स्वयं
	14	21	168	0-30	उ० जावूपांगी द० गोमिया डोनिया
	15	23	205	2 77	उ० सिवाखोरा द० पहाडा
	16	32	173	3-60	उ० भिम्वुधोनू द० धावुली पारजा
	17	43	208	1-00	उ० सदाखोरा द० कुपुली
	18	39	141	0-64	उ० कुपुली द० पटोटा
	19	41	186	0-33	उ० सोला द० समोरा नायक
	20	42	214	0-70	उ० बस्ती द० स्वयं
	21		215	3 90	उ० सदासिवा खारा द० सुकुरा
	22		156	1 52	उ० समारा नायक द० स्वय
	23		161	6-00	उ० स्वय द० कुपुली
	24	45	126	0-13	उ० नादी द० स्वय
	25		127	0 11	उ० स्वयं द० स्वय
	26		128	5-52	उ० स्वय द० पहाडा
	27	56	190	0 54	उ० स्वयं द० सिवाखोरा
	28		148	4 37	उ० स्वय द० समरा नायक
	29	56	146	7 11	उ० समरा नायक द० स्वयं
	30	66	183	3-28	उ० सिवाखोरा द० पानी नाला
	31		179	1-22	उ० स्वयं द० कुपुली
	32		189	0-52	उ० सिवाखारा द० पानी नाला
	33		194	1-50	उ० स्वय द० सिवाखारा
	34		190	1 38	उ० स्वय द० टबू डाम्बा
	35		152	5-90	उ० मादी द० बुडू डाम्बा
	36		139	2-73	प० कुपुली द० सदासिवा खोरा
	37		155	2-98	उ० स्वय द० स्वय
	38		142	3 02	उ० पहाडा द० सरकारी भूमि
	39		147	0-10	उ० स्वय द० मुडुली
	40		181	0-43	उ० सिवाखोरा द० टिबो डाम्बो
	41		149	0-60	उ० मुलिया मुडुली द० बुडू टाम्बो
	42		150	0-55	उ० स्वय द० मुलिया मुडुली
	43		151	1-74	उ० नैदी द० स्वय
	44		162	4-60	उ० स्वय द० सुकुरा जानी
	45		154	0-06	उ० पहाडा द० बिधू जाकबा
	46	67	177	0-15	उ० सुकुरा खिन-बावी द० सुकुरा खिनीबावी
	47		207	1-22	उ० स्वयं द० कुपुली

1	2	3	4	5	6
	48		143	6-51	उ० घावल गोडा द० झोला
	49		202	1-37	उ० डिबू डाम्बो द० स्वय
	50		184	1-80	उ० स्वयं द० घाबुल डाम्बो
	51	67	185	8-64	उ० पैदा द० गुरुमाखोग
	52		188	2-61	उ० स्वय द० पटिया
	53		160	3-20	उ० बुडु डोम्बा द० समरा नायक
	54		192	2-82	उ० स्वयं द० नार्दा बेडा
	55		196	0-72	उ० पटीटा द० गुनिया डोरिया
	58		204	2-47	उ० पटीटा द० धासी परजिया
	57		132	0-44	उ० नाडी द० पहाडा
	58		133	0-33	उ० नाडी द० स्वयं
	59	72	172	0-94	उ० कुपुली द० कुपुली
	60	76	180	2-15	उ० कुपुली द० कुपुली
	61		164	2-60	उ० समरा नायक द० जावू पराजा
	62		209	0-48	उ० धाबुल परजा द० कुपली
	63		212	0-36	उ० सिवाखोग द० पटीटा
	64		176	1-14	उ० सिवाखोरा द० कुपुली
	65		216	0-13	उ० बुडु डाम्बो द० सिवाखोग
	66	180	210	0-34	बिजामनली

[एफ० नं० 8/37/81 -मैटल-4]

जे० ए० चौधरी, निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 14th December, 1982

S.O. 288.—In the exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the table below, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be an estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers and duties imposed by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.			
	Serial No.	Khata No.	Plot No.	Area (acres)
1	2	3	4	5
	Village : Damanjodi, P.S. Semiliguda, Dist. Koraput			
Deputy Manager (Adm.)	1.	1	82	0 88
National Aluminium Co. Ltd.	2.	1	218	1 54
	3.	1	222	1.09
Notified Area Committee Bhawan,	4	1	451	1.09
Sunabeda-763003	5.	2	76	0.69
Distt. Koraput,	6	2	213	1.11
ORISSA.	7	2	212	0.61
	8.	3	2	1 82
	9.	3	8	1.10
	10.	3	10	0 30
	11.	3	417	2.42
	12.	3	419	1 13
	13.	4	41	8.80
	14.	4	44	0.44
	15.	4	93	1 83
	16.	4	94	1 62
	17.	4	110	0 91
	18.	4	112	1.41
	19.	4	32	3.88
	20.	4	34/1	1.70
	21.	4	21	1.76
	22.	4	39	2.08
	23.	4	107	3.05
	24.	5	5	0.98
	25.	6	111	0.53
	26.	7	319	1.18
	27.	7	114	4.06
	28.	7	151	1.68
	29.	7	175	0.25
	30.	7	239	1.41
	31.	7	255	0.58
	32.	8	81	1.71
	33.	8	369	0.88
	34.	8	374	1 12
	35.	8	65	3.21
	36.	8	440	1 11
	37.	9	125	1 32
	38.	72/1	441/476	0.11
	39.	9	231	2.62
	40	9	235	1 13
	41.	10	85	1.72
	42.	10	90	0.85
	43.	10	368	0.61
	44.	10	441	1.99
	45	11	102	0.13
	46.	11	116	1.21
	47.	11	217	1 96
	48.	11	261	2.31
	49.	12	333	0.35
	50.	12	446	0.11
	51.	12	402	0.61
	52.	12	408	1.11
	53.	13	17	7.50
	54.	13	22	2.31

1	2	3	4	5
	55.	13	28	0.79
	56.	13	29	0.29
	57.	13	35	3.98
	58.	13	25	1.72
	59.	13	40	4.18
	60.	13	42	3.39
	61.	13	46	0.71
	62	13	48	1.01
	63.	13	56	2.79
	64.	13	31	1.85
	65	13	92	2.66
	66.	13	108	4.45
	67.	13	51/471	4.82
	68	13	47	0.68
	69.	13	22/479	1.86
	70	14	57	1.41
	71.	15	119	2.00
	72.	15	137	1.57
	73.	15	312	2.82
	74.	16	331	0.67
	75.	17	64	2.13
	76.	17	437	1.74
	77	17	455	3.49
	78	17	180	1.81
	79.	17	324	3.25
	80.	17	207	0.40
	81.	18	66	1.52
	82.	18	389	1.33
	83.	18	393	0.34
	84.	19	12	1.71
	85.	20	13	0 86
	86.	20	103	0.07
	87.	20	256	1.31
	88.	20	262	2.23
	89	20	263	3.04
	90.	20	264	3.42
	91.	20	266	2.22
	92.	20	130	2.57
	93.	20	134	4.72
	94.	20	150	0 24
	95.	21	172	0.64
	96.	21	282	0.81
	97	21	283	1.12
	98.	22	284	0.16
	99.	22	286	0.58
	100.	22	292	0.81
	101.	22	156	1.09
	102.	22	161	1.91
	103.	22	166	0.63
	104.	22	307	0.22
	105	22	311	0 56
	106.	22	347	0.41
	107.	22	348	0.50
	108.	23	285	0.18
	109.	23	293	0.59
	110.	23	294	1.25
	111.	23	295	0.39
	112.	23	207	0.17
	113	23	306	0.35
	114	23	77	0.69
	115.	23	79	0.70
	116.	23	168	0.68
	117.	23	169	0.20
	118	23	370	0.71
	119.	23	375	1.09
	120	23	380	1.23
	121.	24	153	1.07
	122.	24	187	2.60
	123.	24	204	1.00
	124.	24	230	2.05
	125.	24	272	2.03
	126.	24	317	0.58
	127.	24	360	1.68
	128.	24	456	3.47
	129.	25	87	0.41
	130.	25	205	0.95
	131.	25	171	0.72
	132.	25	384	1.07
	133.	25	388	1.39
	134.	26	138	1.06
	135.	26	196	0.91
	136.	26	203	0.36
	137.	26	229	2.76
	138.	26	233	1.41
	139.	26	248	2.33
	140.	26	277	1.60
	141.	26	159	0.42
	142.	26	325	1.56
	143.	26	337	1.39
	144.	26	338	1.40
	145.	26	349	0.76
	146.	26	351	0.64
	147.	26	355	1.89
	148.	26	60	1.40
	149.	26	124	2.20
	150.	26	126	7.88
	151.	26	132	1.41
	152.	26	154	0.73
	153.	26	194	0.28
	154.	26	258	2.69
	155.	26	322	1.00
	156.	26	250	0.84
	157.	26	352	0.80
	158.	26	123	1.48
	159	26	329	0.46
	160.	26	242	1.31
	161.	27	364	0.89
	162.	27	372	1.12
	163.	27	385	1.42
	164.	27	386	2.81
	165.	27	394	0.28
	166.	27	396	0.77
	167.	27	398	1.03
	168.	27	405	0.98
	169.	27	404	2.28
	170.	27	406	0.75
	171.	27	299	0.39
	172.	27	361	1.07
	173.	28	143	3.20
	174.	28	246	1.42
	175.	28	449	0.51
	176.	29	301	0.23
	177.	29	330	0.16
	178.	29	426	3.72
	179.	29	427	0.42
	180.	29	439	0.55
	181.	29	447	0.81
	182.	29	448	1.14
	183.	30	19	2.16
	184.	30	26	0.59
	185.	30	27	1.05
	186.	30	49	1.72
	187.	30	52	4.23

1	2	3	4	5
	188.	30	98	1.88
	189.	30	14	1.91
	190.	30	20	1 21
	191.	30	45	1.78
	192.	30	95	1.44
	193.	30	104	0 98
	194.	30	105	1.82
	195.	31	23	1 80
	196.	32	113	1 13
	197.	32	117	1 82
	198.	32	121	0 66
	199	32	150	1.17
	200.	32	162	0.20
	201.	32	201	1 52
	202.	32	232	2 41
	203.	32	254	0.64
	204.	32	304	0.21
	205.	32	309	3.14
	206.	32	310	3.09
	207.	32	100	1.96
	208.	32	335	1.07
	209.	32	397	3.40
	210.	33	59	0.86
	211.	33	302	0.35
	212.	33	332	0.79
	213.	33	334	0.42
	214.	33	399	1.70
	215.	33	400	0.94
	216.	33	62	0.82
	217.	33	401	0 51
	218.	33	442	1.31
	219.	33	444	0.22
	220.	34	226	1.42
	221.	34	234	1.06
	222.	34	249	0.88
	223.	34	268	1.53
	224.	35	208	0.55
	225.	35	225	0.41
	226.	36	24	13.00
	227.	36	30	0.41
	228.	36	33	2.37
	229.	36	50	3.38
	230.	36	53	1.23
	231.	36	83	3.99
	232.	36	106	2.60
	233.	36	36/472	1.21
	234.	36	6	1.41
	235.	36	15	2.65
	236.	36	37	0.69
	237.	36	54	1 58
	238.	36	55	1 79
	239.	36	34/2	1.92
	240.	37	4	2.47
	241.	38	7	0 36
	242.	39	181	1.70
	243.	39	188	1.44
	244.	39	195	1.08
	245.	39	228	2.37
	246.	39	326	0.81
	247.	39	328	0 78
	248.	39	167	0.54
	249.	40	170	0.38
	250.	40	300	0.30
	251.	40	366	0.88
	252.	40	395	0.97
	253.	40	403	0.73
	254.	40	410	1.40
	255.	41	99	2.09
	256.	41	197	0 59
	257.	41	202	1 39
	258.	41	216	9.10
	259.	41	223	1 48
	260.	41	227	2.65
	261.	41	81/475	2.80
	262	41	250	1.76
	263.	41	321	1.89
	264.	41	391	2.06
	265.	41	425	2.79
	266.	41	458	3.48
	267.	41	136/474	0 59
	268.	42	86	1.31
	269.	42	198	1.02
	270.	42	199	2.78
	271.	43	160	0.69
	272.	43	316	3.22
	273.	43	453	7 21
	274.	43	135	2.18
	275.	43	148	1 20
	276.	43	215	5 22
	277.	43	257	2 66
	278.	43	123	2 97
	279.	43	139	1.42
	280.	43	122	1.27
	281.	44	173	0.71
	282.	44	383	0.49
	283.	44	411	2.26
	284.	44	428	0 80
	285.	44	429	1.71
	286.	44	430	0.81
	287.	44	470	6 61
	288.	44	432	1 01
	289.	44	433	0.41
	290.	44	434	0.56
	291.	44	465	0.42
	292.	44	468	7.08
	293.	44	209	0.19
	294.	44	224	0.18
	295.	44	431	1.11
	296.	44	211/477	0.69
	297.	44	63	1.18
	298.	45	9	0.52
	299.	45	61	2.70
	300.	45	69	1.35
	301.	45	72	1.60
	302.	45	147	1.55
	303.	45	152	1.51
	304.	45	259	3.20
	305.	45	291	0.15
	306.	45	342	0.46
	307.	45	353	0.71
	308.	45	354	0.88
	309.	46	11	3.50
	310.	46	74	1 00
	311.	46	275	0.64
	312.	46	279	0.46
	313.	46	280	0.74
	314.	46	363	1.18
	315.	47	1	0.17
	316	48	267	3.40
	317.	48	327	1.08
	318.	49	273	0.43
	319.	49	274	0.93
	320.	49	381	0.66

1	2	3	4	5
	321.	49	421	4 25
	322.	49	422	0.21
	323	50	183	5.23
	324.	50	186	1.96
	325.	50	245	1.01
	326.	50	270	1 09
	327	50	278	2.35
	328.	50	305	0.32
	329.	50	435	1 55
	330.	50	436	0.93
	331.	51	303	0.10
	332.	51	438	0.72
	333	51	443	1.48
	334.	51	461	2 02
	335	52	67	4 48
	336.	52	127	3.00
	337.	52	131	4.31
	338.	52	174	1.01
	339.	52	243	1.08
	340	52	289	2.02
	341.	52	358	1.78
	342.	52	71	1.90
	343.	53	365	3.05
	344.	53	367	2.09
	345.	54	415	0.66
	346.	55	251	1.65
	347.	55	265	1.88
	348.	55	454	2.52
	349.	56	276	0.23
	350.	56	462	1.98
	351.	57	101	0.11
	352.	57	118	1.41
	353.	57	220	1.40
	354.	57	260	0.81
	355.	57	313	2.88
	356.	57	314	0.96
	357.	57	318	0.51
	358.	58	58	0.71
	359.	58	211	1.70
	360.	59	3	0.41
	361.	59	206	0.92
	362.	60	16	10.00
	363.	61	133	3.03
	364	61	144	1.83
	365.	61	184	0.81
	366.	61	240	1.30
	367.	61	296	0.39
	368.	61	336	1.79
	369.	61	339	4.63
	370.	61	341	2.67
	371.	61	164	1.79
	372.	62	80	1.71
	373.	62	371	0.66
	374	62	378	0.62
	375.	63	219	1.86
	376.	63	238	1.93
	377.	63	459	4.13
	378.	63	460	5.37
	379.	64	356	1.88
	380.	64	362	2.75
	381.	65	129	4.11
	382.	65	145	2.72
	383.	66	73	0.69
	384.	66	176	1.77
	385.	66	177	0.98
	386.	66	179	2.69
	387.	66	290	6.38
	388.	66	344	0.44
	389.	66	346	0.34
	390.	66	452	0.91
	391.	66	241	22.50
	392.	66	288	0.33
	393.	66	343	0.44
	394	66	345	0.63
	395.	67	75	0.80
	396.	67	373	0.80
	397.	67	78	0.68
	398.	67	379	0 82
	399.	68	96	1.88
	400.	68	97	1.21
	401.	62	115	1.62
	402.	62	155	0.59
	403.	68	163/1	1.29
	404.	68	178	1.74
	405.	68	182	0.43
	406.	68	193	0.97
	407	68	221	1.03
	408.	68	247	0.82
	409.	68	252	0.50
	410.	68	269	1.54
	411	72/4	323	0.80
	412.	72/6	340	2.09
	413.	68	392	1.92
	414.	68	413	1.14
	415.	68	423	2.63
	416.	68	457	2.38
	417.	68	464	0.40
	418.	69	70	0.89
	419.	69	214	1.71
	420.	69	287	0.19
	421.	69	296	0.92
	422.	69	376	1.71
	423.	72/5	387	0.64
	424.	69	463	0.60
	425.	69	465	0.58
	426.	69	467	0.93
	427.	69	469	2.58
	428.	69	108/473	0.39
	429.	70	68	1.58
	430.	70	84	0.93
	431.	70	120	1.41
	432.	70	146	0.60
	433.	70	157	1.63
	434.	70	244	1.25
	435.	70	315	2.38
	436.	70	357	2.68
	437.	70	381	0.06
	438.	71	89	0.69
	439.	71	377	1 35
	440.	71	382	1.82
	441.	71	390	1.36
	442.	71	407	0.48
	443.	71	416	2.42
	444.	71	445	0.31
	445.	72	414	3.32
	446.	72	418	0.48
	447.	72/3	200	0.84
	448.	73	253	0.28
	449.	73	140	0.72
	450.	73	142	1.11
	451.	73	82/481	0.09

1	2	3	4	5
	452.	74	359	35.90
	453.	74	149	0.11
	454.	74	158	60.90
	455.	74	185	10.00
	456.	74	237	14.85
	457.	74	424	25.24
	458.	74	308	0.47
	459.	74	420	1 41
	460	74	18	0 82
	461.	74	38	2 45
	462.	74	43	3.97
	463.	74	51	1.21
	464.	74	165	0.31
	465.	75	210	1 38
	466.	75	192	1 08
	467.	76	91	0.73
	468.	76	141	0.66
	469.	76	271	1.28
	470.	77	83	50.00
	471	77	109	14.50
	472.	77	189	2.77
	473.	77	190	0.89
	474.	77	236	10.00
	475.	77	409	11.60
	476.	77	412	4 72
	477.	77	209/480	0.36

Village : Barangaput P.S. Semiliguda Dist. Koraput

1	Sl. No. 2	Khata No. 3	Plot No. 4	Area (acres) 5
	1.	1	4	2.51
	2.	1	6	1.90
	3.	1	35	0.37
	4.	1	31	0.20
	5.	1	75	1.65
	6.	1	124	0.21
	7.	1	150	0.30
	8.	1	152	0.16
	9.	2	121	0.27
	10.	2	170	0.43
	11.	3	16	2.49
	12.	3	40	0.60
	13.	3	72	2 00
	14.	3	140	0.21
	15.	3	153	0.20
	16.	4	130	0.11
	17.	5	5	1.07
	18.	5	30	0.29
	19.	5	36	2.35
	20.	5	47	0.77
	21.	5	65	1.20
	22.	5	68	1.32
	23.	5	74	0.68
	24.	5	100	0.09
	25.	5	113	0.29
	26.	5	115	0.08
	27.	5	137	0.29
	28.	5	143	0.19
	29.	5	139	0 29
	30.	6	112	0.36
	31	7	7	3.39
	32	7	8	1 30
	33.	7	13	0.82
	34.	7	25	1.66
	35.	7	116	0.20
	36.	7	139	0.29
	37.	7	142	0.17
	38.	7	158	0.18
	39.	8	173	0.14
	40.	9	108	0.98
	41.	9	180	0.28
	42.	10	93	0.41
	43.	11	86	0.25
	44.	12	10	1.44
	45.	12	39	2.94
	46.	12	61	0.08
	47.	12	63	1.37
	48	12	123	0.32
	49.	12	149	0.30
	50.	12	155	0.20
	51.	13	111	0.31
	52.	13	126	0.17
	53.	14	9	0.77
	54.	14	15	0.98
	55.	14	18	1.58
	56.	14	24	2.47
	57.	14	52	0.40
	58.	14	58	0.70
	59.	14	62	0.99
	60.	14	77	0.79
	61.	14	125	0.32
	62.	14	133	0.11
	63.	14	145	0.19
	64.	14	156	0.20
	65.	14	164	0.41
	66.	15	53	0.23
	67.	15	119	0.12
	68.	15	174	0.43
	69.	15	131	0.37
	70.	16	85	0.26
	71.	17	19	2.09
	72.	17	20	0.42
	73.	17	26	0.18
	74.	17	46	2.69
	75.	17	79	1.18
	76.	17	92	0.33
	77.	17	122	0.31
	78.	17	134	0.07
	79.	17	151	0.32
	80.	17	157	0.19
	81.	17	44	1 90
	82.	18	99	0.19
	83.	18	107	0.30
	84.	18	117	0.17
	85.	18	118	0.26
	86.	19	83	0.12
	87.	20	88	0.96
	88.	21	11	1.10
	89.	21	17	1.89
	90.	21	33	0.26
	91.	21	34	0.27
	92.	21	38	2.02
	93.	21	45	1.33
	94.	21	54	0.89
	95.	21	70	1.27
	96.	21	71	1.19
	97.	21	73	1.77

2	3	4	5
	98.	21	96	2.80
	99.	21	101	0.15
	100.	21	104	0.19
	101.	21	132	0 35
	102.	21	135	0 24
	103.	21	138	0.32
	104.	21	141	0.17
	105.	21	146	0.20
	106.	21	147	0.24
	107.	21	177	1.70
	108.	22	55	0.45
	109.	22	57	0.70
	110.	22	128	0.21
	111.	22	129	0.33
	112.	22	163	0.68
	113.	22	176	0.94
	114.	23	91	0.90
	115.	24	90	1.11
	116.	25	3	2.26
	117.	25	14	0.68
	118.	25	21	1.40
	119.	25	22	0 90
	120.	25	23	1.37
	121.	25	27	1.92
	122.	25	28	2.56
	123.	25	29	0.28
	124.	25	49	0.78
	125.	25	50	0 37
	126.	25	59	0.71
	127.	25	64	1.11
	128.	25	66	1.63
	129.	25	67	1.57
	130.	25	69	1.07
	131.	25	76	3.52
	132.	25	105	0.06
	133.	25	114	0.25
	134.	25	136	0.46
	135.	25	144	0.19
	136.	25	148	0.24
	137.	25	154	0.34
	138.	25	30/181	0.24
	139.	25	160	0.20
	140.	25	166	0.58
	141.	26	56	0.72
	142.	26	102	0.08
	143.	26	103	0.46
	144.	26	109	0.20
	145.	26	110	0.44
	146.	26	127	0.29
	147.	26	167	0.31
	148.	26	168	0.11
	149.	26	169	0.82
	150.	26	171	0.37
	151.	26	175	0.78
	152.	27	42	2.01
	153.	28	97	1.50
	154.	29	94	3.21
	155.	30	120	0.38
	156.	30	162	0.61
	157.	30	179	1.43
	158.	31	87	1.60
	159.	31/1	37	0.04
	160.	31/1	95	0.42
	161.	31/1	89	0.24
	162.	31/1	161	0 44
	163.	31/1	165	0.19

Village AMBAGAN P.S. SEMILIGUDA DIST KORAPUT

1	Sl. No. 2	Khata No. 3	Plot No. 4	Area (acres) 5	Boundry. 6
	1.	1	785	2 34	N–Bangite Gouda S–Anu Gouda
	2.	1	789	1 04	N–Pahada S–Dhanu Gouda
	3.	1	802	1.28	N–Muli Jani S–Gurmo Keuta
	4.	1	796/967	2.84	N–Dhanu Gouda S–Damonjodi village
	5.	2	865	2 00	N–Pahada S–Benga Muduli
	6.	5	901	0.90	N–Self S–Mulia Jani
	7.	5	902	0 45	N–Magtia Bhoi S–Self
	8.	10	962	1.07	N–Dudu Bhoi S–Padia
	9.	10	852	1.21	N–Gotia Bhoi S–Bandulu
	10.	10	887	0.74	N–Bingu Budia S–Dara Chalan
	11.	15	884	3.25	N–Pahada S–Nala
	12.	15	480	0.86	N–Dora Chalan S–Dora Chalan
	13.	15	837	1.00	N–Budu Bedia S–Duara Chalan
	14.	13	851	0.87	N–Mangiti Bhoi S–Kesaba Bhoi
	15.	16	896	0 39	N–Danguru Bhoi S–Damonjodi Village
	16.	16	830	0.14	N–Patita S–Patita
	17.	17	867	1 29	N–Benga Muduli S–Bonduku Chalan
	18.	19	871	3 44	N–Budu Bhoi S–Chaitu Bhoi
	19.	20	922	0.63	N–Mulia Bhoi S–Burja Bhoi
	20.	25	872	2.03	N–Gonda Bhoi S–Mulia Bhoi
	21.	25	957	0.72	N–Magtia Bhoi S–Gonda Bhoi
	22.	26	910	0.24	N–Patita S–Patia
	23.	26	965	0.33	N–Self S–Self
	24.	27	775	0 99	N–Self S–Damonjodi
	25.	30	791	1.58	N–Magitia Gouda S–Self
	26.	30	792	0 91	N–Self S–Nala
	27.	30	793	1 75	N–Bangati Gouda S–Self
	28.	30	797	1.48	N–Suku Bhoi S–Dhanu Bhoi
	29.	30	803	0 63	N–Alka Gouda S–Dhan Gouda

1	2	3	4	5	6
	30.	32	895	2 42	N–Dhanu Bhoi S–Gangadhar Bhoi
	31.	32	912	0.30	N–Patita S–Patita
	32.	32	915	0.82	N–Self S–Damonjodi
	33	34	913	0.22	N–Padia S–Patita
	34	34	919	1 26	N–Dara Muduli S–Damonjodi
	35.	40	860	1.15	N–Bandaka Chalan S–Gangadhar Majhi
	36.	40	869	1.86	N–Banduku Chalan S–Buruja Bhoi
	37	40	888	1 38	N–Kesaba Bhoi S–Dhanu Bhoi
	38.	40	823	0.90	N–Gurju Dami S–Padia
	39.	40	546	0.85	N–Self S–Pahada
	40.	41	897	0.11	
	41.	41	829	0.15	N–Patita S–Patia
	42.	42	854	1 69	N–Banduku Chalan S–Damonjodi Village
	43.	42	891	1 14	N–Janu Bhoi S–Self
	44.	42	892	2.19	N–Self S–Self
	45.	42	893	2.25	N–Self S–Self
	46.	42	894	1 31	N–Self S–Damonjodi Village
	47	42	929	4.15	N–Pahada S–Nala
	48	42	935	0.84	N–Mulia Jani S–Gonda Bhoi
	49	42	940	0.41	
	50	42	548	0.85	N–Nala S–Jayram Bhoi
	51.	42	918	1 60	N–Self S–Dombu Bhoi
	52.	44	890	3.31	N–Dora Chalan S–Dora Muduli
	53.	46	834	0.05	N–Baraju Dami S–Gangadhar Majhi
	54.	48	783	1 65	N–Dhanaka Gouda S–Damonjodi village
	55.	48	788	0.66	N–Dhanaka Gouda S–Ladhia Jani
	56.	48	796	1.74	N–Banu Gouda S–Dhanaka Guda
	57.	48	799	3.67	N–Sukuru Bhoi S–Mulia Jani
	58.	48	805	0.63	N–Bangiti Gouda S–Lodia Jani
	59.	48	807	2.01	N–Self S–Damonjodi
	60.	50	753	1 76	N–Reli Bhoi S–Reli Bhoi
	61.	50	760	1.26	N–Reli Bhoi S–Reli Bhoi
	62.	50	761	0.97	N–Reli Bhoi S–Reli Bhoi
	63.	50	816	1.28	N–Mulia Jani S–Nala
	64.	50	939	0.48	N–Duara Muduli S–Suku Bhoi
	65.	52	817	1.26	N–Self S–Nala
	66	52	818	1.48	N–Pahada S–Self
	67.	52	846	0.38	N–Nala S–Pahada
	68	52	858	1.11	N–Pahada S–Sadhu Chalan
	69.	52	853	0.80	N–Kesaba Bhoi S–Dora Muduli
	70.	52	868	1 59	N–Nala S–Dora Chalan
	71.	52	900	2.25	N–Nala S–Mulia Jani
	72.	52	839	1.73	N–Buruju Jani S–Nala
	73.	52	857	1.52	N–Pahada S–Padia
	74.	54	876	2.02	N–Magatia Bhoi S–Sukuru Bhoi
	75.	54	880	2 26	N–Nala S–Sukura Bhoi
	76.	54	934	1 82	N–Dora Muduli S–Reli Bhoi
	77.	54	958	1.48	N–Chaitan Bhoi S–Lada Bhoi
	78.	56	786	2.19	N–Nodia Jani S–Alaka Gouda
	79	56	790	1 64	N–Pahada S–Jamu Gouda
	80.	56	801	0.20	N–Alka Gouda S–Hanu Gouda
	81.	56	828	0.98	N–Baraju Dami S–Sukuru Bhoi
	82.	58	849	1.30	N–Nala S–Magitia Bhoi
	83.	58	886	0 54	N–Pahada S–Kesaba Bhoi
	84.	60	768	4.21	N–Pahada S–Self
	85.	60	769	2.30	N–Self S–Self
	86.	60	770	2.13	N–Self S–Self
	87.	60	771	1.99	N–Self S–Gochar
	88.	60	772/1	4 70	N–Self S–Mulia Jani
	89.	60	776	0.74	N–Gochar S–Self
	90	60	781	2 04	N–Self S–Village Damonjodi
	91.	60	782	1.79	N–Gochar S–Self

1	2	3	4	5	6
	92	61	777	0 89	N Gochar S-Damonjodi
	93.	61	778	0 81	N-Gochar S-Damonjodi
	94.	66	822	0 50	N-Dora Chhanel S-Padia
	95.	66	827	1 59	N-Buruju Jani S/Ganga Dhar Majhi
	96	66	832	2 03	N-Padia S-Padia
	97.	66	833	2 81	N-Buruju Jani S-Self
	98	66	845	1 30	N Nala S.Pahada
	99.	66	693	1 51	N-Sadhu Chalan S-Self
	100.	66	692	1 24	N-Self S-Anabadi
	101.	66	691	1.00	N Self S-Padia
	102.	66	838	0 72	N-Bonducu Chalan S-Bonducu Bhoi
	103.	66	820	2 10	N-Hemogudia S-Nala
	104.	66	690	0 05	N-Ledia Jani S-Self
	105.	70	870	1 39	N-Dora Chalan S Gonda Bhoi
	106	70	874	2 14	N-Magita Bhoi S-Magitia Bhoi
	107.	71	923	0.87	N-Gonda Bhoi S-Damonjodi
	108.	72	866	1 03	N-Bonda Bhoi S-Gangadhar Budia
	109	72	905	2 58	N-Lada Bhoi S-Magata Bhoi
	110.	72	907	1 54	N-Magata Bhoi S-Padia
	111.	78	956	1.13	N-Bhonga Bhoi S-Chaitan Bhoi
	112.	74	955	2 24	N-Tangla Bhoi S-Magulia Bhoi
	113	82	780	2 21	N Padia S-Damonjodi Land
	114	82	800	2 81	N-Dhana Gouda S-Anaka Gouda
	115.	82	813	1 88	N-Pahada S-Hemogudia
	116.	82	865	1.29	
	117.	90	936	1.26	N-Padia S-Dora Muduli
	118.	90	703	0.60	N-Mulia Jani S-Buruju Dami
	119.	84	811	3.40	N-Pahada S-Nala
	120	84	873	1.71	N-Chaitan Bhoi S-Buruji Bhoi
	121.	85	909	0.37	N-Podia S-Podia
	122	87	914	0 20	N-Patita S-Patita
	123	87	920	0 49	N-Mulia Jani S-Dhamonjodi
	124.	80	900	0 74	N Loda Bhoi S-Dudu Bhoi
	125	80	906	2 60	N-Lada Bhoi S-Denga Muduli
	126.	88	757	1 37	N-Bala Bhoi S-Bala Bhoi
	127.	88	759	1 44	B-Bala Bhoi S-Bala Bhoi
	128.	88	762	1.76	N-Bala Bhoi S-Pahada
	129.	88	883	3 97	N-Pahada S-Nala
	130.	88	547	0.90	N-Bala Bhoi S-Pahada
	131.	90	812	0 06	N-Nalo S-Nalo
	132.	90	787	9 10	N-Sudhia Jani S-Padia
	133.	90	794	1 20	N-Bangra Gouda S-Nala
	134.	90	806	1 28	N-Dhanu Gauda S-Damonjodi village
	135.	90	809	0 99	N-Pahada S-Pahada
	136.	90	844	1 08	N-Nala S-Pahada
	137	90	545	3 14	N-Bala Bhoi S Pahada
	138.	90	863	2 06	N-Pahada S-Bonda Bhoi
	139.	92	903	2 67	N-Sukuru Bhoi S-Magudu Bhoi
	140.	92	904	3 78	N-Sukuru Bhoi S-Benga Muduli
	141.	92	969	1.23	N-Benda Bhoi S-Magulu Bhoi
	142.	97	798	2 66	N-Pahada S-Padia
	143	97	877	1.30	N-Bonda Bhoi S-Lada Bhoi
	144.	97	878	1 52	N-Gonda Bhoi S-Loda Bhoi
	145.	97	964	0.96	N-Kurumuli S-Chaitan Bhoi
	146	97	938	0.81	N-Bala Bhoi S-Padia
	147.	79	924	0.57	N-Mulia Jani S-Buruju Bhoi
	148.	99	812	1.21	N-Mulia Bhoi S-Nala
	149.	99	826	1.56	N-Padia S-Buruja Jani
	150.	101/1	772/2	5 30	N-Binju S-Binju
	151	101/1	773	0 21	N-Sunadhar Chalan S-Self
	152.		814	1 50	N Gangadhar Majhi S--Mulia Jani
	153.		847	3 48	N-Nala S-Nala

1	2	3	4	5
154.	101/1 927	2 68	N–Pahada S–Pagutia	
155.	101/1 928	3.84		
156.	101/1 779	1.15	N–Mulia Jani S–Mulia Jani	
157.	101/2 774	0 74	N–Self S–Poduku Jani	
158.	101/2 815	0.97	N–Mulia Jani S–Nala	
159.	101/2 864	2.39		
160.	101/6 831	0.39	N–Buruju Jani S–Buruju Jani	
161.	101/12 704	0 20	N–Pahada S–Ladia Jani & Others	
162.	101/13 908	1.36	N–Kobi Bhatra & Others S–Dumburi Bhoi & Others	
163.	101/12 911	0 73	N–Damonjodi village S–Danguru Bhoi	
164.	101/33 926	0 10	N–Pratap Chalan S–Sukuri Bhoi & others	
165	101/33 930	0.54	N–Dura Muduli & others S–Pratap Chalan	
166.	101/44 898	1.56	N–Mulia Jani S–Damonjodi village	
167.	101/44 899	0.88	N–Bounduku Challan S–Mulia Jani & others	
168.	101/44 916	0.61	N–Donguria Bhoi S–Mosanipada	
169.	101/44 917	0.47	N–Duara Muduli S–Donguria Bhoi	
170.	101/44 921	0.54	N–Mulia Jani S–Damonjodi	
171.	101/44 925	0.92	N–Mulia Jani S–Damonjodi	
172.	37 932	0.79	N–Bonda Bhoi S–Bonga Bhoi	
173.	35 961	1.20	N–Magatu Bhoi S–Kesaba Bhoi	
174.	6 841	0.81	N–Pahada S–Pahada	
175.	15 819	0.74	N–Padia S–Banduku Challan	
176.	78 850	1.96	N–Nala S–Gotia Bhoi	
177.	78 875	3 72	N–Buruju Bhoi S–Bonda Bhoi	
178.	78 879	1.32	N–Nala S–Banduku Challan	

VILLAGE : CHAMPAPADAR P.S. KORAPUT
DIST. KORAPUT

Serial No.	Khata No.	Plot No.	Acquired Area (acres)
1	2	3	4	5
1.	1	2	0.97
2.	1	51	2.35
3.	1	53	3.30
4.	1	54	1.04
5.	1	82	0 98
6.	1	95	1.48
7.	1	111	0.91
8.	1	180	0.32
9.	1	181	3.14
10.	2	85	0 37
11.	2	96	1 05
12.	3	9	3.21
13.	3	19	2 68
14.	3	25	1.63
15.	3	58	1 19
16.	3	122	2.73
17.	3	169	8.00
18.	3	178	0.94
19.	3	183	2.93
20.	4	153	0.64
21.	5	156	0.31
22.	6	24	0.76
23.	6	48	2.99
24.	6	87	0.93
25.	6	104	0.22
26.	6	112	2.30
27.	6	118	2.60
28.	6	138	0.31
29.	6	151	3.52
30.	6	166	2.29
31.	6	173	0.96
32.	6	177	0.93
33.	6	197	1.32
34.	6	201	1.75
35.	6	235	3.72
36.	7	94	0 21
37.	7	239	0.88
38.	8	234	0.62
39.	9	29	1.83
40.	9	38	1 16
41.	9	60	3 56
42.	9	115	0.58
43.	9	193	1.88
44.	9	194	3.46
45.	9	208	5 13
46.	9	213	2.20
47.	9	121/249	1.41
48.	10	207	0.08
49.	11	11	0.77
50.	11	30	2.09
51.	11	80	1 75
52.	11	83	0.98
53.	11	120	3.77
54.	11	171	2.03
55.	11	186	3.04
56.	11	187	3.04

1	2	3	4	5
	57.	11	190	1.30
	58.	11	192	1.89
	59.	11	202	1.57
	60.	11	238	4.98
	61.	11	241	3.67
	62.	12	135	0.31
	63.	13	204	3.54
	64.	14	4	0.60
	65.	14	6	3.38
	66.	14	15	1.07
	67.	14	20	3.45
	68.	14	22	3.21
	69.	14	45	4.72
	70.	14	64	4.28
	71.	14	65	3.55
	72.	14	67	2.28
	73.	14	68	3.63
	74.	14	73	0.79
	75.	14	81	1.35
	76.	14	114	0.81
	77.	14	117	5.19
	78.	14	126	1.58
	79.	14	128	1.90
	80.	14	142	0.67
	81.	14	149	5.05
	82.	15	69	1.21
	83.	15	84	0.35
	84.	15	90	0.25
	85.	15	147	0 56
	86.	15	150	0.74
	87.	15	152	0.42
	88.	15	179	0.23
	89.	15	205	0.41
	90.	16	44	2 43
	91.	16	174	1.64
	92.	17	49	4.18
	93.	17	188	3.52
	94.	17	200	3.56
	95.	17	214	3.40
	96.	17	218	1.63
	97.	18	7	6.31
	98.	18	8	2.34
	99.	18	12	2.05
	100.	18	13	3.07
	101.	18	28	5.12
	102.	18	40	3.38
	103.	18	59	4.01
	104.	18	62	4 99
	105.	18	74	0.75
	106.	18	76	0.45
	107.	18	92	0.78
	108.	18	106	0.61
	109.	18	116	2 08
	110.	18	125	3.94
	111.	18	146	3 92
	112.	18	196	4.62
	113.	19	79	0.85
	114.	19	154	0.23
	115.	19	155	0.50
	116.	19	77	1.34
	117.	20	17	0.21
	118.	20	21	5.71
	119.	20	27	1.47
	120.	20	31	1 48
	121.	20	33	0.84
	122.	20	35	5.70
	123.	20	37	2 23
	124.	20	41	3.68
	125.	20	43	2.49
	126.	20	63	1.58
	127.	20	72	2.97
	128.	20	88	1.21
	129.	20	99	0 65
	130.	20	100	0.47
	131.	20	101	0.46
	132.	20	102	1 59
	133.	20	105	0.33
	134.	20	107	0.40
	135.	20	109	0.50
	136.	20	110	1.20
	137.	20	121	1.34
	138.	20	123	3.78
	139.	20	124	2.40
	140.	20	129	1.96
	141.	20	132	2.15
	142.	20	136	4.32
	143.	20	140	5.84
	144.	20	141	1.10
	145.	20	144	7.45
	146.	20	148	2.61
	147.	20	160	2.50
	148.	20	162	2.56
	149.	20	163	4.12
	150.	20	[illegible]	11.55
	151.	20	168	6 30
	152	20	172	2.55
	153.	20	184	2.92
	154.	20	191	1.27
	155.	20	199	1.09
	156.	20	203	2.49
	157.	20	210	0.58
	158.	20	215	3.50
	159.	20	220	3.11
	160.	20	221	2.58
	161.	20	222	4.01
	162.	20	225	2.54
	163.	20	227	7 06
	164.	20	228	6.16
	165.	20	229	2.38
	166.	20	230	2.29
	167.	20	242	4.55
	168.	20	121/248	0.29
	169.	20	26	0.19
	170.	20	97	0.27
	171.	20	157	1 09
	172.	20	232	0.80
	173.	20	233	0.52
	174.	20	236	2.06
	175.	20	237	0.56
	176.	20	240	0.40
	177.	20	244	1.06
	173.	20	245	0.21
	179.	20	246	2.40

VILLAGE : DUMURIGUDA P.S. SEMILIGUDA
DIST. KORAPUT

Serial No.	Khata No.	Plot No.	Area (acres)
1	2	3	4	5
1.	1	4	0 03
2.	2	87	0.70
3.	2	27/3	1.03
4	2	10	3.76
5.	2	54	1.84
6.	2	22	1.19
7.	2	24	3.88
8.	2	47	1.46
9.	2	41	0 93
10.	2	23	3.84
11.	3	70	0 36
12.	3	34	1 53
13	3	78	3.91
14.	3	84	0.28
15.	3	5/2	1.53
16.	3	27/1	6.96
17.	3	80/2	0.54
18.	3	80/3	0 53
19.	4	27/4	6 00
20	4	3	3.72
21.	4	5/1	4.19
22.	4	17	17.05
23.	4	64	1.00
24.	4	81	1.63
25.	5	48	0.91
26.	5	72	0.30
27.	5	19	4.41
28.	5	21	2.75
29.	5	28	2.04
30.	5	33	3 35
31.	5	55	3.55
32.	5	71	2.82
33.	5	77	0.30
34.	6	49	0.84
35.	6	31	4.98
36.	6	59	1.30
37.	7	80/1	1.06
38.	7	82	1.36
39.	7	83	2.45
40.	7	13	7.65
41.	8	85	0.92
42.	8	6	1.81
43.	8	15	6.60
44.	8	16	3.09
45.	9	40	0.31
46.	9	2	3.70
47.	9	30	4.39
48.	9	35	1.66
49.	9	45	0 51
50.	9	56	1 81
51.	9	63	2.53
52.	9	27/5	2.65
53	10	76	0.76
54.	10	42	0.65
55.	10	9	1.16
56.	10	29	1.73
57.	10	38	2.25
58.	10	70	1.49
59.	15/1	61	4 06
60.	11	39	1. 0
61.	11	50	
62.	11	14	4 03
63.	11	20	2.82
64.	11	36	0.67
65.	11	37	1.18
66.	11	62	2.14
67.	12	68	0.29
68.	12	73	2.28
69.	12	74	0.91
70.	13	46	0.27
71.	13	8	3.88
72.	13	12	0.86
73.	13	51	1.16
74.	13	52	1.58
75.	13	60	2.87
76.	13	53	2.27
77.	14	44	0.32
78.	14	86	0.77
79.	14	27/2	10.02
80.	14	25	2.98
81.	14	26	2.62
82.	14	54/2	1.26
83.	15	69	1 30

VILLAGE SUGURIGUDA P.S. KORAPUT
DIST. KORAPUT

Serial No.	Khata No.	Plot No.	Area (acres)
1	3	4	5
1.	1	38	1.55
2.	1	118	1.49
3.	1	50	0.18
4.	1	71	3.01
5.	1	100	0.24
6.	1	110	2.29
7.	1	35	2.23
8.	1	39	3.37
9.	1	183	0.62
10.	2	96	0.24
11.	2	101	0.11
12.	2	171	0.21
13.	2	175	0.41
14.	3	25	1.51
15.	3	26	0.08
16.	3	27	2.96
17.	3	29	1.19
18.	3	33	5.11
19.	3	34	3.84
20.	3	54	0.42
21.	3	63	6.25
22.	3	94	0.70
23.	3	121	2.14
24.	3	144	0.23
25.	3	145	5.59
26.	3	187	1.22
27.	3	153	0 96
28.	4	45	0.39
29.	4	178	0 89
30.	4	182	0.42
31.	4	188	1.00
32.	4	189	0.39

1	2	3	4	5
	33.	4	184	1.88
	34.	5	2	0.79
	35.	5	8	1.57
	36.	8	12	4.47
	37.	5	88	0.15
	38.	5	89	4.33
	39.	5	90	5.02
	40.	5	114	0.88
	41.	5	125	6.92
	42.	5	126	1.69
	43.	5	127	0.89
	44.	5	131	0.24
	45.	5	134	1.90
	46.	5	152	1.39
	47.	5	156	0.08
	48.	5	161	0.15
	48.	5	166	0.60
	59.	5	135/195	0.64
	51.	5	138	2.48
	52.	5	112/200	2.89
	53.	5	139	6.03
	54.	5	159	0.12
	55.	5	168	0.60
	56.	5	4	1.56
	57.	5	73	2.31
	58.	5	75	4.11
	59.	5	149	1.13
	60.	5	157	0.11
	61.	5	162	0.14
	62.	5	6	1.09
	63.	5	20	2.47
	64.	5	22	2.13
	65.	5	30	1.46
	66.	5	31	2.41
	67.	5	68	2.22
	68.	5	76	1.32
	69.	5	140	1.20
	70.	5	141	1.44
	71.	5	150	0.19
	72.	5	154	0.20
	73.	5	164	0.32
	74.	5	165	0.19
	75.	5	169	0.42
	76.	6	43	0.86
	77.	6	44	0.35
	78.	6	130	1.79
	79.	6	174	1.20
	89.	6	92	0.78
	80.	6	129	0.62
	82.	6	91	1.09
	83.	6	153	0.32
	84.	7	21	4.67
	85.	7	59	1.69
	86.	7	77	1.12
	87.	7	97	0.13
	88.	7	99	0.15
	89.	7	101	0.12
	90.	7	113	0.88
	91.	7	119	0.47
	92.	7	123	1.72
	93.	7	142	1.49
	94	7	40	2.01
	95	7	83	2.17
	96.	7	60	1.25
	97.	8	102	0.59
	98.	9	132	0.61
	99.	10	5	0.97
	100.	10	13	2.39
	101.	10	16	0.84
	102.	10	32	0.80
	103.	10	52	0.41
	104.	10	56	0.19
	105.	10	65	0.94
	106.	10	93	0.29
	107.	11	179	0.31
	108.	11	191	0.29
	109.	12	19	1.72
	110.	12	47	0.20
	111.	12	51	0.18
	112.	13	177	0.31
	113.	13	180	0.27
	114.	14	7	4.60
	115.	14	24	3.54
	116.	14	41	5.19
	117.	14	49	0.39
	118.	14	57	0.29
	119.	14	80	2.19
	120.	14	82	1.11
	121.	14	111	2.14
	122.	14	155	0.46
	123.	14	186	1.90
	124.	15	193	0.56
	125.	16	18	0.63
	126.	16	23	0.87
	127.	16	58	0.13
	128.	16	67	1.51
	129.	16	72	1.22
	130.	16	98	0.13
	131.	17	194	0.29
	132.	18	48	0.37
	133.	18	66	2.71
	134.	18	81	2.87
	135.	18	84	1.79
	136.	18	86	2.35
	137.	18	62	2.96
	138.	18	85/195	0.48
	139.	19	172	0.42
	140.	20	1	1.68
	141.	20	15	1.32
	142.	20	28	0.92
	143.	20	37	0.87
	144.	20	55	0.26
	145.	20	95	0.37
	146.	20	108	2.42
	147.	20	109	1.97
	148.	20	170	0.48
	149.	21	181	0.57
	150.	21	192	0.35
	151.	22	10	1.52
	152.	22	146	1.60
	153.	23	3	0.82
	154.	23	11	1.21
	155.	23	160	0.08
	156.	23	135	1.81
	157.	23	151	0.10
	158.	23	116	0.92
	159.	23	176	0.21
	160.	23	197/198	0.49

VILLAGE : POTIASIL P.S. : KORAPUT
DIST. KORAPUT.

1	Serial No. 2	Khata No. 3	Plot No. 4	Area (Acres) 5
	1.	1	142	9.37
	2.	1	145	3.25
	3.	1	149	3.44
	4.	1	150/2	1.52
	5.	2	148	1.81
	6.	3	3	0.74
	7.	3	11	1.44
	8.	3	15	3.10
	9.	3	22	3.24
	10	3	27	1.80
	11.	3	57	0.45
	12.	3	61	0.11
	13.	3	87	2.06
	14.	4	81	0.33
	15.	5	10	2.28
	16.	5	39	0.08
	17.	5	63	0.17
	18.	5	66	4.40
	19.	5	86	0.38
	20.	6	85	0.27
	21.	7	1	1.92
	22.	7	6	4.27
	23.	7	9	5.26
	24.	7	16	4.30
	25.	7	35	0.76
	26.	7	37	4.88
	27.	7	41	0.51
	28.	7	71	0.48
	29.	7	93	1.79
	30.	7	144	4.52
	31	7	36/153	0.97
	32.	8	16/156	1.39
	33.	8	14	2.25
	34.	8	51	1.51
	35.	9	146	1.12
	36.	10	12	0.93
	37.	10	23	0.58
	38.	10	33	0.99
	39.	10	34	0.48
	40.	10	56	0.17
	41.	10	59	0.05
	42.	10	74	0.27
	43.	10	150/1	2.96
	44.	10	108	1.72
	45.	10	89	0.26
	46.	10	112	7.57
	47.	12	2	2.79
	48.	12	17	3.07
	49.	12	19	5.25
	50	12	38	0.19
	51.	12	40	0.35
	52.	12	44	1.30
	53	12	50	0.44
	54.	13	49	0.33
	55.	13	77	0.23
	56.	14	111	2.07
	57.	14	113	1.51
	58.	14	114	1.76
	59.	14	124	6.65
	60.	14	125	1.27
	61.	14	132	4.40
	62.	14	134	1.57
	63.	15	120	0.60
	64.	15	126	0.98
	65.	15	26	1.27
	66.	15	30	5.41
	67.	15	60	0.09
	68.	15	65	2.98
	69.	15	68	0.39
	70.	17	52	0.22
	71.	17	78	0.21
	72.	18	151/1	1.14
	73.	19	4	0.60
	74.	19	21	0.44
	75.	19	25	0.77
	76.	19	64	0.21
	77.	19	72	1.28
	78.	19	75	0.91
	79.	19	91	1.81
	80.	19	119	0.18
	81.	19	137	1.86
	82.	19	116	0.34
	83.	20	98	1.19
	84.	20	92	1.88
	85.	20	97	1.65
	86.	20	99	4.84
	87.	20	101	2.17
	88.	20	102	1.30
	89.	20	106	6.17
	90.	20	138	2.75
	91.	20	139/2	2.59
	92.	21	129	0.48
	93.	21	151/2	1.37
	94.	21	152	1.96
	95.	22	103	6.98
	96.	22	104	5.83
	97.	22	133	1.92
	98.	22	130	3.39
	99.	22	131	5.98
	100.	23	32	1.36
	101.	23	58	0.18
	102.	23	110	2.71
	103.	23	115	0.35
	104.	24	46	0.66
	105.	24	83	0.12
	106.	25	62	0.08
	107.	25	69	5.50
	108.	26	88	0.17
	109.	26	82	0.34
	110.	27	28	2.65
	111.	27	29	3.33
	112.	27	43	0.43
	113.	27	54	1.57
	114.	27	70	2.65
	115.	27	95	7.10
	116.	27	31	1.56
	117.	27	55	1.18
	118.	27	67	0.50
	119.	27	76	1.64
	120.	27	94	4.39
	121.	27	109	5.72
	122.	27	7	4.81
	123.	27	42	0 20
	124.	28	48	0 33
	125.	28	117	0.19
	126.	28	47	0 31
	127.	28	80	0.13

Village :Chhagan Tahsil;Nandapur (Potting) Dist : Koraput Koraput

Serial No.	Khata No.	Plot No.	Area 0(acres)	Boundary
1	2	3	4 5	6
1.	7	198	1.32	N–Suigo Khora S–Siba Khora
2.		167	0.16	N–Siba Muduli S–Khalpadi
3.	12	206	1.15	N–Siba Khora S–Kupuli
4.		138	0.29	N–Kupuli S–Tibo Damba
5.	14	131	7.73	N–Potita S–Kupuli
6.		145	0.77	N–Nadi S–Self
7.		144	4.79	N–Mulia Muduli S–Sadasiba Dora
8.	14	135	9 37	N–Self S–Kupuli
9.	15	166	2.88	N–Kupuli S–Khalpadi
10.	20	178	8.21	N–Pani Nala S–Dhania Naik
11.		200	1.66	N–Self S–Self
12.		201	3 16	N–Self S–Sadasiba Khora
13.		137	0.40	N–Ghasi Pangi S–Self
14.	21	168	0.30	N–Jadu Pangi S–Gonia Dhonia
15.	23	205	2.77	N–Siba Khora S–Pahada
16.	32	173	3.60	N–Jibu Dhonu S–Dhabulu Paraja
17.	33	208	1.00	N–Sada Khora S–Kupuli
18.	38	141	0.64	N–Kupuli S–Patita
19.	41	186	0 33	N–Jhola S–Samora Naik
20.	42	214	0.80	N–Basti S–Self
21.		215	3 90	N–Sadasiba Khora S–Sukura Khilo Budu
22.		156	1 52	N–Samara Naik S–Self
23.		161	6 00	N–Self S–Kupuli
24.	45	126	0.13	N–Nadi S–Self
25.		127	0.11	N–Self S–Self
26.		128	5 52	N–Rever S–Pahada
27.	56	190	0.54	N–Self S–Siba Khora
28.		148	4.37	N–Self S–Samara Naik
29.	56	146	7.11	N–Samara Naik S–Self
30.	66	183	3.28	N–Siba Khora S–Pani Nala
31.		179	1.22	N–Self S–Kupuli
32.		189	0 52	N–Sibakhora S–Pani Nala
33.		194	0 50	N–Self S–Siba Khora
34.		199	1.38	N–Self S–Tibu Dambo
35.		152	5.90	N–Nadi S–Budu Dambo
36.		139	2.73	N–Kupuli S–Sadasiba Khora
37.		155	2 98	N–Self S–Self
38.		142	3.62	N–Pahada S–Govt. land
39.		147	0.10	N–Self S–Mulia Muduli
40.		181	6.43	N–Siba Khora S–Tibu Dambo
41.		149	1.60	N–Mulia Muduli S–Budu Dombo
42.		150	0.55	N–Self S–Mulia Muduli
43.		151	1.74	N–Naidi S–Self
44.		162	4.66	N–Self S–Sukura Jani
45.		154	0 06	N–Pahada S–Bisu Jadaba
46.	67	177	0.15	N–Sukura Khinibadi S–Sukura Khinibadi
47.		207	1.22	N–Self S–Kupuli
48.		143	6.51	N–Chandal Gouda S–Jholla
49.		202	1.37	N–Tibu Dambo S–Self
50.		184	1.08	N–Self S–Badul Dambo
51.	67	185	8.64	N–Paida S–Guruma Khora
52.		188	2 61	N–Self S–Patia S–Patia
53.		160	3.20	N–Budu Dambo S–Samara Naik
54.		192	2.82	N–Self S–Nadibeda
55.		196	0.72	N–Patita S–Gunia Dhoria
56.		204	2.47	N–Patita S–Ghasi Parjia
57.		132	0 44	N–Nadi S–Pahada
58.		133	0.33	N–Nadi S–Self
59.	72	172	0.94	N–Kupuli S–Kupuli
60.	76	180	2.15	N–Kupuli S–Kupuli

1	2	3	4	5
61.		164	2 60	N-Samara Naik S-Jadu Paraja
62.		209	0 49	N-Dhabulu Paraja S-Kupuli
63.		212	0.26	N-Siba Khora S-Patria
64		176	1.14	N-Siba Khora S-Kupuli
65.		216	0 13	N-Budu Dambo S-Siba Khora
66.	180	210	0 34	Bijastali

[F. No 8/37/81-Met IV]

J A. CHOWDHURY, Director

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1982

का० आ० 289—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा से जलन्धर (पंजाब) तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों का बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा जलन्धर पाईप लाईन प्रोजेक्ट 2008/4, अर्बनइस्टेट गुडगांव (हरियाणा) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तहसील पानीपत जिला करनाल राज्य हरियाणा

नाम ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल हे० ए०		वर्गमी०	क्षेत्रफल जो पूर्व प्रकाशित हो चुका है।
1	2	3	4	5	6
मेहराना	25/7 मिन	0	10	37	009 36
ह०नं० 29	25/14 मिन	0	08	35	00 203
	25/17 मिन	0	06	82	
	25/24 मिन	0	02	53	
	31/12 मिन	0	12	14	00 531
	92/1/3 मिन	0	09	11	
पानीपत	5609/1690 मिन	0	14	67	
तरफ इन्सार	5610/1691 मिन	0	06	07	
ह न०12	5615/1692 मिन	0	04	81	
	1721 मिन	0	00	25	
	1722 मिन	0	02	53	

[क्रमांक 0-12016/63/82 - प्रो०]

MINISTRY OF ENERGY

(Deptt. of Petroleum)

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 289.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from Mathura in Uttar Pradesh to Jullundur in Punjab pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Mathura-Jullundur Pipeline, 2008/4 Urban Estate, Gurgaon-122001 (Haryana).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Tehsil : Panipat District : Karnal State Haryana

Name of village	Khasra No.	Area H	A	Sq. M.	Area already Notified.		
1	2	3	4	5	6		
Mehrana	25/7 Min	0	10	37	0	09	36
H No. 29	25/14 Min	0	08	35	0	02	02
	25/17 Min	0	06	82			
	25/24 Min	0	02	53			
	31/12 Min	0	12	14	0	05	31
	92/1/3 Min	0	09	11			
Panipat	5609/1690 Min	0	14	67			
Taraf	5610/1691 Min	0	06	07			
Insar	5615/1692 Min	0	04	81			
	1721 Min	0	00	25			
	1722 Min	0	02	53			

[No. O-12016/63/82-Prod.]

का० आ० 290—यत पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार (अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50 का) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० नं० 2639 दिनांक 21-7-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : थानेसर	जिला कुरुक्षेत्र		राज्य : हरियाणा	
नाम ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		है०	ऐ०	वर्ग मी०
1	2	3	4	5
मसाना ह० नं० 96	42/16 मिन	0	00	76
	42/25 मिन	0	06	58
	51/5 मिन	0	10	12
	51/6 मिन	0	10	12
	51/15 मिन	0	10	12
	52/21 मिन	0	00	25
	55/1 मिन	0	04	05
	55/10 मिन	0	09	11

[संख्या के-12020/6/82-प्रो०)

S.O. 290.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 2639 dated 24-7-1982 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And Further : in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Thanesar	Distt : Kurukshetra	State : Haryana		
Name of Village,	Khesra No.	H.	A.	Sq.M.
1	2	3	4	5
MASANA H. No. 96	42/16 Min	0	00	76
	42/25 Min	0	06	58
	51/5 Min	0	10	12
	51/6 Min	0	10	12
	51/15 Min	0	10	12
	52/21 Min	0	00	25
	55/1 Min	0	04	05
	55/10 Min	0	09	11

[No. O-12020/6/82-Prod]

का०आ० 291.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962, का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 57, दिनांक 3-1-1981 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तहसील पानीपत	जिला : करनाल	राज्य : हरियाणा		
नाम ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		है०	ऐ० वर्ग	मी०
पानीपत तरफ इंसार ह० नं० 12	2374 मिन०	0	00	51
	2375 "	0	02	02
	2376 "	0	01	26
	2378 "	0	02	53

[सं० O-12020/19/80-प्रो०]

एल० एम० गोयल, निदेशक

S.O. 291.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (Department of Petroleum) S. O. No. 57, dated the 3rd January, 1981, under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after condering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil: Panipat	District: Karnal	State: Haryana		
Name of Village	Khasra No.	Area		
		H	A	Sq.M.
Panipat Taraf Insar				
H. No. 12	2374 Min	0	00	51
	2375 Min	0	02	02
	2376 Min	0	01	2
	2378 Min	0	02	53

[No. O-12020/19/80-Prod.]
L.M. Goyal, Director

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1982

का० आ० 292.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 3 मई, 1980 मे प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1250, तारीख 18 अप्रैल, 1980 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र मे 4950.00 एकड़ (लगभग) या 2003.17 हैक्टर (लगभग) भूमि मे कोयला का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और उपरोक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना नही दी गई है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 3 मई, 1982 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप मे विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि मे या उस पर किन्हीं अधिकारों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

रेखांक सं० रा० 85/79
ता : 24-11-79

अनुसूची

मकोनिया ब्लाक
डालटनगंज कोयला क्षेत्र
पलामू (बिहार)

क्रम सं०	ग्राम का नाम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्रफल टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	सरैया	पाटन	180	पलामू	भाग
2.	सांडा	"	186	"	"
3.	नौडीहा	"	187	"	"
4.	हुरहुसा	"	188	"	"
5.	गोलहना	"	189	"	"
6.	बिजरा	"	190	"	पूर्ण
7.	सखुआ	"	191	"	भाग
8.	मनू	"	192	"	पूर्ण
9	पलहे खुर्द	पाटन	193	पलामू	पूर्ण
10	सीका	"	194	"	भाग
11.	गरेरिया	"	195	"	"
12.	लोहौरा	"	199	"	"
13	गारीखास	"	200	"	"
14.	कठौतिया	"	201	"	पूर्ण
15.	कजरी	"	202	"	भाग
16.	बनसारा	"	203	"	"

कुल क्षेत्र 4950.00 एकड़ (लगभग)
या 2003.17 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा गारीखास ग्राम में रेल लाइन की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है।

ख-ग रेखा कजरी ग्राम में सड़क की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है।

ग-घ रेखा कजरी, बनसारा, सखुआ और गोलहना ग्रामों में से होकर जाती है।

घ-ङ रेखा गोलहना, हुरहुसा, और नौडीहा ग्रामों में नाले के दाहिने किनारे के भाग के साथ साथ जाती है।

ङ-च रेखा नौडीहा सांडा में से होकर पलहे खुर्द और गोमहेठाई ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ साथ पलहे खुर्द और सरैया ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है।

च-छ-ज रेखा सरैया ग्राम में से होकर जाती है।

ज-झ रेखा पलहे खुर्द और सरैया ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ सीका और गररिया डीह ग्रामों से होकर जाती है।

झ-क रेखा गडरिया डीह, लोहौरा ग्रामों में से होकर [जो कोयला अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन पहले से अधिसूचित लोहरी ब्लाक की आंशिक सामान्य सीमा भी है] फिर गारी खास और पंडवा ग्रामो की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा० सं० 19/6/82-सी०एल०]
पी० सरकार, निदेशक

(Department of Coal)

New Delhi, the 14th October, 1982

S.O. 292.—Whereas by the notification of the Government of India, in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal), No. S.O. 1250, dated the 18th April, 1980, Published in the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-section (ii) dated the 3rd May, 1980, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Deveopment) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 4950.00 acres (approximately) or 2003.17 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule annexed to that Notification;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section, 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 3rd, May, 1982, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

Drg. No. Rev/85/79 dated 24-11-79

Schedule

Kathautia Block

Daltanganj Coalfield

Palamau (Bihar)

Sl. No.	Name of Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Saraiya	Patan	180	Palamau		Part
2.	Sanda	,,	186	,,		,,
3.	Naudiha	,,	187	,,		,,
4.	Huruhansa	,,	188	,,		,,
5.	Golhana	,,	189	,,		,,
6.	Bijra	,,	190	,,		Full
7.	Sakhua	,,	191	,,		Part
8.	Sakhu	,,	192	,,		Full
9.	Palhe Khurd	,,	193	,,		,,
10.	Sika	,,	194	,,		Part
11.	Gareriadih	,,	195	,,		,,
12.	Lohanxa	,,	199	,,		,,
13.	Garikhas	,,	200	,,		,,
14.	Kathautia	,,	201	,,		Full
15.	Kajri	,,	202	,,		Part
16.	Batsara	,,	203	,,		,,

Total area : 4950.00 acres (approximately)
or 2003.17 hectares (approximately)

Boundary Description :

A-B line passes along the eastern boundary of Railway line in village Garikhas .

B-C line passes along the eastern boundary of road in village Kajri.

C-D line passes through villages Kajri, Batsara, Sakhua and Golhana.

D-E line passes along the part right bank of Jinjoi Nala in villages Golhana, Huruhansa and Naudiha.

E-F line passes through villages Naudhia, Sanda along common boundary of villages Palhe Khurd and Gomhethai along part common boundary of villages Palhe Khurd and Saraiya.

F-GH line passes through village Saraiya.

H-I line passes along part common boundary of villages Palheckhurd and Saraiya through villages Sika and Gareriadhi,

I-A line passes through villages Gareriadih Lohanra (which is also part common boundary of Lohri Block already notified u/s 4(1) of the Coal Act) then along part common boundary of villages Garikhas and Pandwa and meets at starting point 'A'.

[No. 19/6/82-CL.]

P. SARKAR, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1982

का० आ० 293.—यत: दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 16) की धारा 3 के खण्ड (घ) के अनुसरण में इन्दौर विश्वविद्यालय परिषद के सदस्यों ने डा० वाई० एन० सक्सेना, लेक्चरार, दंत चिकित्सा कालेज, इन्दौर को 29 मार्च, 1982 से डा० ए० के० दास के स्थान पर भारतीय दन्त परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 9 फरवरी, 1978 की अधिसूचना सं० का० आ० 533 में पुन: प्रकाशित भारत सरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 12 अप्रैल, 1949 की अधिसूचना संख्या 10-10/48-एम०-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 12 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12. डा० वाई० एन० सक्सेना, लेक्चरार, दंत चिकित्सा कालेज, इन्दौर।	इन्दौर विश्वविद्यालय 29-3-1982"

[संख्या वी०-12013/4/82-पी० एम० एस०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 27th November, 1982

S.O. 293.—Whereas in pursuance of clause (d) of section 3 of The Dentists Act, 1948 (Act 16 of 1948) Dr. Y. N. Saxena, Lecturer, Colege of Dentistry, Indore, has been elected to be a member of the Dental Council of India by the members of the Council of University of Indore in place Dr. A. K. Dass with effect from 29-3-1982.

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Govrnment hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 10-10/48-MI, dated the 12th April, 1949, as republished by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 533, dated the 9th February, 1978, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (d) of section 3", for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"12. Dr. Y. N. Saxena,
Lecturer,
College of Dentistry,
Indore.
Indore University 29-3-82."

[No. V. 12013|4|82-PMS]

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1982

का० आ० 294.—संविधान के अनुच्छेद 306 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1965 में आगे और परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे।

2. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती, नियम, 1965 के :—

(क) पहले और दूसरे नियम में आग शब्द और अक्षर और समूह "घ" निकाल दिये जाएं।

(ख) अनुसूची में क्रम संख्या 17 से 38 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों को निकाल दिया जाए।

[सं० ए० 12018/2/79-जी०]
एस० पी० पाठक, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 1982

S.O. 294.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Research Institute, Kasauli (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Research Institute, Kasauli (Group C and Group D posts) Recruitments Rules, 1965,—

(a) the words and letter "and Group D" occuring in rule 1 and rule 2 shall be ommitted;

(b) in the Schedule, serial numbers 17 to 38 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. A. 12018/2/79-G.]
S. P. PATHAK, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1982

का० आ० 295.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार के परामर्श से डा० एस० आर० मेहता, प्रोफेसर, एवं अध्यक्ष, काय-चिकित्सा विभाग, एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर को डा० जी० सी० शर्मा के स्थान पर भारतीय आयुर्विज्ञानन परिषद का (इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से) सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं० का० आ० 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात

उक्त अधिसूचना में धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मनोनीत "शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"4. डा० एस० आर० मेहता,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, काय-चिकित्सा विभाग
एस० एम० एस० मेडिकल कालेज,
जयपुर।"

[संख्या वी० 11013/13/82-एम० ई० (पी०)]

New Delhi, the 17th December, 1982

S.O. 295.—Whereas the Central Government in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1965 (102 of 1956), in consultation with the Government of Rajasthan, have nominated Dr. S. R. Mehta, Professor and Head of Department of medicine, SMS Medical College, Jaipur, to be a member of the Medical Council of India vice Dr. G. C. Sharma (with effect from the date of publication of this notification).

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"4. Dr. S. R. Mehta,
Professor and Head of the Department
of Medicine, S.M.S. Medical College,
Jaipur."

[No. V-11013/13/82-M.E. (Policy)]

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1982

का० आ० 296.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) उपबंध का पालन करते हुए शिवाजी विश्वविद्यालय की सीनेट ने 30 अक्तूबर, 1982 को हुई अपनी बैठक में डा० डी० के० गोसावी को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय, की 9 जनवरी, 1930 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-मए-1 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की "धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम

संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"डा० डी० के० गोसावी,
अश्विनी प्रसाद अस्पताल,
मिरज, जिला सांगली,
महाराष्ट्र ।

[सं० वी० 11013/15/82-एम० ई० (पी०)]
रविन्द्रनाथ तिवारी, उप सचिव

New Delhi, the 16th December, 1982

S.O. 296.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. D. K. Gosavi has been elected by the Senate of Shivaji University to be a member of the Medical Council of India, in its meeting held on 30th October, 1982.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", for serial number 32 and entries relating theerto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"32. Dr. D. K. Gosavi,
Ashvini Prasad Hospital,
Miraj, District Shangli,
Maharashtra."

[No. V 11013/15/82 ME(P)]
R. N. TEWARI, Dy. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का० आ० 297—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम, 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के निम्नलिखित कार्यालयों को अधिसूचित करती है, जिनके कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :—

(1) इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, 34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

(2) कृषक भारती, कोआपरेटिव लिमिटेड, रेडरोज हाउस, 49-50, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

(3) कृषि मूल्य आयोग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

[सं० 3-11/78 हिं० नी०]
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agri & Coopn)

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 297.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), the staff of which have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., 34, Nehru Place, New Delhi-110019.
2. Krishak Bharati Cooperative Ltd., Red Rose House, 49-50, Nehru Place, New Delhi-110019.
3. Agricultural Prices Commission, Shastri Bhavan, New Delhi.

[No. 3 11/78-Hindi Neeti]
R. P. GUPTA, Director
(Official Language)

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1982

का० आ० 298.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय खाद्य निगम, कुरनूल के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अत: केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० बी० रामना रेड्डी होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

भारतीय खाद्य निगम कुरनूल के प्रबन्धतंत्र की श्रीमती वाफया नितार बा० पाकुरमा तथा शेकाभा सफाई कर्मचारियों की जून, 1978 में सेवा की समाप्ति करने तथा तत्पश्चात् उन्हें ठेकेदार के माध्यम से नियोजित करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल०-42011(11)/82-एफ० सी० आई०/डी०-IV (ए०)]
डा० बी० सिवारमन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

New Delhi, the 8th October, 1982

S.O. 298.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Kurnool and the workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10,

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. V. Ramana Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Food Corporation of India, Kurnool in terminating the services of Shrimati Papamma, Silar Bee, Pakuramma and Shekamma, Sweepers, with effect from June, 1978, and thereafter, employing them through a contractor is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[No. L-42011(11)/82-FCI/D. IV(A)]
T. B. SITARAMAN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1982

का० आ० 299.—उत्प्रवास अधिनियम 1922 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एन० आर० पुनि, अनुभाग अधिकारी श्रम मंत्रालय को तेईस दिसम्बर 1982 के पूर्वाह्न से उत्प्रवासी संरक्षी दिल्ली के रूप में नियुक्त करती है।

[डी०-जी० एल० डब्ल्यू० 11017/1/81-ई० एम० आई० जी०]
रमेन्द्र कुमार दास, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd December, 1982

S.O. 299.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1922 (7 of 1922), the Central Government hereby appoints Shri N. R. Puni, Section Officer, Ministry of Labour to be the Protector of Emignants, Delhi with effect from the fore-noon of 13th December,, 1982.

[No. DGLW. 11017(1)/81-EMIG]
R. K. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का० आ० 300—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (4) के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 2270, तारीख 7 जून, 1982 द्वारा सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून, 1982 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि का छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 दिसम्बर, 1982 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० -11017/10/81-डी०-1(ए०)]

New Delhi, the 18th December, 1982

S.O. 300.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest as required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2270 dated the 7th June, 1982 the Security paper mill, Hoshangabad, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 1982

And whereas, the Central Government is of opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 18th December, 1982.

[F. No S-11017/10/81-D-1(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

का० आ० 301—भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 456 तारीख 5 फरवरी 1963 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, मुख्यालय हैदराबाद के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है,

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री रूपेन्द्र प्रसाद सहगल को उक्त गठित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एस० 11020/4/81- डी०-1(ए०)]
एल० के० नारायणन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 301.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarttrs at Hyderabad constituted by the notification of the Gnvernnment of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 456 dated 5th February, 1963;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Rupender Pershad Sehgal as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[F. No. S-11020/4/81-D.I(A)]
T. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 302.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Gondia Branch and their workman, which was received by the Central Government on the 26-11-82.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Justice M. D. Kambli Esqr., Presiding Officer.

Reference No. CGIT-33 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employer—Mr. A. A. Khan, Officer-in-Charge Disciplinary Cell.

For the workman—Mr. S. P Chaudharv, Vice President, State Bank Workers' Organisation.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharastra CAMP . Nagpur.

Nagpur, dated the 20th day of October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-12012/13/81-D. II(A) dated 19th December, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of subsection (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, and their workman in respect of the matters mentioned in the schedule given below :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India, Gondia Branch in terminating the services of Shri A. A. Hirani, Clerk, with effect from 9-9-1972 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. The workman A. A. Hirani was employed by the State Bank of India (hereinafter referred to as the "Bank") at its Gondia Branch on 18-11-1971 as a Clerk. The appointment order of that date was issued for a period of one month and by a further order dated 19-12-1971 the period of employment was extended upto 31-12-1971. Even thereafter the workman was given breaks and was asked to work for an intermittent period without any regular orders of appointment or termination. Lastly, he worked from 29-8-1972 to 9-9-1972. For this period also there was no order of appointment or termination.

3. The case of State Bank Workers' Organisation (hereinafter referred to as the "Organisation") which represent the workman is that Hirani was employed in a permanent vacancy in place of one Mr. C. J Pendhari. who was transferred from Gondia to Achalpur branch. It is also alleged that during the period of his employment the workman worked on other permanent counters and that the nature of his work was of a permanent nature. It is alleged that the workman was in continuous service from 18-11-1971 to 9-9-1972, including the interrupted service, which was beyond his control. The period of total employment of the workman, according to the Organisation aggregated to 297 days. During the period of the employment of the workman some more temporary employees were also engaged by the Bank not only at Gondia branch but at other branches also. Many such employees were junior to the workman, but they were continued in supersession of the seniority of the workman. It is pointed out in the statement of claim that on 9-9-1972 Mr. Patel and Mr. Sahasrabuddhe, temporary cashier and clerk respectively at Gondia branch, who were junior to the workman were continued in supersession of seniority of the workman. It was obligatory on the Bank in accordance with paragraph 493 of Sastry Award and paragraph 14.10 of Desai Award read with rule 77 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, to prepare a list of seniority of employees for the purpose of effecting retrenchment. It is alleged in the statement of claim that the Bank did not adhere to the principles of 'last come first go" while the terminating the services of the workman and continuing in employment the workmen junior to him It is therefore alleged that the action of the Bank in terminating the services of the workman with effect from 9-9-1972 is in contravention of the provisions of Section 25-F an 25-G of the Industrial Disputes Act, 1947. It was therefore prayed that this Tribunal be pleased to declare the action dated 9-9-1972 of the Bank in terminating the services of the workman as illegal and to reinstate the workman with back wages.

4. The Bank in its written statement pleaded as follows. not be said that he was employed in a permanent vacancy. His appointment being of a purely temporary nature it could not be said that he was employed in a permanent vacancy. The services of the workman were terminated at intermittent periods as there was no vacancy on which he could be employed. The workman had not put in 240 days of work in a calendar year and that therefore he is not entitled to the benefits provided under Section 25-F of the Industrial Disputes Act. Sarvashri Sahastrabudhe, Patel, D. Y. Wadekar and J. M. Rathod were appointed temporarily; but since all these four persons had completed nine months' temporary service as on 31-12-1973, their names were recommended for special test for permanent absorption. There was no any infringement of any statutory provision in not offering a permanent employment to the workman. For all these reasons, it was pleaded on behalf of the Bank that the workman was not entitled to any relief prayed for.

5. The first question that arises for consideration is whether there is contravention of the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act. It is the case of the workman that he was in continuous service of the Bank from 18-11-1971 to 9-9-1972, including the interrupted service which was beyond his control and not due to any fault on his part. The period of his total employment aggregates to 297 days. It is alleged that the workman therefore entered into the channel of Section 25-F of the Industrial Disputes Act. According to the workman, the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act had not been complied with. The termination of his services is therefore illegal and void.

6. The workman has given a tabulation statement at annexure 'E' to the statement of claim showing the number of days on which he worked from time to time from 18-11-1971 to 9-9-1972. He has shown the numoer of days for which he suffered the breaks. It is contended for the workman that under the provisions in para 522.4 of the Sastry Award an employee in the Bank other than permanent employee or probationer is entitled to 14 days notice for the termination of his services. No such notice was given to the workman when his services were terminated on various occasions. It is, therefore, submitted that when no 14 days notice is given, the break of 14 days or the break of lesser period than 14 days till the next appointment should be added to the days on which the workman actually worked for the purpose of finding out whether there is compliance with the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act. For example, this workman was for the first time appointed on 18-11-1971. His services were terminated on 31-12-1971. Fresh appointment was given to him on 3-1-1972. There was thus a break of two days on 1-1-1972 and 2-1 1972. No notice of 14 days was given before this break was effected. It is argued for the workman that the two days of break should therefore be added to the actual number of days on which the workman worked. If the days of break are thus added to 212 days on which the workman actually worked, he

would be in continuous service for one year. It is submitted that he put in actual work for 212 days and if the days of break without notice which aggregate to 45 days are added to this period the total period of work will come to 257 days. He should therefore be deemed to be in continuous service for a period of one year as per the provisions in Section 25-B of the Industrial Disputes Act.

7. It is contended for the Bank that the notice of 14 days is not necessary if the workman is appointed for a fixed period. It is further contended that the days of break cannot be added to the actual days on which the workman has worked for the purpose of Section 25 B of the Industrial Disputes Act. It was contended for the workman that artificial breaks were given to the workman so as to prevent him from having the benefits of Section 25-F of the Industrial Disputes Act. These breaks were not due to any fault on the part of the workman. The days of break therefore should be added for finding out for what period the workman was in continuous service. Reliance is placed upon the provisions in Section 25-B(1) of the Industrial Disputes Act. However, it is submitted for the Bank that the expression "which is not due to any fault on the part of the workman" governs lock-out or a cession of work affected by the employer. I think, there is some substance in this contention.

8. It does appear that during the period from 18-11-1971 to 9-9-1972 the services of the workman were terminated by giving breaks on atleast five times. Sometimes the breaks were of two or four days. There is much substance in the contention of the workman that these breaks were given in order to deprive the workman of the benefit of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, or similar provisions. It appears that after giving breaks appointment was again made orally on some occasion and the service was also subsequently terminated orally. Even then it would not, in my opinion, be possible to add the days of break to the actual days on which the workman worked for the purpose of finding out whether there is contravention of Section 25-F of the Industrial Disputes Act. Assuming for the sake of argument that before giving a break, notice of 14 days was necessary, the workman may at the most be able to claim wages for the period of notice. It would not, however, in my opinion, be possible to add the days of break to the actual number of days on which the workman worked to find out whether he was in continuous service for one year within the meaning of Section 25-F read with Section 25-B of the Industrial Disputes Act. The workman in this case has actually worked for 212 days only. Technically, therefore, there is no breach of Section 25-F of the Industrial Disputes Act.

9. The next question is whether there is breach of the provisions in Section 25-G of the Industrial Disputes Act. Section 25-G of the Industrial Disputes Act is in the following terms :—

> "25-G. Procedure of retrenchment.—Where any workman in an industrial establishment, who is a citizen of India, is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen in that establishment in the absence of any agreement between the employer and the workman in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category, unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman."

The workman Hirani was first appointed in this Bank for a period of one month on 18-11-1971. Then there were intermittent breaks in his service five times. Lastly, he was appointed under an oral order on 29-8-1972 and his services were terminated by an oral order on 9-9-1972 One Mr. Patel and one Mr. Sahasrabuddhe, temporary cashier and clerk respectively in the same Branch at Gondia, who were junior to him were continued in supersession of his seniority. The workman has stated in his deposition recorded on 19-10-1982 that the two persons were working in the same category and they were not retrenched when his services were terminated on 9-9-1972 There is no cross examination of the workman on this point by the representative of the Bank. In reply to the averment in the statement of claim in this behalf what was stated by the Bank in para 11 of its written statement was :—

> "As already submitted by this workman in reply to the Asstt. Labour Commissioner, Nagpur, vide letter dated 22-10-1980. Sarvashri Sahastrabudhe, Patel and also one D. Y. Wadekar and J. M. Rathod whose names have not been mentioned by the workman were appointed temporarily but since all these four persons had completed 9 months temporary service as on 31-12-1973, their names were recommended for special test for permanent absorption. No grievance could be made by the workman about the absorption of these 4 persons."

This is no reply to the averment of the workman in para 11 of his statement of claim. What is alleged by the workman is that when his services were terminated on 9-9-72 some persons who were junior to him were continued in supersession of his seniority. What is stated in para 11 of the written statement and which is quoted above is that the two persons mentioned by the workman in his statement of claim and two other persons had completed nine months temporary service as on 31-12-1973 and their names were therefore recommended for special test for permanent absorption. It is not denied that these persons were juniors to the workman Hirani. If the workman Hirani would have continued in service upto 31-12-1972 without giving artificial breaks he too could have completed nine months' temporary service on 31-12-73. The Bank has not alleged nor proved that these four employees were not junior to the workman. The order of termination of the workman on 9-9 1972 was oral. It does not give any reasosn for retrenchment of this workman while his juniors were retained in service. Ordinarily, rule of retrenchment in the fields covered by industrial law is "last come, first go" and where other things are equal, this rule has to be followed by the employer in effecting retrenchment of a workman, as it is intended to afford a very healthy safeguard that in the matter of retrenchment the management should commence with the latest recruit. This statutory provision contained in Section 25-G of the Industrial Disputes Act, restricts the employer's common law right to decide which of his emoloyees he should retrench. The management of an establishment has to act fairly to the employees. It is true that for a valid and sufficient reasons an employer may depar from the rule "last come, first go". However, when the rule in question has been departed from the employer has to satisfy the Tribunal that the departure was justified. The employer has to be record the reasons why he followed the course of retrenching a senior employee. If such reasons are not given and proved the Tribunal will be justified in holding that the action of the mangaement was not bonafide. Wherever the rule in queston has not been followed the employer has to satisfy the Industrial Tribunal that the departure was justified Failure to comply with the rule "last come, first go", the reasons for such departure not being recorded would make the retrenchment invalid. It is observed by the Supreme Court in the case of workman of Subong Tea Estate v. Subong Tea Estate (1964 I L L J. p 333) :—

> "Though the right of the management to effect retrenchment cannot normally be questioned, when a dispute arises before an industrial court in regard to the validity of any retrenchment, it would be necessary for industrial adjudication to consider whether the impugned retrenchment was justified for proper reasons"

In the above case the Supreme Court held that as the impugned retrenchment was not shown to have been effected for valid reasons, the concerned workman would be entitled to reinstatement with continuity of service and full back wages.

10. I hold that the termination of the services of the workman in this case on 9-9-1972 under oral orders of the Bank was invalid for violation of the provisions in S 25-G The workman therefore will be entitled to reinstatement with continuity of service I have already pointed out how the services of the workman were terminated between 18-11-1971 to 9-9-1972 by giving him breaks on five occasions, on some of these occasions there were breaks of two days only. The termination of the services and fresh appointments were under oral orders on some occasions.

11. The next question is about the back wages. Normally, I would have granted full back wages. However, it appears that the workman approached the Regional Labour Commissioner late to seek the redressal of his grievance. He approached him on 28-8-1980. His services were terminated on 9-9-1972. It appears that in the mean while he was involved in long correspondence with the Bank. Taking the long lag of time, I think the ends of justice would meet if the workman is given half the back wages only, but with continuity of service.

12. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer
[No. L-12012/13/81-D.II(A)]

New Delhi, the 21st December, 1982

S.O. 303.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur (M.P.) in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Berasia Road, Bhopal and their workmen, which was received by the Central Government on the 16-12-82.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.)
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R) (15) of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank, Berasia Road, Bhopal and their workman Shri S. P. Dubey, Clerk, Raipur represented through the Madhya Pradesh Bank Employees' Association, Parvana Bhavan, Aminpura, Near Shita Mandir, Raipur (M.P.)

APPEARANCES :

For Workmen—Shri L. N. Malhotra, Advocate

For Managemet—Shri P. S. Nair, Advocate

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Raipur (M.P.)

AWARD

Dated: December 7, 1982

By Notification No. L-12012(52)/80-D.IIA dated 2nd April, 1981 and subsequent Corrigendum/Notification dated 19th June, 1981, Government of India in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal, for adjudication :—

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank, Berasia Road, Bhopal is justified in suspending the services of Shri S. P. Dubey, Clerk, Raipur Branch with effect from 2-5-77? If not, to what relief is the worker concerned entitled?"

2. Briefly stated the facts giving rise to this reference are these. Shri S. P. Dubey, hereinafter referred to as the workman, was employed as a Clerk in the Raipur Branch of the Punjab National Bank in 1977. The Bank's management hereinafter referred to as the management, suspended him from service on 2-5-1977 vide Branch Manager's Order dated 2-5-1977. The workman's Union felt that the aforesaid order of suspension was in violation of Clause 19(12)(b) of the Bipartite Settlement and was therefore illegal. A dispute was accordingly raised by the Union before the Assistant Labour Commissioner (Central) Raipur but in the conciliation proceedings before him no settlement could be arrived at. Because of the failure of the conciliation proceedings the Central Government have referred the aforesaid dispute to this Tribunal for adjudication.

1116 GI-82—7

3. The claim of the workman's Union, hereinafter referred to as the Union, is that while the workman was working as a Clerk in the Raipur office the Branch Manager suspended him by the aforesaid order dated 2-5-77. Such a suspension order could not have been passed except with the due compliance of para 19(12)(b) of the Bipartite Settlement according to which a suspension order could be passed only after a charge-sheet was given to the workman if some disciplinary action was proposed or taken against him. Further according to the said para some procedure had to be followed before the suspension order could be issued against any workman. Accordingly on the ground of the alleged non-compliance of the aforesaid provisions of the Bipartite Settlement the suspension order was illegal, void and inoperative. A prayer is accordingly made that from the date of suspension till the workman was reinstated on 13-4-1979 the workman should be allowed full wages and other allowances which otherwise would have been payable to him.

4. The management does not dispute the facts alleged by the workman. It is, however, contended that before the suspension order was issued on 2-5-1977 the Branch Manager had come to know of some serious irregularities allegedly comitted by the workman; that the matter was investigated by the Investigator and when it was found that the Bank had probably suffered substantial losses on account of the acts of omission and commission by the workman a chargesheet was served on 24-3-1977 and that only subsequent to this service of the charge-sheet the workman was suspended on 2-5-1977. It is also alleged that another detailed charge-sheet was served on the workman on 26-8-1978 and that lastly the workman was reinstated after being duly warned for his acts of omission and commission.

5. Rejoinder was filed by the Union in which it is stated that what was served on the workman on 24-3-1977 was only a Memo calling for his comments/remarks on certain matters; that it was not a charge-sheet as contemplated by the foresaid para of the Bipartite Settlement; that without the service of a detailed charge-sheet no order of suspension in term or otherwise could have been passed and that on these grounds the suspension order passed on 2-5-1977 cannot be said to be proper.

6. No rejoinder was filed on behalf of the management.

7. On these rival contentions of both the parties the following issues were framed :—

ISSUES

1. Whether the management of Punjab National Bank was justified in suspending Shri S. P. Dubey with effect from 2-5-1977?

2. To what relief are the parties entitled to?

8. Neither party led any oral evidence in support of its contentions and relied upon documents only which were not disputed.

9. I have considered the pleadings of the parties and the documents relied upon by them. My findings on the aforesaid issues are as under :—

Issue No. 1.—The management of the Punjab National Bank was not justified in suspending Shri S. P. Dubey with effect from 2-5-1977. However, the suspension order dated 2-5-1977 shall be deemed to be effective from 26-8-1978.

Issue No. 2.—In view of the findings on Issue No. 1 the workman is entitled to his full wages and allowances from 2-5-1977 to 26-8-1978 minus the suspension allowance which may have ben paid to him.

Reasons for the above findings :—

10. Issue No. 1.—According to the management Ex. M/2 (Annexure A to the statement of the management dated 24-3-1977 is the first charge-sheet served on the workman as contemplated by para 19(12)(b) of the Bipartite Settlement. A bare reading of this will show that it is not a

chare-sheet served on a workman in respect of any improper or illegal acts of omission and commission committed by him while discharging his duties as an employee of the management. It is a letter addressed to the workman by which he was intimated that the management has observed certain irregularities committed by him in preparing certain schedules, credit vouchers and maintenance of other accounts. It specifies the names of 12 Constituents of the Bank, the accounts of which were said to be irregularly maintained by the workman. By the same letter Branch Manager called upon the workman to submit his comments/remarks within 7 days failing which the management was to take necessary action in the matter.

11. The question is as to whether this letter can be construed as a charge-sheet. In my pinion, it cannot be so construed as contended by the management.

12. Ex. M/2 letter/memo addressed to the workman only brings it to the notice of the workmar that certain irregularities, the details of which are not specified in the memo, have been observed by the management to have been committed by the workman. What those irregularities were and in what manner they were treated as irregular and the necessary details of these alleged irregularities were not specified in this so called charge-sheet Ex. M/2 cannot be said to be a charge-sheet as contemplated by para 19(12)(b) of the Bipartite Settlement. It was precisely for this reason that a detailed charge-sheet Ex. M/3 was subsequently served by the management on 26-8-1978. Though in this detailed charge sheet the management has stated that the charge-sheet was served on the workman on 24-3-1977 and the reply dated 30-3-1977 given by the workman was vague, incomplete and unsatisfactory, but it was this charge-sheet which the management was required to serve upon the workman because the management itself felt that what was served earlier on 24-3-1977 was not what was contemplated by the Bipartite Settlement. In Ex. M/3 the necessary details of the alleged irregularities, malpractices etc. committed by the workman were given. If according to the management a charge-sheet as contemplated by the Bipartite Settlement has already been served on the workman on 24-3-1977 then where was the necessity to serve another charge-sheet on 26-8-1978. In my opinion, therefore, it has to be concluded that the memo/letter dated 24-3-1977 was neither on facts nor in law the charge-sheet served upon the workman and that the charge-sheet both on facts as well as in law was served only on 26-8-1978 on the workman.

13. It is not dispute that the Bipartite Settlement is binding on both he parties The provisions of para 19 (12) (a) & (b) are as under:—

> "19.12(a)—An employee against whom disciplinary action is proposed or likely to be taken shall be given a charge-sheet clearly setting forth the circumstances appearing against him and a date shall be fixed for enquiry, sufficient time being given to him to enable him to prepare and give his explanation so also to produce any evidence that he may wish to tender in his defence. He shall be permitted to appear before the Officer conducting the enquiry to cross examine any witness on whose evidence the charge rests and to examine witness and protuce other evidence in his defence.... "

> "19.12(b).—Pending such enquiry he may be suspended, but if on the conclusion of the enquiry it is decided to take no action against him he shall be deemed to have been on duty and shall be entitled to all the full wages and allowances and to all other privileges for the period of suspension and if some punishment other than dismissal is inflicted the whole or part of the period of suspension may, at the discretion of the management, be treated as on duty with the right to a corresponding portion of the wages, allowance, etc"

14. The aforesaid provisions of para 19(12(b) are relevant in this matter It clearly provides that a suspension order can be passed only pending the enquiry provided by para 19 12(b) as reproduced above. An enquiry cannot be said to be pending unless a proper and regular charge sheet is served on the workman.

15. In this case, as already held above, a charge-sheet both on facts as well as in law was served on the workman only by Ex. M/3 and not by Ex. M/2 dated 24-3-1977. Accordingly a suspension order could not precede. The management could issue a suspension order against a workman either after service of a charge-sheet or along with the charge-sheet itself but not earlier than the service of a charge-sheet. If suspension order has been passed before the service of the charge-sheet it must be treated as violative of the settlement between the parties.

16. Accordingly in the light of the view that I have taken above the suspension order dated 24-3-1977 cannot be treated as legally effective from that date.

17. The next question that arises is as to whether after the service of the charge-sheet the suspension order can be treated as effective. Admittedly the suspension order was issued on 2-5-1977 and the charge-sheet was served on 26-8-1978. Once the management issued the charge-sheet on 26-8-1978 the suspension order can be said to be effective only from that date and not from a date earlier than the service of the charge-sheet. Consequently, once the workman was served with the charge-sheet, the propriety, legality of which has not been challenged in these proceedings the suspension order though issued earlier would become effective from the date of service of the charge-sheet. Accordingly I hold that the suspension order dated 2-5-1977 (Ex.M/4) could be effective form 26-8-1978 for the reasons given above. Issued No 1 is accordingly answered

18. Issue No. 2:—In view of the findings on Issue No. 1 the workman will be entitled to his full wages and allowances from 2-5-1977 till the date on which the detailed charge-sheet dated 26-8-1978 was served upon the workman by the management.

19. The management will accordingly pay him full wages and alowances of the post held by the workman from 2-5-1977 upto 26-8-1978 or upto a later date if the detailed charge-sheet Ex. M/3 was served upon the workman on a later date. This payment shall be inclusive of the suspension alowance paid to the workman during the aforesaid period. In the circumstances of the case there will be no order as to costs Award is made accordingly

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No L-12012(52)/80-D.IIA]

S.O. 304—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Tokyo Limited, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT:

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/41 of 1982

PARTIES:

Employer in relation to the Management of Bank of Tokyo Limited, Bombay.

AND

Their workmen

APPEARANCES:

For the Employer—Shri V. V. Pai, Advocate.

For the Workmen—Shri J. G. Gadkari, Advocate.

INDUSTRY: Banking. STATE: Maharashtra.

Bombay, dated the 2nd December, 1982

AWARD

By their order No. L-12012/95/82-D.II(A) dated 22nd September, 1982 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947;—

"Whether the action of the management of Bank of Tokyo Limited, Bombay in not allowing Shri L. S. Bengera, driver, to report for duty from 10th February, 1982, is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Now the facts as they appear from the statement of claim as well as written statement in reply to the claim statement in brief are that according to the Union who is espousing the cause of the workman Shri L. S. Bengera who was serving with the Bank of Tokyo, on 10th February, 1982 the Driver was orally told by the management not to report for duty any longer. Now the grievance of the Union is that this oral action on the part of the management in inhibiting the Driver from attending the Driver's duty is illegal and he is entitled to relief at the hands of this Tribunal.

3. In reply to this contention it is urged on behalf of the Bank that subsequent to 10th February, 1982 which is the cause of action for which the reference has been made, on 3rd June, 1982 the Bank terminated the services of the concerned workman by paying three months' pay and allowance in lieu of three months' notice and also on payment of retrenchment compensation amounting to Rs. 8000 and odd. It is alleged that because of this termination which according to the Bank was done validly, now the employee cannot be said to be any longer in the service of the Bank. In paragraph 17 it is further stated that as directed by the Assistant Labour Commissioner—Conciliation the Bank did maintain the status-quo by paying the concerned workman all his wages from 1st February, 1982 till the closing hours of 3rd June, 1982 and there is a further averment that pay and allowances equal to three months have been paid on 3rd June, 1982 and further retrenchment compensation had also been paid.

4. Now, if we refer to the cause of the dispute which has been referred for adjudication of the Tribunal, as seen from the reference itself, it is whether the action of the management of Bank of Tokyo Limited, Bombay in not allowing Shri L. S. Bengara Driver, to report for duty from 10th February, 1982 is justified. Now as the alleged facts stand, it seems that the Driver in question was orally told not to report for duty. In all probability might be on realising the error in which the Bank fell at that time by the subsequent notice dated 3rd June, 1982 termination has been brought about Here I am not concerned with whether the subsequent termination is valid or not because it requires another reference. Here there is a clear admission that they have paid the wages to the workman concerned till 3rd June, 1982 thereby meaning, though they do not admit it that the alleged action in not allowing Shri Bengera, Driver not to report for duty from 10th February, 1982 was not justified.

5. The reference has to be decided and the powers of the Tribunal arose for the said purpose from the order of reference itself and if by any subsequent event which cannot be ignored it is found that the reference cannot survive, suitable finding will have to be noted. What was urged on behalf of the workman was that the action of the management dated 10th February, 1982 itself amounted to termination of service. It was further urged that because there was no subsequent order of reinstatement before 3rd June, 1982, if any subsequent action was taken by the management that would be non est and as such shall have to be ignored. In this connection the reference has arisen because of the contention of the Union that the oral direction by the management itself is against the Bipartite Settlement as well as against the provisions of the Industrial Disputes Act. Really speaking we are not called upon to determine whether it was a termination or not. Had it been a termination certainly this question would have been gone into but the management itself having said that the termination occured on 3rd June, 1982, the contention that the termination occured on 10th February, 1982 as tried to be pleaded at one stage would not be entertainable at all. Similarly the question whether the subsequent termination would be non est would not arise for the determination of the present reference as the scope of the present reference is whether the action of the management in not allowing the Driver to report for duty from 10th February, 1982 is justified or not, and if the finding is "not justified" whether the workman is entitled to any relief. Since the alleged action of 10th February, 1982 shall be deemed to have been affected by the notice of termination dated 3rd June, 1982 and since whether relief was permissible namely payment of wages till the workman was deemed to be in service is already given the reference as it stands does not survive. It may be that the said termination may not be liked by the workman or the Union and they may challenge the same but that demand will have no bearing on the present reference the scope of which as it stands is limited and on any subsequent development no finding one way or other on the part of the Tribunal is called for.

6. At this stage my attention is drawn to the attempt made by the Union to refer the issue of termination dated 3rd June, 1982 which has been turned down by the Government. This was done in the context of the present reference. Since I have held that because of the subsequent development the reference does not survive, the question whether the subsequent termination dated 3rd June, 1982 is valid or not would still be open and the parties would be at liberty to vantilate and get redressed the grievance through proper channel.

The reference therefore fails.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-12012/95/82-D.II(A)]

S.O. 305.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the Industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/23 of 1982

PARTIES :

Employer in relation to the Management of Union Bank of India, Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—Shri F. D. Damania, Advocate.

For the workmen—Shri J. G. Gadkari, Advocate.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra.

Bombay, the 1st December, 1982

AWARD

By their order No. L-12011/46/81-D.II(A) dated 26th March, 1982 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 and everything depends upon as to what were the terms and conditions between the Belgaum Bank Ltd. on one side and the Union Bank of India on the other by which the merger and the resultant liability would be governed :—

"Whether the action of the management of Union Bank of India, in relation to its Bombay Branch, in not paying ex-gratia amount in lieu of bonus @ 4 per cent wages together with 12 per cent interest, for the year 1975 to its workmen who were taken over from the Belgaum Bank Limited, after its merger with the Union Bank of India, Bombay with effect from 1st December, 1975 is justified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?"

2. Without referring to the pleadings in detail succinctly it can be said that by virtue of the agreement reached between these two banks the Belgaum Bank was taken over by the Union Bank of India with effect from 1st December, 1975. The employees whose cause is espoused by the Union, were admittedly prior to 1st December, 1975 in the service of the

Belgaum Bank Ltd. Now because of the understanding between the two banks as well as the employees, these employees were deemed to have resigned from the service of the Belgaum Bank Ltd. and entered into fresh service with the Union Bank of India. This has happened on 1st December, 1975. However because of directive from the Reserve Bank of India a question of payment of bonus arose at the rate of 4 per cent and this has given rise to the dispute that to who is liable to discharge the said burden, whether the Belgaum Bank Ltd. with whom they were serving from 1st January, 1975 to 30th November, 1975 or from the Union Bank of India in whose service they entered on 1st December, 1975. The contention of the Union is that it is the Union Bank of 4 per cent and this has given rise to the dispute that to who ther the money comes from the pocket of one bank or another, the only concern being actual payment. It may be mentioned here that the Belgaum Bank has deposited a sum of Rs. 1,70,000 with the State Bank of India, Belgaum on 8th July, 1978 in order to meet out the estimated liability of payment of bonus of their employees. So far as payment by the Belgaum Bank is concerned in view of the deposit the same is clearly assured. However, the Liquidator, who is now looking after the affairs of the said Bank, pleads that despite this deposit, since the entire business income of the Belgaum Bank Ltd. for the period from 1st January, 1975 to 30th November, 1975 was taken over by the Union Bank though the merger occured on 1st December, 1975, the liability to pay bonus dependant upon the income derived shall pass on to the new Bank that is the transferee Bank and would not rest with the first mentioned bank.

3. Before turning to the determination of the issue involved in the matter, since the Union Bank is denying the liability, the grounds on which the same is being denied will have to be taken in order to decide the same. In the first place by their written statement it is stated that the reference is grossly belated and therefore the workmen are not entitled to any relief. It is further alleged that these employees having been treated as fresh recruits with effect from 1st December, 1975, any liability which arose in the said year cannot be passed on to the transferee or assignee Bank. It is further stated that in fact during the year 1975, the Government of India promulgated an ordinance excluding commercial banks from the applicability of Payment of Bonus Act, 1965 and as such legally no bonus is payable to the employees by any of these banks at the same time it is conceded that the Reserve Bank of India by directive had directed the payment of ex-gratia payment in lieu of bonus to the employees who were eligible to the same as defined under Section 2(13) of the Payment of Bonus Act, an amount equivalent to 4 per cent of the wages earned by the workmen in the said year. Since these workmen, it is alleged, joined the Bank namely the Union Bank of India on 1st December, 1975, they having not worked for 30 working days in the accounting year, it is contended that they would not be governed by the requisite circular, working 30 days in a particular year being the condition precedent to become eligible for bonus. They therefore say that the liability if at all there be shall be of Belgaum Bank and not of the successor Bank and therefore the Union Bank should be exempted from the payment of the same. I have already referred to the claim made by the Union and also the request advanced by the Liquidator of as the Bank having gone in liquidation, requiring no fresh reference.

4. On the strength of these pleadings the following issues arise for consideration and my findings thereon are :—

Issues	Findings
1. At the time of transfer whether the entire business income for the period from 1-1-1975 to 30-11-1975 was taken over by the Union Bank of India or only the selected assets as contended by the Bank ?	Entire business income and not seleted assets as contended by the Union Bank.
2. Whether there was to be continuity of service after joining the Union Bank of India as contended by the Union ?	No, but this question pales in insignificance.
3. Or whether the services of the ex-employees of Belgaum Bank Limited was to be fresh service from 1-12-1975	Yes
4. Whether the Belgaum Bank Ltd had deposited a sum of Rs. 1,70,000/-with the State Bank of India to meet the Bank's estimated liability for payment of bonus to their employees, on 8-7-1978 ?	Yes
5. If, yes whether the bonus liability should be met from the said amount ?	No
6. Whether the Union Bank of India can be termed as successor to the Belgaum Bank Ltd.[] ?	Yes, but nothing turns on this.
7. Whether the Union cannot demand bonus because the agreement between the parties is silent on this ground ?	Can demand.
8. If the ex-employees of Belgaum Bank Ltd are recruited as fresh recruits of 1-12-1975, are they entitled for ex-gratia payment by way of bonus for the relevant year even though they did not work for 30 working days during the year 1975 ?	They are entitled and the matter itself revolves not on whether they worked 30 working days or not.
9. Whether the workmen can claim as of right the ex-gratia amount in lieu of bonus ?	Yes
10. If not whether this Court can order payment under the present reference	Yes
11. Whether the calim is grossly belated and therefore cannot be granted ?	No.
12. Who is responsible for payment of ex-gratia amount by way of bonus whether erstwhile Belgaum Bank Ltd or the Liquidators or the Union Bank of India ?	The Union Bank of India and not others.
13. What relief	As per award.
14. What Award	

REASONS

5. Though as a sort of deference alleged delay in making the demand is pleaded in answer to the claim made by the employees, there is no substance in the said averment and it should not detain us for long. The directive of the Reserve Bank of India to pay bonus is dated 27-10-1976 as seen from Ex. 17/M and whereafter the liability seems to have arisen and when the proceedings were started which ultimately resulted in the present reference, the workmen or the Union can never be said to have committed any latches to deprive them of the right to claim bonus. Now the Reserve Bank has cast the responsibility to pay 4% of salary as ex-gratia payment in lieu of bonus for the accounting year 1975 and the ordinance reference to for the year 1975 would be also of no use and since it is a directive from the Reserve Bank, the payment will have to be made, the only question being which Bank is liable to pay. The Reserve Bank of India has laid down ex-gratia payment at the rate of 4% of the salary or wages and has also laid down the minimum as well as the ceilings for the purpose of determination of the liability. It is further stated that this laibility would arise provided that a particular employee has worked in the Bank for not less than 30 working days in the year 1975. The Union Bank contends that these employees being fresh recruits from 1-12-1975, shall not be deemed to have worked for 30 working days or more in the year 1975, having regard that in December there are 31 days

but the working days would be less than 30. There is some force in this argument and though it is tried to be urged on behalf of the employees for determining the working days the holidays cannot be considered, but the test merely does not state that he has worked in the Bank but it is further qualified by saying for not less than 30 working days For this purpose that he might have worked in the bank for a particular number of days since he continues in the service even on the holidays but when reference to 30 working days is made and not merely 30 days, those holidays will have to be excluded and it the matter turns on this clause alone there would not have been any difficulty in discharging the Union Bank from the liability. However, the Liquidator has brought on record at Ex. 2/L, a copy of letter sent by the Manager, Central Accounts of the Union Bank of India addressed to the Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Belgaum Range. Belgaum where certain assertions have been made. It is immaterial whether it is addressed to the Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax or somebody else but since the profit and income was involved the said authority was directly concerned with the income earned in the year 1975 and for that purpose whether income earned by the Belgaum Bank prior to the merger should be considered as also the income of the Union Bank. It was stated in the said letter that the Union Bank has taken over the selected assets and liabilities of the Belgaum Bank Ltd. outstanding and valued as per the audited balance sheet of the said bank as on 31st December, 1974 and further stated that also its entire banking business with all the accounts of income and expenditure for the period from 1st January, 1975 to 30th November, 1975 and the banking business done by the Belgaum Bank Ltd. during this period has been done "on our account and not on its own account".

It is, therefore, evident that the understanding between the two Banks was that for doing the business during the relevant year that is during the year 1975 prior to 1st December, 1975 that is from 1st January, 1975 to 30th November, 1975 the Belgaum Bank Ltd. shall be functioning for and on behalf of the Union Bank of India. Therefore, though the employees of Belgaum Bank continued to be the employees of that bank and though by virtue of the agreement between these two Banks these employees resigned from the Belgaum Bank and joined the new Bank on 1st December, 1975, still the income and business having been taken over from 1st January, 1975, the liability if there be any to pay bonus to the employees shall rest not with the Belgaum Bank but solely with the Union Bank of India from whom the said claim is being claimed. In view of this specific admission and the assertion to an authority who ultimately was to determine the income and business for the said purpose in the year 1975, now the Union Bank of India cannot avoid any payment of bonus at the rates stated by the Reserve Bank of India for the year 1975. In my view the liability rests with the Union Bank of India and not with Belgaum Bank Ltd. which is now gone in liquidation. although during the relevant period 1st January, 1975 to 30th November, 1975 the employees were in the service of the said Bank and though the fresh service started with the Union Bank of India from 1st December, 1975. The payment shall be made therefore by the Union Bank of India as per the directive of the Reserve Bank of India with all the stipulation stated therein.

No order as to costs.

Dated : 6-12-82.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-12011/46/81-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 21st December, 1982

S.O. 306.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benedih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

REFERENCE NO. 13|80

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Benedih Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Nawagarh, Distt. Dhanbad.

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workman—Shri S. Bose, Secretary, R.C.M.S.

INDUSTRY : Coal. STATE : Bihar.

Dated, the 10th December, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them u|s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012|142|79-D.III(A), dated the 3rd March, 1980.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workman of Benedih Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Nawagarh, Distt. Dhanbad that Shri Lalan Choudhury sould be taken back in service with effect from the 8th March, 1976 is justified ? If so, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The case of the workman is that prior to take over of coal mines various nature of jobs in the coal mining industries were done through contractors which continued for some time even after take over of the management of coal mining industry by the Central Government and even after their nationalisation. Thereafter contract system was abolished gradually and persons employed through the contractors were regularised as employees of the respective collieries under the Central Government.

3. It is stated that Benedih Colliery is one of those non-coking coal mines the management of which was taken by the Central Government with effect from 31-1-1973 and it was nationalised with effect from 1-5-1973. The workman concerned Sri Lalan Choudhury was employed in the capacity of Tub Repairing Mazdoor in this colliery through contractor and when the contract system was abolished he and other workmen of the said contractor were absorbed as employees of Bharat Coking Coal Ltd., in the same colliery.

4. It is submitted that the workman concerned after regularisation was performing his duty peacefully and the management never asked him to establish his genuineness or otherwise as a workman of the contractor at the time of his regularisation. But all on a sudden he was stopped from his duties by the Senior Manager,, Benedih Colliery vide his letter dated 6th|8th March '76 mentioning that it had come to the notice of the management that he was an imposter and not a genuine worker. No explanation was ever asked from him nor any chargesheet was issued against him. The concerned workman for this illegal stoppage of work approached the management and thereafter he raised an industrial dispute before the A.L.C. in 1979 and after the conciliation ended in failure the present reference was made. It is submitted that the action of the management is illegal and arbitrary and hence the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages.

5. The management has contested the claim of the concerned workman and the defence is that the workman has no case and the present Reference is not maintainable. It

is, however, stated that prior to take over the tub repairing and tub making jobs were under contract system and this system was abolished in the month of July, 1974. Four persons viz Tulsi Neula, Kedar Nunia Shib Prasad Nunia and Lalal Choudhuary were given employment by the present management after the abolition of the contract system on the consideration that hey were engaged on the job of tub making and repairing under contract system prior to 1974. Accordingly one Lalan Choudhury was appointed by a letter dated 18-7-1974 as a temporary tub repairing mazdoor and he was son of Ramdhani Chaudhary of village Mandra, in the District of Gazipur, but the concerned workman surreptitiously impersonated himself as said Lalan Choudhary and entered into the service through back-door methods with the connivence of some colliery staff. It is stated that the concerned workman is the son of Hiraman Chaudhary of Village Badki Nainjore, District Arra|Bhojpur. It is submitted that as the concerned workman was an inductee and as such he had no right to get employment in the colliery and as his impersonation was established he was stopped from his duties. It is also submitted that the concerned workman is not the same Lalan Choudhary who was appointed by the management and who worked under the contractor and hence he is not entitled to any relief.

6. The point for consideration is as to whether the demand of the concerned workman that he should be taken back in service with effect from 8-3-1976 is justified. If so, to what relief he is entitled.

7. The concerned workman has examined himself as WW-1 and has stated that he worked under the contractor and thereafter he was regularised by the management but he was illegally stopped from service on the basis of a letter issued by the management. According to the management, however, the concerned workman is an imposter and there was another Lalan Choudhary having different parentage and residence who was appointed to work as a tub repairer. Thus the very identity of the concerned workman has been denied on behalf of the management. Ext. W-2 is a letter dated 6th/8th March, 1976 addressed to Lalan Choudary by the Senior Manager, Banedih Colliery informing him that it had come to the notice of the management that he was an imposter and not a genuine worker and therefore he was stopped work with immediate effect. It is not denied that the concerned workman worked as Lalan Choudhary even after nationalisation till his work was stopped. This is also proved from his pay sheet Ext. W-1. It, however, appears that as late as in 1979 an industrial dispute was raised on behalf of the concerned workman though he was stopped service in the year 1976. The union pressed for employment of the concerned workman and a meeting between the management and the representatives of the R.C.M.S., of which the concerned workman claim to be a member was held on 5-8-80. Ext. M-1 is the record notes of the said meeting. Item No 20 of this Agenda relate to the case of the concerned workman Lalan Choudhary. After mutual agreement it was decided that Lalan Choudhary should be allowed to resume his duty provisionally pending enquiry regarding his genuineness. On the basis of this meeting the concerned workman was allowed to resume duty by a letter dated 22-9-80 (Ext. M-2) that is during the pendency of the present Reference In the mean time the enquiry regarding the identity of Lalan Choudhary was given to Shri P. N. Chaturvedi, the Chief Security Officer and along with the said direction the certificate granted to Lalan Choudhary by the Mukhiya was also forwarded. The Chief Security Officer made enquiry into the matter and he reported that the concerned workmen Lalan Choudhary was a resident of village Barki Nainjore, P.S. Berhampur, Dist. Bhojpur and he was son of Hiraman Choudhary and he does not belong to village Mandra, P.S. Sadiabad, Dist. Gazipur (U.P) vide his letter Ext. M-4 dated 13-11-80. Thus it was established after proper enquiry that the concerned workman was a resident of the District of Bhojpur and father's name was Hiraman Choudhary. The concernedworkman has also given his same name and parentage After the said enquiry the Personal Manager reported the matter to the General Manager informing that from the report of the Chief Security Officer it was established that the concerned workman was actually an imposter and as it was decided during the meeting with the union that he should be allowed to continue work till final enquiry is completed hence the matter may be decided as to whether the work of Lalan Choudhary should be stopped or not. The final decision is still pending with the management as the present Reference is pending before this Court.

8. MW-1 is Sri S.P. Singh, Deputy Personnel Manager. He has proved a declaration Ext.M-3 which was filled by four workmen who worked under the contractor and who were regularised as workmen of the colliery after aboition of the contract system. It bears the name of Tulsi Nunia, Kedar Nunia Shib Prashad Nunia and Lalan Choudhary. All the four workmen have put their thumb impression on it. In this declaration form Lalan Choudhary has been shown as son of Ramdhani Choudhary of village Mandra, P.S. Sadiyabad. District Gazipur. According to the management on the basis of this declaration Lalan Choudhary of the District. of Gazipur was appointed and not this workman and as this workman is a resident of Dist. Bhojpur having a different parentage he is not a genuine worker and is an imposter. It is also proved from the report of the Chief Security Officer that he is a resident of Dist. Bhojpur and is son of Hiraman Choudhary. Thus it is proved that the concerned workman is not the same workman who was regularised by the management and who worked under the contractor prior to the abolition of the contract system.. In this view of the matter the concerned workman is not entitled to be taken back in service as claimed by him as he is proved to be an imposter.

9. Thus on consideration of all the evidence on the record, I hold that the concerned workman is not the same Lalan Choudhary who was regularised by the management and as such in law or on facts he is not entitled to any relief.

10. It may however be mentioned that the concerned workman has been given provisional employment by the management and considering the problem of non-employment the management may consider the desirability of continuing him in service if they so like.

11. I give my award accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20012/142/79-D III(A)]

New Delhi, the 22nd December, 1982

S.O. 307.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Godhur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 35 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Godhur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.), Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S Bose, Secretary Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE: Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 14th December, 1982

AWARD

By Order No. L-20012(134)/80-D.III(A) dated the 20th November, 1980 of the Central Government in the Ministry of Labour the following dispute has been referred to this Tribunal for adjudication in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Keeping in view the categorisation done by the management of Bharat Coking Coal Limited in respect of persons doing the same type of jobs in Bararee Coke Plant, whether the demand of the workmen of Godhur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad that Sarvashri Chandrika Dusadh, Ramadhan Koiri, Banharilal Koiri and Kayru Bhuia should be paid Category-V wages is justified ? If so, to what relief are the said workmen entitled ?"

2. The concerned workmen are admittedly permenent employees performing duties in the hard coke ovens in Godhur colliery which was taken over by the Central Government with effect from 17-10-1971 and nationalised with effect from 1-5-1972 when its ownership, management and control vested in M/s. Bharat Coking Coal Limited. Bararee Coke Plant is also vested in M/s. Bharat Coking Coal Limited consequent upon its nationalisation with effect from 1-5-1972.

3. Now it is the case of the concerned workmen that though they are performing three to four different types of jobs the management is paying them wages of lower Category-IV whereas for similar type of job singly done by different persons in Bararee Coke Plant they are paid Category-IV and Category-V rate of wages and thus the concerned workmen are denied their legitimate wages of Category-V though they are performing higher degree of duty than the workmen of Bararee Coke Plant who are paid Category-IV wages. The matter was raised before the management by the Union of the workmen, but, when it could not be resolved, the Union represented the matter before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad, who arranged local inspection regarding the nature of job performed by the concerned workmen and deputed Shri S. N. Pathak, Labour Enforcement Officer (C), Dhanbad who conducted the enquiry on 14-7-79 and submitted his report dated 25-7-79 (Ext. W-1) to the Asstt. Labour Commissioner (C) but in spite of the findings of the Labour Enforcement Officer (C) the management refused to change its stand with the result that the conciliation proceedings ended in failure leading to the present reference by the Central Government for adjudication by this Tribunal. The contention of the concerned workmen, therefore, is that since they are performing duties involving higher degree of responsibility and skill they are entitled to higher rate of wages of Category-V with effect from the date of nationalisation on 1-5-1972.

4. On the other hand the case of the management is that the concerned workmen are operators of machines installed on the surface which are used for crushing coal for feeding into coke ovens. The power requirement of such machines is less than 75 H.P. The operators of machines of 75 H.P. and below have been put in Category-III under Coal Wage Board recommendations, and, therefore, normally the concerned workmen would have been placed in Category-III instead of Category-IV. Keeping in view the recommendations of the Coal Wage Board and National Coal Wage Agreement, applicable to the entire coal industry the operators of crushers and elevators have been fitted either in Category-III or Category-IV at different collieries of M/s. Bharat Coking Coal Limited. In exceptional cases a few drivers of crushers and elevators might have been promoted to Category-V considering their merit and seniority. The Bararee Coke Plant is completely an independent establishment exclusively manufacturing hard coke besides various bye-product. The coke plants of different collieries are however parts and parcels of coal mines and no bye-product is manufactured there. The Bararee Coke Plant had fixed certain wage structures in respect of certain employees which was higher than normally applicable to employees of coke plants of colliery management as the rate of profit in Bararee Coke Plant was more as it was able to produce bye-products also which cannot be done in the coke plants of collieries. Wherever the workmen were getting more, the same had to be protected even after nationalisation but this will not entitle the workmen of other establishment to claim wages beyond that prescribed under the Coal Wage Board recommendations and National Coal Wage Agreement. The contention of the management, therefore, is that the concerned workmen have been properly fixed in Category-IV and they are not entitled to claim Category-V wages.

5. Only one witness has been examined on behalf of the concerned workmen, namely, Ramadhar Koiri (WW-1) who is one of the concerned workmen, and only one document has been exhibited on their behalf, namely, the report dated 25-7-79 (Ext. W-1) of the Labour Enforcement Officer (C), Dhanbad, detailed the job performed by the concerned workmen. On behalf of the management also only one witness, namely, N. Mukherjee (MW-1), Dy. Personnel Manager of Kusunda Area in which Godhur Colliery is situate, has been examined and no document has been exhibited on its behalf.

6. The Labour Enforcement Officer (C), Dhanbad in his report dated 25-9-79 (Ext. W-1) had reported that the concerned workmen do the following work :

"(1) Operation of switch board in switch room for on and off.

(2) Elevator Roller Crusher 30 H.P., starting, greasing, oiling, removal of coal jamming in roller crusher and repairing of broken strap.

(3) Staring Elevator, stopping elevator and oiling. In the gear oiling on the top, coupling motor of 10 h.p. which is fitted on the top is stopped by them in case the coupling bolt is broken to renew or repair. If elevator chain breaks or opened is repaired by them.

(4) Coal grinding crusher of 5 h.p. is being operated by them and also greasing of bearing, repairing of broken strap or removal of coal jamming etc.

In case elevator crusher breakes or free wheel teeth breakes then only Mistry is called to repair or replace as required."

7. The concerned workman, Ramadhar Koiri (WW-1), has stated that he and other concerned workmen operate crusher and elevator machines in Godhur Colliery which are fitted with engine of 30 h.p. and, though fitted with different motors, work simultaneously and automatically by putting on electric switches, and it is their duty to see that the elevators and crushers function properly and if in course of their functioning any belt breaks or snaps it is also their duty to mend the same, and in case some oil is needed in some part of the machine to put oil there, but if there is any break down in the machine then some mistry has to be called. According to him, he and other concerned workmen also operate coal grinding crusher of 50 H.P. He has also stated that the designation of the concerned workmen is Crusher Khalasi.

8. Under Coal Wage Board recommendations, which have been accepted by the Central Government in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by Resolution No. WB-16(5)/666 dated 21st July, 1967, crusher khalasis, whose job description is given as "workmen who stop or start the engine driving the mill or crusher and who help in feeding materials to be crushed or pulverised into the machine" have been placed in Item No. 26 of Category-II (Semi Skilled labour) at page 44 of Vol-II of the Coal Wage Board recommendations. According to the evidence of the concerned workman, Ramadhar Koiri (WW-1), before nationalisation he was in Category-III but after nationalisation M/s. Bharat Coking Coal Ltd. gave him one higher category, namely, Category-IV about 5 to 6 years back and the other concerned workmen are also getting Category-IV wages. Hence the concerned workmen, who are crusher khalasis and who would have ordinarily got Category-II according to Coal Wage Board recommendations, should have no grievance when they have already been given two lifts and have been placed in higher Category-IV by the management.

9. In the present reference the claim of the concerned workmen to get a higher Category-V is based on comparison with the workmen of Bararee Coke Plant doing the same type of jobs as are being done by the concerned workmen

in Godhur Colliery. There is, however, practically no evidence on the record to show that workmen of Bararee Coke Plant doing the same type of job as are being done by the concerned workmen in Godhur Colliery are getting Category-V wages. On this point the evidence of the concerned workman Ramadhar Koiri (WW-1) is that he had not enquired as to the wages of which category the workmen of Bararee Coke Plant are getting and so far as the elevator operators of Bararee Coke Plant are concerned they are getting wages of Category-IV or V about which he is not sure. On the other hand, there is the definite evidence of N. Mukherjee (MW-1), Dy. Personnel Manager, that in Bararee Coke Plant also the workmen who operate crusher, elevators etc. in Coke Plant are placed in Category-IV. Thus, on the evidence on record, it is not possible to hold that the workmen in Bararee Coke Plant who are doing jobs similar to the one done by the concerned workmen in Godhur Colliery have been placed in Category-V so as to sustain the claim of the concerned workmen to get higher Category-V by comparison.

10. In their written statement the concerned workmen have, no doubt, also tried to make out a case that the different types of work enumerated in the report dated 25-7-79 (Ext. W-1) of the Labour Enforcement Officer (C), which the concerned workmen are doing singly are being done in Bararee Coke Plant by different workmen who are paid Category-IV wages, and hence they should get one higher category, namely, Category-V wages; but that is also not substantiated in evidence as it is the evidence of Ramadhar Koiri (WW-1) that he had not enquired as to the wages of which category the aforesaid workmen of Bararee Coke Plant are getting. Therefor, the concerned workmen are not entitled to Category-V wages on that score also.

11. Moreover, there could be no justifiable comparison between Godhur Colliery and Bararee Coke Plant as Ramadhar Koiri (WW-1) has admitted in his cross-examination the case of the management that in coke oven of Godhur Colliery only hard coke is prepared but in Bararee Coke Plant hard coke is prepared besides bye-products, like coal-tar etc., and that Bararee Coke Plant is bigger than the coke plant of Godhur Colliery. There could be a comparison between the operators of crushers and elevators in coke plant of Godhur Colliery and operators of crushers and elevators of coke plants of other collieries of M/s. Bharat Coking Coal Limited, but the evidence of N. Mukherjee (MW-1), who is presently working as Dy. Personnel Manager in Kusunda Area in which Godhur Colliery is situate and was formerly working as Dy. Personnel Manager in Kustore Area, is that M/s. Bharat Coking Coal Ltd. have got coke plants in different areas of Kusunda Area as well as Kusture Area and the workmen who work as operators of crushers and elevators in those coke plants are in Category-III or Category-IV, and this has not been challenged in his cross-examination.

12. Moreover, under Sec. 17(1) of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 wherever the workmen were being paid more by the out-going owners before nationalisation of coking coal mines or coke oven plants, that had to be protected even after nationalisation, notwithstanding that it was higher than what has been recommended in the Coal Wage Board recommendations; but the same cannot be a ground for increasing the wages of the same class of workers doing the same type of job in other collieries who have already been placed in a category much higher than the one recommended by the Coal Wage Board and accepted by the Government.

13. In no view of the matter, therefore, the concerned workmen are entitled to Category-V wages. The reference is answered and the award is made accordingly. There will be no order as to cost.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.

[No. L-20012/134/80-D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 18th December, 1982

S.O. 308.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Girmint Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 21 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Girimint Colliery of Messrs Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. M. N. Kar, Advocate.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal

AWARD

By Order No. L-19012(44)/82-D.IV(B), dated 15th June, 1982 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Agent, Girmint Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Charanpur, District Burdwan in superannuating Sri Arjun Bhuiya, Timber Mistry with effect from 1-9-1980 is justified ? If not, to what relief is the workmen entitled ?"

2. In my opinion the reference has to be answered in the affirmative. There are ample evidence on record to show that Arjun Bhuiya was born in the year 1920. It has so been recorded in the B form Register of which the relevant entry is No. 1182, Ext. M-1. This entry bears the LTI of Arjun Bhuiya. In the increment list of the erstwhile company bearing No. 24590 also his year of birth is recorded as 1920, vide Ext. M-2. It appears that a notice dated 28th January, 1980 (Ext. M-3) was issued to him by the management stating that he was to retire with effect from 1st July, 1980. He then raised a dispute regarding his recorded age. Then a Medical Board was constituted to assess his age. He was asked to appear before it on 1st October, 1980 by notice dated September 29, 1980, Ext. M-7. He appeared before the Board on that day in the Area Office, Sripur Area. The Medical Board found his age to be above 60 years. Ext. M-9 which is an office order of Sri S. C. Mallik, Deputy Chief Personnel Officer of Sripur Area dated 12/21 October, 1980 clearly shows it. This office order of Sri Mallik was followed by the office order of the Manager, Ext. M-10 dated 11th November, 1980 and this also shows that the Medical Board had assessed his age to be above 60 years. The matter regarding his age was communicated to him by letter dated 11-11-80.

3. The concerned workman did not turn up for duty from 5th September, 1980. His wages upto 4th September, 1980 had already been paid to him vide Ext. M-11 which is an entry in the wagesheet. The concerned workman retired from service with effect from 11-11-80 when the matter was communicated to him but he was absent from duty from 5th September, 1980. MW-1 Sri S. C. Sahajwani has proved all the aforesaid documents. He was not cross-examined because none appeared on behalf of the workman. He is the Manager of Girimint Colliery and there being nothing against him on record I find no reason to disbelieve him. The documentary evidence above mentioned clearly shows that the workman was rightly retired from service with effect from 11th November, 1980.

4. In view of above, my concluded award is that the action of the Agent, Girimint Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited in superannuating the concerned workman Arjun Bhuiya, a Timber Mistry, with effect from 1st September 1980 (appears to be a mistake for 5-9-80 or 11-11-1980) is justified. It follows that the concerned workman is not entitled to any relief.

Dated, Calcutta,
The 2nd December, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(44)/82-D.IV(B)]

New Delhi, the 22nd December, 1982

S.O. 309.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sodepur Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th December, 1982

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

Reference No. 54 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sodepur Colliery of M/s E C Ltd, PO Sunderchak, Distt Burdwan;

AND

Their Workman

PRESENT :

Mr. Justice M. P Singh, Presiding Officer

APPEARANCES.

On behalf of Employer—Mr. B N. Lala, Advocate with Mr. P. N Goswami, Senior Personal Officer

On behalf of workman—Mr Tarapada Rajwar, an authorised representative

STATE West Bengal INDUSTRY Coal

AWARD

The following dispute was referred to this Tribunal for adjudication by the Government of India, Ministry of Labour, vide Order No L-19012(19)/80-D.IV(B) dated 8th July, 1980

"Whether the action of the management Sodepur Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Sunderchak, District Burdwan in refusing employment to Shri Rampada Majhi Tyndal with effect from 5th March, 1978 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. When the case was called out for hearing, a petition of compromise was filed by both the parties A prayer has been made for an award in terms of the said compromise I have gone through the compromise and I find the terms are reasonable and fair. therefore accept the same and pass an award in terms thereof which will form part of this Award as Annexure "A".

Date, Calcutta,

The 10th December, 1982.

ANNEXURE A

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

In the matter of Reference No. 54 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sodepur Colliery of M/s. E.C. Ltd., P.O. Sundarchak District Burdwan

AND

Their Workman.

JOINT PETITION OF COMPROMISE

Both the parties most respectfully beg to submit as under

1 That the above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal.

2. That the hearing of the above matter has not yet concluded

3 That in the meantime the parties negotiated the matter mutually and have come to a settlement on the following terms.—

(i) That the management shall allow the concerned workman, Shri Rampada Majhi to resume duty in his substantive post of Tyndal within 3 days from the date this settlement is accepted by the Hon'ble Tribunal

(ii) That the period of non-employment of the workman concerned as arising out of this reference and upto the date of his resumption of duty as clause (i) above shall be treated as leave without pay with continuity of service.

(iii) That the concerned workman shall have no claim whatsoever for any back wages arising out of the present dispute for the period of his non-employment as said in para (II) above.

(iv) That the management agrees to pay a sum of Rs. 1000/- (Rupee One Thousand only) to the concerned workman towards his cost for the present proceedings and the said payment will be made within 15 days from the date this settlement is accepted by the Hon'ble Tribunal.

4 Both the parties pray that the Hon'ble Tribunal would be pleased to accept this settlement and pass an award in terms thereof

Dated this the 9th day of December, 1982.

For and on behalf of the Workman.

Sd/-
9-12-82
Authorised Representative of the workman

For and on behalf of the Employers
Paresh Nath Goswami
9-12-82
Senior Personnel Officer
E.C Ltd.
M P SINGH, Presiding Officer.
[No L-19012(19)/80-D IV(B)]

S.O 310.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dishergarh Area of Eastern Coalfields Limited, Borachak House, Post Office Sitarampur, Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 64 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dishergarh Area of ECL, Borachak House, P.O. Sitarampur, Burdwan.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M P. Singh, Presiding Officer

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. S. N. Ram, Deputy Personnel Manager.

On behalf of Workmen—Mr. S. K. Chakraborty, Vice-President of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

Two Telephone Operators, namely, S/Shri Sudip Chattaraj and Tarit Banerjee, working in the establishment of the General Manager's office, Borachak House at Dishergarh Area of ECL raised a dispute with regard to the non-payment of over-time wages to them beyond 39 hours per week. This dispute was sponsored by the Coal Mines Employees Union (briefly the Union). At their instance the Central Government in the Ministry of Labour, by Order No. I-19012(5)/80-D. IV(B) dated 22nd July, 1980 referred the following dispute to this tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Dishergarh Area of Eastern Coalfields Limited, Post Office Sitarampur, District Burdwan in denying the over-time wages beyond 39 hours per week to S/Shri Sudip Chattaraj and Tarit Banerjee, Telephone Operators is justified? If not, what relief are the concerned workmen entitled ?'

2. A preliminary objection has been raised by the management that the reference is invalid and unsustainable inasmuch as neither the concerned workmen nor a substantial section of the workmen of the establishment nor the Trade Union by any resolution of its Executive Committee or by any resolution in any general meeting has espoused the cause of the concerned workmen. It is urged that the union has no following whatsoever from amongst the employees of the Dishergarh Area office which employees about 184 workmen.

3. One witness has been examined on behalf of the Union. He is WW-1, Sudip Chattaraj, one of the two concerned workmen. He has proved the Membership register (Ext W-1) in order to show that he is a member of the said union and his Serial No. is 249. The witness has also filed receipts and counter-foil receipts (Exts W-6, W-7 and W-8) in order to show that annual subscription was paid by the concerned workman. The witness has also filed the resolution of the Executive Committee (Ext W-9) dated 30 September 1979. On the basis of these documents and on the basis of the oral evidence of WW-1 Sudip Chattaraj it is contended that the union has locus standi to espouse the cause of the concerned workmen who are its members.

4. The management, on the other hand, has contended that it has not been proved as to when Sudip Chattaraj became a member of the union, that neither in his evidence he can say it nor there is anything in the membership register to prove it. In my opinion the fact that Sudip Chattaraj is a member of the union is established by the membership register of 1968 (Ext. W-1) I do not see any good reason to disbelieve it. However, there are two broad facts on account of which I think the union has no locus standi to represent the concerned workmen.

5. The first thing to be noticed is that not a single member of the Executive Committee of the aforesaid union has come forward to say that the Executive Committee was authorised by the general body of the workers to represent the cause of the two concerned workmen. The resolution of the Executive Committee (Ext W-9) no doubt shows that the Executive Committee in a meeting decided to support the cause of the concerned workmen on the ground that the General Secretary had been authorised in the general meeting dated 8-4-1979. The General Secretary has not been examined. That is not all. When the competency of the union to represent the concerned workman is challenged it is necessary for the union to produce all the relevant and material evidence in the case in order to show that they have locus standi to represent the concerned workman. The resolution Ext W-9, mentions about the minutes of the meeting of the general body of workers dated 8 April 1979, but that has not been produced. It is by virtue of the resolution of the general body of workmen that the Executive Committee claims that the General Secretary was authorised to represent the two concerned workmen. No paper has been filed by the union to show that the members of the Executive Committee were authorised to take up the cause of the concerned two workmen. From agenda 2 of the Ext W-9 it is clear that it was the General Secretary who reported to take up the cause of two concerned workmen along with other cases and that the General Secretary was authorised in the general meeting dated 8-4-1979 to do so. From the evidence of WW-1 it appears that there were more than 60 members in his union. In absence of the minutes of the meeting of the general body of workers dated 8 April 1979 coupled with the fact that none of the members of the Executive Committee is coming forward to support the case of the concerned workmen, I am inclined to hold that the union lacked representative capacity to represent the two concerned workmen. As per evidence of WW-1 Sudip Chattaraj it seems that three telephone operators were members of the union out of whom the two aforesaid raised the dispute with the management. That is immaterial. In the present case it is not the concerned workmen nor any group of workmen of that establishment who raised the industrial dispute. It is the union which raised the industrial dispute. In such a situation it was necessary for the union to prove that the Executive Committee of the union was duly authorised by a resolution of the general body of the workers to represent the two concerned workmen. That has not been done as stated above. Relying upon the case of Tata Chemicals v. Workmen, 1978 II LLJ 22, it is argued on behalf of the union that even a minor union of workmen of the establishment can validly raise an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947. That decision has no application to the facts of the present case. It may be mentioned that the management has filed before this Tribunal points of argument on preliminary objection but it is not necessary to deal with each and every point mentioned therein as several minor matters have been stated there.

6. For the reasons given above it must be held that the union has no locus standi and it lacks authority to represent the two concerned workmen. If so, it must further be held that there was no industrial dispute which could be referred to this tribunal for adjudication. I accordingly hold that the reference is bad in law and invalid. Hence it will not be right to pass any award in terms of the Schedule to the Reference aforesaid.

Dated, Calcutta,

The 9th December, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-19012(5)/80-IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 24th December, 1982

S.O. 311.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of India Security Press, Nasik Road, Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-12-82.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/38 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the Management of India Security Press, Nasik Road, Maharashtra.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. M. Masurkar, Advocate.

For the Workmen—Shri S. H. Deshpande (workman in person).

INDUSTRY : Security Press. STATE : Maharashtra.

Bombay, the 22nd October, 1982

AWARD

(Dictated in the Open Court)

By their order No. L-42012(53)/79-D.II(B) dated 22-7-1980 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of India Security Press, Nasik Road, Maharashtra, in terminating the services of Shri Sharad Hari Deshpande, Office Peon, vide Office Order No. Adm. 89/M dated the 18-9-1978 is justified and legal ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The nature of dispute itself indicates, it is arising out of the termination of the services of Shri S. H. Deshpade Office peon who was employed by order dated 24-10-1975 and who the contention of the management is, was appointed on probation for two years and the order of appointment itself laid down that it was purely temporary and was liable for termination forthwith without assigning any reason under Rule 5 of the Central Civil Service (Temporary service) Rules, 1965. The plea of the workman however is that he had completed the period of probation for wto years, which period elapsed on 20-10-1977 and therefore say is that he having completed the period of probation for two years, which period deemed to be permanent since the vacancy which was there was an existing vacancy and was not a temporary one. However on 18-9-1978 according to the workman to his surprise his services were terminated forthwith and it was directed that he would be paid a sum equivalent to one months wages in lieu of the period of notice. On receipt of the order, representations were made but all of them were turned down. It is alleged that this order of termination itself amounts to order of termination for misconduct and therefore amounts to retrenchment and since according to the workmen the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act were not followed, the retrenchment is bad in law and the workman is entitled to be reinstated with all reliefs.

3. The management have filed two written statements one at Ex. 8/M and another additional Written statement at Ex. 4/M. Now the contention of the management is that the appointment of the workman was purely on temporary basis and his services were liable to be terminated worthwith without assigning any reason. So far as the contention of the workman that on satisfactory completion of the probation period he shall be deemed to have been confirmed, the management in reply have said the work of the employee was not satisfactory and he was continued in the employment in the hope that he would improve himself but since there was no improvement in the discharge of his duties and the employee being purely a temporary employee, his services were terminated in accordance with the Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules 1965. It is alleged that these special rules which are statutory in character will overrids the provisions of the Industrial Disputes Act or any other law for the time being in force including the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1948 and therefore any termination which was made under those rules cannot be challenged.

4. By additional written statement Ex. 4/M attempt was made to suggest that since the workman was not sponsored by the Employment Exchange the initial appointment itself is bad and cannot be any relationship of employer-employee. It is further contended that on making a misrepresentation that the workman belonged to the category of meritorious sportsman, the services were secured by him and as such when the fraud was detected, there cannot be any relationship of employer-employee on this ground also and if the workman cannot be deemed to be an employee of the Security Press, he cannot claim any relief under the Industrial Disputes Act.

5. On the above pleadings the following issues arise for determination and my findings thereon are:—

ISSUES

	Finding
1. Whether the Security Press establihes that the Workman had secured employment by practising mi-representation or Frand ? If yes, what is its effect on the employer-employee relationship?	No
1(A) Was it incumbent on employee to apply only when sponsored by employment exchange? If yes, whather the appointment was without such sponsoring	
1(B) Whether the appointment or Shri Deshpande was illegal on this count from inception?	No
1(C) Whether the action taken in exercise of the powers under Rule 5 of the Central civil Services (Temporary) Rules 1965 can be a matter for adjudication in a reference under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act?	Yes
2. If yes whether the termination of service of Shri S.H. Deshpande was valid and legal?	No
3. Does it amount to retrenchment?	Yes
4. If yes is it valid and legal without following the procedure an contemplated undersection 25F etc.?	No
5. to what relief the workman is entitled?	As per Award

REASONS

6. It was tried to be established that the workman secured the employment by misrepreentaion of he facts and by fraud and for that purpose dual contentions are raised viz. in the first place since he was not sponsored by the Employment Exchange, the appointment itself is bad and secondly on account of misrepresentation regarding the meritorious sportsmanship, if the management was misled, any order of appointment made is also bad and on this ground there will be no relationship of employer-employee. In this connection my attention has been drawn to the rules regarding the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 (Act No. 31 of 1959) on going through which I find no where that if any appointment is made in contravention of the said Act the appointment becomes illegal. No doubt Section 7 speaks that on such appiontment the employer is liable to be punished but the relationship of employer-employee is not declared to be illegal and therefore it is continued and whether Shri Deshpande was sponsored by the Employment Exchange on that occasion or not, he having served the Security Press almost for more than two years, benefits if otherwise available by his service conditions will have to be extended to him.

7. The application seeking the appointment was read over to me but nowhere I find any misrepresentation on the part of the employee namely his claim to be belonging to the category of meritorious Sportsman and thus securing the service. Therefore the plea that fraud was played or misrepresentation was made to secure the job carries no force.

8. Once we hold accordingly, the only conclusion possible is that the appointment of Shri Deshpande cannot be said to be illegal from the inception. Now it is true that even the statement of claim and the order also speaks that the appointment would be on probation for two years in the first instance and that the appointment was purely on temporary basis. Now the record speaks that he was allowed to complete the period of two years of probation. But what happened subsequently has got material bearing and for that purpose what is pleaded on behalf of the workman is that on completion of the period of probation of two years he shall be deemed to be permanent against which the contention of the employer is that he continued to be a purely temporary employee. Nowhere the management pleaded that even after the completion of the period of two years, since there was no confirmation by an order in writing, the workman continued to be on probation. Had there been such pleading, since a probationer has no right to the post and since the very order of appointment speaks that the services are liable for termination without assigning any reason, the employee would not have been entitled to any relief. It is now a settled law that so far as the provisions of Section 25F are concerned, they are applicable to the employees whether they are permanent or confirmed or temporary. Therefore by merely pleading that the workman continued to be on purely temporary basis, no inference can be drawn that the management wanted to contend that he continued to be on probation till he was confirmed though had there been such pleading there would not have been any difficulty in accepting the same.

9. In order to overcome the difficulties created by Section 25F which enjoins upon the management to follow certain procedure, it was contended that the workman is governed by Central Civil Service (Temporary Service) Rules 1965 and those rules shall have overriding effect and therefore whatever might have been laid down under Section 25F of the Industrial Disputes Act, so far as the workman is concerned he cannot invoke the provisions of Section 25F or such

other provisions of the Industrial Disputes Act. In this connection it is pertinent to note that Section 25J which falls under Chapter VA lays down that the provisions of this Chapter—Section 25F is falling in the very chapter—shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law including Standing Orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 and shall have overriding effect, and on the contrary when the dispute is governed by the Industrial Disputes Act and there being an industry and employee-being a workman, the only question to be determined is whether the provisions of Section 25F have been followed or not. In this connection I may refer to the Judgement of Kerala High Court in the case Bhaskaran Vs. Sub-Divisional Officer, reported in 1982, (II) LLJ, page 248, which deals with all the points raised in this case and ultimately held that the provisions of Sections 25F, 25G and 25H govern the case of the workman in that case and not any other rules.

10. Respectfully following the ratio of the said case and further having found that the plea—that the work-man continued to be on probation is conspicuously absent and further whether temporary or confirmed, the provisions of section 25F being applicable the only question to be determined is whether those provisions have been complied with or not. Since the management wanted to terminate the service purely by way of discharge simpliciter in exercise of the powers, any such termination which is not based on the misconduct, would amount to retrenchment under Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act and in view of the decision of the Supreme Court in L. Robert D Souza Vs. Executive Engineer, Southern Railway and another, reported in 1982, (I), LLJ, 330 and since Section 25F of the Act has not been followed admittedly, the termination has to be declared as bad. Normally the workman would have been entitled to reinstatement but having regard to the fact that services are to be in the Security press and further having regard to the fact that management had lost confidence as is evident from the correspondence produced on record, in my view he shall not be entitled to this relief. The workman shall be entitled to wages. In this connection Shri Deshpande informs that he is gainfully employed from May, 1980. Therefore he shall be entitled to wages from the date of termination till May, 1980 that is 20 months from September, 1978 to the end of April, 1980 at the rate at which he was drawing his wages at the time of his termination. He shall be also entitled to retrenchment compensation for the period of service put in at the rate of 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months under the provisions of Section 25F of the Act. The workman was offered notice pay but he declined to accept it that notice pay also be paid to him.

11. I am also ordering reinstatement because I find that the workman has succeeded on technical ground of absence of the plea that he continues on probation in the absence of order of confirmation. Had there been such a plea there would not have been any difficulty at all in holding that he was still on probation there being no order of confirmation and in that case since he would not have any right to the post vested in him, the service contract would have governed his case, that is his services were liable to be terminated without assigning any reason. However as already observed since there was no such plea the proceeding has taken another course.

Award accordingly.

No order as to costs.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUTNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/38 of 1980

Employers in Relation to the Management of India Security Press, Nasik Road, Maharashtra.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the employers—Shri B. M. Masurkar, Advocate.

For the Workman—Shri S. M. Dharap, Advocate.

INDUSTRY : Security Press. STATE : Maharashtra.

Bombay, the 7th December, 1982

AWARD PART II

(Dictated in the Open Court)

In this connection Award, which is being treated as Part I, was passed on 22-10-1982, which order was reviewed by another order dated 4-11-1982 and the workman was granted chance to lead evidence so far as the nature of employment, the quantum of salary earned and the period of employment which now he has done. While calculating the wages as per Part I Award therefore for the resultant liability of the Security Press to make good the loss, the wages earned by the workman during the period of his employment shall have to be considered.

2. It was however, urged on behalf of the workman by Shri Dharap, learned Advocate that since the new salary which the work was getting or is getting in something less than what he was drawing while in the service of the Press, there was no gain as such and therefore since he cannot be said to be gainfully employed whatever was earned during the course of re-employment cannot be deducted from the wages to which the workman would be entitled in view of the earlier order. Since the term 'gainfully' is used not in the sense of gain or profit or loss but has been used in order to see the amount earned by such subsequent employment meaning thereby whether he has earned anything or not, the contention that the subsequent salary was less than earlier one and there being no gain as such the salary cannot be ordered to be deducted carries no force. While giving relief if by virtue of the subsequent service, the workman has gained anything, while the liability is determined, the salary so earned by the workman from the subsequent employment will have to be deducted.

3. It was also urged that the order of termination is void abinitio and therefore even if the workman has earned anything that cannot be taken into account. In this connection I have noted in my earlier judgment that the management having failed to observe the conditions as laid down under Section 25F of the I.D. Act, the termination is bad and therefore certain reliefs follow. Now the reliefs which were ordered to be given are that the workman would be entitled to certain wages. While doing so therefore the employee cannot be an employee at both the places as such it becomes necessary to deduct those wages which he has earned in the employment of the new employer.

4. It was also tried to be urged that in the light of my finding the reinstatement was a must and for that purpose my attention has been drawn to the rulings reported in 1981 (I), LLJ, page 386, 1981 (II), LLJ, page 700 and also the judgment reported in 45 F.L.R. page 280. However this argument is no longer open to the workman the reasons for not ordering reinstatement having been given by me and further by my subsequent order on application for review scope having been made limited, if the workman is not satisfied with these orders his remedy lies elsewhere and not in this Tribunal.

5. In the light of the evidence adduced while calculating the wages and the resultant responsibility on the Security Press, the wages earned by the workman shall be deducted. He has stated that after the termination of his service by order dated 18-9-1977 he remained unemployed for a period of two years. He further stated that from 25-5-1980 he was employed for a period of nine months on monthly salary of Rs. 200. Then he has stated that from February, 1981 he started getting Rs. 280 per month and that he continued to get the same till today. Barring the breaks of 3 days initially and 2 or 3 days in the subsequent period from 25-8-1980 the workman was employed and whatever he has earned shall have to be deducted while fixing the wages for the arrears of salary. In case any dispute would arise, that would be settled in a proceeding under Section 88C(2) of the Act. The Security Pres shall calculate the liability accordingly in the light of these observations and shall effect payment within a period of one month. The question of application under Section 33C(2) of the I.D. Act would only arise if the calculations so made by the Security press are not acceptable to the workman.

Award accordingly.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-42012 (53)/79-D. II (B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1982

का० आ० 312.—मैसर्स इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपार पश्चिम, बम्बई-86 (महा/1172), अपने पंजीकृत कार्यालय आक्सीजन हाउस पी०—34 तरातला रोड, कलकत्ता-700053 सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बद्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/344/82-पी०एफ-2]

New Delhi, the 26th November, 1982

S.O. 312.—Whereas Messrs Indian Oxygen Limited, Lal Bahadur Shastri Marg, Ghatkopar West, Bombay-86, (MH/1172), including its registered office at Oxygen House, P-34, Taratola Road, Calcutta-700053, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund

Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avaiable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/344/82-PF-II]

का० आ० 313—मैसर्स टाटा हाईड्रो-इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बम्बई हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई-23 (मेहा/9080) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, हो वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदे से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त

स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/345/82-पी० एफ-II]

S.O. 313.—Whereas Messrs The Tata Hydro-Electric Power Supply Company Limited, Bombay House, Homi-Mody Street Bombay-23, (MH/9080), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(345)/82-PF-II]

का० आ० 314—मैसर्स वेलकम ग्रुप सी-रॉक, लैण्ड्स इण्ड, बान्द्रा, बम्बई-50, (महाराष्ट्र-18236), (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही,

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त-अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन के भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा मे संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों मे कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस---35014/346/82--पी० एफ० -II]

S.O. 314.—Whereas Messrs Welcome Group Sea-Rock Lends End, Bandra, Bombay-50, (MH/18236), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the Employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avaiable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(346)/82-PF-II]

का० आ० 315.—मैसर्स ब्यैथ लेबोटरीज लिमिटेड, अपीजय हाउस दिनिशा वाचा रोड, पोस्ट बक्स नं० 11056, बम्बई 20 (महाराष्ट्र 6714) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले, सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधय की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदक के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदक देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो

यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/347/82-पी०एफ० II]

S.O. 315.—Whereas Messrs Wyeth Laboratories Limited, Apeejay House, Dinshaw Wacha Road, Post Box No. 11056, Bombay-20 (MH/6714), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra (Bambay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avaiable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(347)/82-PF-II]

का० आ० 316.—मसर्स वालचन्दनगर इण्डस्ट्रिज लिमिटेड (सिविल एण्ड ट्रामलाईन), डाकघर वालचन्दनगर, जिला पूना (महाराष्ट्र राज्य) (महाराष्ट्र/9922), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिअनुकूल हैं जो कर्मचारी - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों स्कीमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/350/82-पी० एफ०-I]

S.O. 316.—Whereas Messrs Walchandnagar Industries Limited (Civil and Tramline), Post Office Walchandnagar, District Pune, (Maharashtra State), (MH/9122), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval,

give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(350)/82-PF-II]

का० आ० 317.—मैसर्स वालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० एम० डिवीजन) पोस्ट आफिस वालचन्दनगर, जिला पूणे (महाराष्ट्र राज्य), (महाराष्ट्र/9125), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के, कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में, उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम कम से कम है जो कर्मचारी को उस वर्ष में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन से देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/351/82-पी० एफ०-II]

S.O. 317.—Whereas Messrs Walchandnagar Industries Limited (I.M. Division), Post Office Walchandnagar, District Pune, (Maharashtra State), (MH/9125), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(351)/82-PF-II]

का० आ० 318.—मैसर्स बालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (प्लास्टिक प्लान्ट) डाकघर बालचन्दनगर, जिला पूणे (महाराष्ट्र राज्य) (महाराष्ट्र/9127), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त

दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/352/82-पी० एफ०-II]

S.O. 318—Whereas Messrs Walchandnagar Industries Limited, (Plastic Plant), Post Office Walchandnagar, District Pune, (Maharashtra State), (MH/9127) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied to the Central Government under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No S-35014(352)/82-PF-II]

का० आ० 319- मैसर्स वालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (शुगर फेक्ट्री) पोस्ट आफिस, वालचन्दनगर, जिला पुणे (महाराष्ट्र/944), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/353/82-पी० एफ-II]

S.O. 319.—Whereas Messrs Walchandnagar Industries Limited, (*Sugar Factory*), *Post Office*, Walchandnagar, District Pune, (MH/944), (Maharashtra State), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund

Commissioner Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be brone by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(353)/82-PF II]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० 320—मैसर्स श्री वेंकटेसा मिल्स लिमिटेड, पिलानी रोड, वेंकटेसा मिल्स पोस्ट- 642128, उदमलपेट, (तमिलनाडु/51), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक 'प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन भूत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होती, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्यक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/400/82-पी० एफ०-II]

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 320.—Whereas Messrs Sri Venkatesa Mills Limited, Pilani Road, Venkatesa Mills Post-642128, Udamalpet, (TN/51), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits avaiable to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(400)/82-PF.II]

का० आ० 321.—मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट कमोडिटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०, 16, मालवीय नगर, भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश/3810), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम,

1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/381/82-पी० एफ०-II]

S.O. 321.—Whereas Messrs Madhya Pradesh State Commodities Trading Corporation Limited, 16, Malviya Nagar, Bhopal-462003, (MP/2810) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involve in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(381)/82-PF.II]

का० आ० 322—मैसर्स सुरेश मालपानी एण्ड कम्पनी, का० ओ० संगम मोटेज कम्पलैक्स, कुमारापत्तनम, जिला धारवाड़, (कर्नाटक/3967), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिकअनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/382/82-पी० एफ-II]

S.O. 322.—Whereas Messrs Suresh Malpani and Company, B.O. Sangam Motel Complex, Kumarapatnam. District Dharwad, (KN/3967) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member concerned under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(382)/82-PF.II]

का० आ० 323.—मैसर्स दि मिलिंग ट्रेडिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड, 3-दिनशा वाचा रोड, अपीजय हाऊस, चर्चगेट रिक्लेमेशन, बम्बई-20 (महाराष्ट्र/4422), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/390/82-पी० एफ०-II]

S.O. 323.—Whereas Messrs. The Milling Trading Company (Private) Limited, 3, Dinsha Vachha Road, Appeejay House, Churchgate Reclamation, Bombay-20 (MH/4422) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspecting, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salien features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member o the Employees' Provident Fund or the Provident Fund o an establishment exempted under the said Act, is employe in his establishment, the employer shall immediately enro him as a member of the Group Insurance Scheme and pa necessary premium in respect of him to the Life Insuranc Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefi available to the employees under the Group Insuran Scheme appropriately, if the benefits available to the er ployees under the said Scheme are enhanced, so that i benefits available under the Group Insurance Scheme more favourable to the employers than the benefits admissil under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Gro Insurance Scheme, if on the death of an employee amount payable under this scheme be less than the amo that would be payable had employee been covered un the said Scheme, the employer shall pay the difference the legal heir/nominee of the employee as compensatior

8. No amendment of the provisions of the Group I rance Scheme shall be made without the prior approva the Regional Provident Fund Commissioner, Maharas and where any amendment is likely to affect adversely

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(390)/82-PF. II]

का०आ० 324—मैसर्स आटोलेक इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, अम्बात्तूर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास-58 तमिलनाडु /5647) (जिसे इसमें पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा, तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी , होंगे वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का, या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसी स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों । जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमा कृत रकमों का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/391/82-पी० एफ०-II]

S.O. 324.—Whereas Messrs Autolec Industries (Private) Limited, Ambattur Industrial Estate, Madras-58. (TN/5647) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and where amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(391)/82-PF. II]

का० आ० 325—मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, मशीन टूल्स डिवीजन, रजिस्टर्ड आफिस 36, कब्बिघम रोड, बंगलौर-52, (कर्नाटक/873), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों को नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा मे संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किस सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/392/82 पी० एफ० II]

S.O. 325.—Whereas Messrs Hindustan Machine Tools Limited, Machine Tools Division, Registered Office 36, Cunningham Road, Bangalore-52 (KN/873) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and where amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(392)/82-PF. II]

का० आ० 326.—मैसर्स सिवानन्धा स्टील्स लिमिटेड, प्लाट सं० 18, 19, 20, इंडस्ट्रियल एस्टेट, अम्बात्तूर, मद्रास-58, (तमिलनाडु/6361) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा/ में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/393/82-पी० एफ०-II]

ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 326.—Whereas Messrs Sivanandha Steels Limited, Plot Nos. 18, 19, 20, Industrial Estate, Ambattur, Madras-58 (TN/6361) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(393)/82-PF. II]

का० आ० 327—मैसर्स एच० एम० एम० लिमिटेड, 26 मेन रोड विल्सन गार्डन्स, बंगलौर, (कर्नाटक/6666), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम स्थिर करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/394/82-पी० एफ०-II]

S.O. 327.—Whereas Messrs H.M.M. Limited, 26th Main Road, Wilson Gardens, Bangalore, (KN/6666) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity of the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption is liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(394)/82-PF. II]

का० आ० 328.—मैसर्स सनद्विक एशिया लिमिटेड, बम्बई-पूना रोड, पूना-411012 (महाराष्ट्र/5949) तथा इसकी बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता, नई दिल्ली और मद्रास स्थित शाखाएं जो कि इसी कोड नम्बर के अन्तर्गत आती हैं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/251/82-पी०एफ-II]

S.O. 328.—Whereas Messrs Sandvik Asia Limited, Bombay-Poona Road, Poona-411012 including its branches at Bombay, Bangalore, Calcutta, New Delhi and Madras which are centrally covered under Code No. MH/5949 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(251)/82-PF. II]

का० आ० 329—मैसर्स श्रीराम फर्टीलाईजर्स एण्ड केमिकल्स कंचेनजंगा, बिल्डिंग, 18, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली 1, (दिल्ली/5819) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप-सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारियों के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उसके नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/386/82/पी०एफ० II]

S.O. 329.—Whereas Messrs Shriram Fertilisers and Chemicals, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi-1, (DL/5819) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life

Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(386)/82-PF. II]

का० आ० 330.—मैसर्स मेडल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, 225-एफ, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-20 (पश्चिम बंगाल/12526), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, रेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/396/82-पी० एफ-II]

S.O. 330.—Whereas Messrs Metal Scrap Trade Corporation Limited, 225-F, Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta-20 (WB/12526) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014(396)82-PF.II]

का०आ० 331.—मैसर्स अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, प्लाट नं० 5, सिपकोट इण्डस्ट्रियल कम्पलेक्स रानीपेट-632403 (तमिल नाडु), (तमिल नाडु/10118), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अंशदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं को रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एफ-35014/395/82-पी०एफ०-II]

S.O. 331.—Whereas Messrs Appollo Tubes Limited Plot No. 5, Sipcot Industrial Complex, Ranipet-632403 (Tamil Nadu), (TN/10118) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(395)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1982

का. आ. 332.—मैसर्स इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड, तुमकूर रोड, डाकघर यशवन्तपुर, बंगलौर-560022 (कर्नाटक/868), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक (बंगलौर) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक (बंगलौर) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, जो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/421/82-पी. एफ.-II]

S.O. 332.—Whereas Messrs Indian Oxygen Limited, Tumkur Road, Post Office Yeshwanthpur, Bangalore-560022 (KN/868) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka (Bangalore), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable undr this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka (Bangalore) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(421)/82-PF. II]

का. आ. 333.—मैसर्स कोठारी फाइटोकैमिकल्स (इन्टर-नेशनल), नं. 766, अन्ना नगर, मदुराई-625020, (तमिल नाडु 10578), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्तस्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, जो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/420/82-पी. एफ.-2]

S.O 333.—Whereas Messrs Kothari Phytochemicals (International) No. 766, Anna Nagar, Madurai-625020, (TN/10578) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said estabilshment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madras, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable the opportunity to the employees to expplain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(420)/82-PF.II]

का. आ. 334.—मैसर्स बुक्को उल्फ नई इण्डिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, पिम्परी, पिम्परी-पूणे-411018, (महाराष्ट्र/1887), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/409/82-पी एफ -2]

S.O. 334.—Whereas Messrs Buckau Wolf new India Engineering Works Limited, Pimpri-Pune-411018 (MH/1887) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Cetral Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and suubject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said estabilshment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as when amended, alongwith a transaction of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees, then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had emnployee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014(409)/82 PF II]

का. आ. 335.—मैसर्स थेरमैक्स (इण्डिया) (प्राइवेट), लिमिटेड, डी-13, एम आई डी सी इण्डस्ट्रियल एरिया, चिन्चवाड़, पूणे-19 (महाराष्ट्र/1599), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/300/82-पी. एफ.-2]

S.O. 335.—Whereas Messrs Thermax (India) (Private) Limited, D-13, M.I.D.C. Industrial Area, Chinchwad, Poona-19 (MH/1509)

(hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(330)/82-PF.II]

का. आ. 336—मैसर्स के. एम. बी. पम्प लिमिटेड, (फाउण्ड्री डिविजन) पोस्ट वाम्बोरी, तालुक राहुरी, जिला अहमदाबाद (बम्बई), (महाराष्ट्र/15920), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/399/82-पी. एफ.-2]

S.O. 336.—Whereas Messrs K.S.B. Pump Limited, (Foundary Division) Post Vambori, Taluka-Rahuri, District Ahmednagar (Bombay), (MH/15920) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estblishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits availabe to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less then the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014(399)/82-PF.II]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1982

का. आ. 337.—भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1982 के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2) के पृष्ठ 57 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 23 (अ) दिनांक 16 जनवरी, 1982 की पंक्ति 8 में "अटकोली" के स्थान पर "अठोली" पढ़िए ।

[संख्या एस-38013/35/81-एच. आई.]

ए. के भट्टराई, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd December, 1982

S.O. 337.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 23 (E), dated the 16th January, 1982 published in the Gazettee of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16th January, 1982 at page 58 in line 9 for "Atcholi" read Atholi".

[No. S. 38013/35/81-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

का० आ० 338.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का नाम निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1982 हैं ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा . इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदो के जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ है जो उनके अधिनियम में है ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :— एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :— अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :— बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :— (1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा । (ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन मे किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम-से-कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गई है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जाएगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक-तिहाई या चार की इनमें से जो अधिक हो, होगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन—यदि बोर्ड का अधिवेशन गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन, अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो उसी समय, और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :- (1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निदिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा लेखबद्ध किये हो, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख, को पारित किया गया माना जाएगा जिस तारीख, को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किए हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किए गए सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जाएगा।

11. कारबार के अभिलेख :-(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति अध्यक्ष अथवा निदेशक जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाए तो इस प्रकार किए गए कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनसे अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं० एफ० 12-5/81-आर० आर० बी० (1)]

दिनेश चंद्र निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

S.O. 338.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Nimar Kashetriya Gramin Bank (Meeting of Board) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Nimar Kashetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) . The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director

7 Special meeting of the Board :

(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned, for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation :

(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitutes quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors

(5) All decisions in a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.

(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/81-RRB(I)]

DINESH CHANDRA, Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983